आर्थिक समीक्षा
Economic Review
1994-95

राजस्थान सरकार
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

25515

आर्थिक समीक्षा
Economic Review
1994-95

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, राजस्थान, जयपुर
DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS, YOJANA BHAVAN, RAJ., JAIPUR

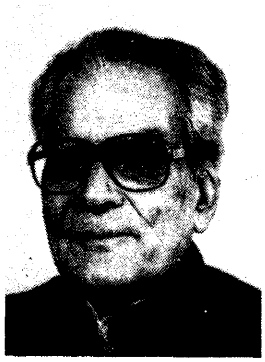

प्रस्तावना

आर्थिक समीक्षा बजट से सम्बन्धित प्रलेख है, जो कि परम्परागत रूप से, गत वर्षों में "आय व्ययक अध्ययन" नामक प्रकाशन में सम्मिलित की जाती थी। इस वर्ष "आर्थिक-समीक्षा 1994-95" पृथक से एवं बजट से पूर्व प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रकाशन में, राजकीय विभागों के कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों का तुलनात्मक विवरण दिया गया है, जो राज्य की अर्थ व्यवस्था के वृहद परिदृश्य को परिलक्षित करता है।

आशा करता हूँ कि यह प्रकाशन जनप्रतिनिधियों, राजकीय विभागों, विभिन्न संस्थाओं, शिक्षाविदों एवं राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी होगा।

(भैरों सिंह शेखावत)
मुख्य मंत्री

Foreword

The Economic Review is Budget related document which has traditionally been incorporated in the publication entitled "Budget Study" in the past. This year, the "Economic Review - 1994-95" is being presented separately and in advance of the Budget. While depicting the macro level view of economy of the State, it seeks to depict the activities and programmes of various Departments in a dynamic and comparative framework.

I hope that the publication will prove useful to public representatives, Government Departments, various organisations and academicians and who are interested in the major issues and analysis of the socio-economic development of the State.

(Bhairon Singh Shekhawat)
Chief Minister

भूमिका

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान द्वारा " आर्थिक समीक्षा", 1994-95 का प्रकाशन किया जा रहा है। यह प्रथम प्रकाशन है जो कि पूर्व में "आय-व्ययक अध्ययन" में सम्मिलित किया जाता रहा है। इस प्रकाशन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण गतिविधियों की प्रगति, मानचित्रों एवं रेखा चित्रों सहित आर्थिक विकास के मुख्य सूचकांक एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य दिया गया है।

मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होने इस प्रकाशन को समय पर निकालने में अपना सहयोग दिया।

आशा करता हूँ कि यह प्रकाशन पाठकों के लिए उपयोगी होने के साथ-साथ शोध कर्ताओं एवं राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ी संस्थाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

(एम. के. खन्ना)
शासन सचिव,
आयोजना विभाग, राजस्थान।

INTRODUCTION

Directorate of Economics and Statistics, Rajasthan is bringing out a Publication entitled "Economic Review", 1994-95. It is the first publication which in the past, has been a part of the "Budget Study". Macro level overview of economy of the State, important indicators of Economic Growth along with charts and graphs and the progress of important activities of various departments under the State Govemment have been given in the publication.

I am grateful to all those who have made efforts in bringing out this publication in time.

I hope this publication will be useful for the readers and assist the research scholars and the institutions engaged in the work of Socio-economic developments of the State.

(M. K. KHANNA)
Secretary to Govt.,
Planning Department, Rajasthan.

विषय सूची
CONTENTS

पृष्ठ
Page

I. आर्थिक समीक्षा 1994-95

- आर्थिक विकास के मुख्य सूचक 1

1. सामान्य पुनरावलोकन 3
   - वृहद आर्थिक परिदृश्य

2. राज्य घरेलू उत्पाद एवं वित्त 8

   2.1 राज्य घरेलू उत्पाद
   2.2 अष्टम् पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 1994-95
   2.3 बैंकिंग

3. मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली 14

   3.1 थोक मूल्य सूचकांक
   3.2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
   3.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4. उद्योग एवं खनिज 17

   4.1 उद्योग
   4.2 खादी एवं ग्रामोद्योग
   4.3 कारखाना एवं बायलॅर्स
   4.4 खनिज
   4.5 श्रम
   4.6 रोज़गार

5. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र 23

   5.1 मानसून
   5.2 कृषि उत्पादन
   5.3 कृषि विस्तार एवं आदान प्रबन्धन
   5.4 सिंचाई
   5.5 पशु पालन
   5.6 दुग्ध विकास
   5.7 भेड़ पालन
   5.8 मत्स्य पालन
   5.9 वन
   5.10 वन्य जीव संरक्षण

पृष्ठ
Page

6. आधारभूत ढांचागत विकास 30

6.1 विद्युत
6.2 गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत-रेडा
6.3 परिवहन एवं संचार
- सड़क
- सड़क परिवहन

7. सामाजिक आधारभूत विकास 35

7.1 मानव संसाधन विकास
7.2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
7.3 परिवार कल्याण
7.4 जल-आपूर्ति
7.5 आवास
7.6 पिछड़ी जातियों का कल्याण एवं समाज कल्याण
- अनुसूचित जाति कल्याण
- अनुसूचित जनजाति कल्याण
- महिला एवं बाल कल्याण

8. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज 40

9. अन्य कार्यक्रम 42

9.1 बीस सूत्री कार्यक्रम
9.2 अकाल एवं सहायता
9.3 अल्प बचत

10. राज्य में आरम्भ किये गये आर्थिक एवं वित्तीय सुधार 45

10.1 उद्योग एवं राजकीय उपक्रम
10.2 कर सुधार
10.3 उर्जा क्षेत्र
10.4 अन्य

II. आर्थिक स्थिति की तालिकाएँ
TABLES OF ECONOMIC SITUATION

1. राजस्थान की राज्य आय औद्योगिक उद्भव प्रचलित कीमतों पर एवं प्रतिशत विभाजन 49
State Income of Rajasthan by industrial origin at current prices and percentage distribution

पृष्ठ
Page

2. राजस्थान की राज्य आय औद्योगिक उद्भव स्थिर (1980-81) कीमतों पर एवं प्रतिशत विभाजन 51
State income of Rajasthan by industrial origin at constant (1980-81) prices and percentage distribution

3. राजस्थान में कृषि उत्पादन का सूचकांक 53
Index Numbers of Agricultural Production in Rajasthan

4. औद्योगिक उत्पादन 56
Industrial Production

5. राजस्थान के थोक भाव सूचकांक 58
Indices of Wholesale Prices in Rajasthan

6. उपभोक्ता भाव सूचकांक 60
Indices of Consumer Price

7. राजस्थान में अकाल/अभाव स्थिति से हुई क्षति 62
Loss due to Famine/Scarcity condition in Rajasthan

8. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक 63
Statewise Important Economic Indicators

III. ECONOMIC REVIEW

- Key Indicators of Economic Development 68

1. General Review 71

- Macro Economic Overview

2. State Domestic Product and Finance 80

2.1 State Domestic Product
2.2 Eighth Five Year Plan and Annual Plan 1994-95
2.3 Banking

		पृष्ठ Page
3.	Prices and Public Distribution System	88
	3.1 Wholesale Price Index Numbers	
	3.2 Consumer Price Index Numbers	
	3.3 Public Distribution System	
4.	Industries and Mines	92
	4.1 Industries	
	4.2 Khadi and Village Industries	
	4.3 Factories and Boilers	
	4.4 Minerals	
	4.5 Labour	
	4.6 Employment	
5.	Agriculture and Allied Sectors	100
	5.1 Monsoon	
	5.2 Agriculture Production	
	5.3 Agriculture Extension and Input Management	
	5.4 Irrigation	
	5.5 Animal Husbandry	
	5.6 Dairy Development	
	5.7 Sheep Husbandry	
	5.8 Fisheries	
	5.9 Forestry	
	5.10 Preservation of Wild Life	
6.	Basic Infrastructural Development	110
	6.1 Power	
	6.2 Non-Conventional Sources of Energy - REDA	
	6.3 Transport and Communication	
	- Roads	
	- Road Transport	
7.	Social Infrastructural Development	116
	7.1 Human Resource Development	
	7.2 Medical and Health	
	7.3 Family Welfare	

पृष्ठ
Page

7.4 Water Supply
7.5 Housing
7.6 Welfare of Backward Classes and Social Welfare
- Welfare of Scheduled Castes
- Welfare of Scheduled Tribes
- Welfare of Women and Children

8. Rural Development and Panchayati Raj 124

9. Other Programmes 127

9.1 Twenty Point Programmes
9.2 Famine and Relief
9.3 Small Savings

10. Economic and Financial Reforms initiated in the State 130

10.1 Industry and State Enterprises
10.2 Tax Reforms
10.3 Power Sector
10.4 Others

*****

आर्थिक समीक्षा

1994-95

आर्थिक विकास के मुख्य सूचक

विवरण	इकाई	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95@
1	2	3	4	5	6
1. सकल घरेलू उत्पाद	करोड़ रूपये				
(a) प्रचलित कीमतों पर		22986	26458	28015	
(b) स्थिर कीमतों (1980-81) पर		8939	9906	9344	10793
*2.अग्रिम अनुमानों के आधार पर आर्थिक वृद्धि दर	प्रतिशत				
(a) प्रचलित कीमतों पर		10.99	15.10	5.88	
(b) स्थिर कीमतों (1980-81) पर		(-)5.58	10.82	(-)5.67	15.51
3. सकल घरेलू उत्पाद से वृद्द क्षेत्र का प्रतिशत स्थिर कीमतों (1980-81) पर	प्रतिशत				
(अ) प्राथमिक		43.05	45.57	40.51	44.79
(ब) द्वितीय		21.97	20.69	23.19	21.37
(स) अन्य सेवायें (तृतीयक)		34.98	33.74	36.30	33.84
4. कृषि उत्पाद सूचकांक (आधार 1979-82 =100)	सूचकांक	182.33	216.67	156.38	अप्राप्त
5. कुल खाद्यान उत्पादन	लाख टन	79.81	114.79	70.45	105.37
6. औद्योगिक विनिर्माण उत्पाद सूचकांक (आधार 1970=100)	सूचकांक	272.71	269.17	335.19	निर्माणाधीन
+7. समान्य थोकभाव सूचकांक (आधार 1952-53 =100)	सूचकांक				
(अ)सूचकांक		1467.8	1622.7	1668.7	1827.61
(ब)प्रतिशत वृद्धि		24.17	10.55	2.83	9.52
+8. औद्योगिक क्षमिकों के लिये सामान्य उपभोका सूचकांक (आधार 1982=100)	सूचकांक				
(a) जयपुर केन्द्र		210	228	245	269
(b) अजमेर केन्द्र		217	243	253	280
9. विद्युत उत्पादन (उत्पादन+क्रय)	मि.यूनिट	12979.59	14666.50	15374.86	15329.15
-प्रतिशत वृद्धि		16.47	13.00	4.83	(-)0.30
#10. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक साख	करोड़ रू.	3141.61	3507.37	3912.41	4210.48
-प्रतिशत वृद्धि		13.22	11.64	11.55	7.62

@ वर्ष 1994-95 की सूचना प्रावधानिक है।

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष से वृद्धि दर्शाती है।

+ थोक भाव सूचकांक/उपभोका सूचकांक कैलेन्डर वर्ष 1991, 1992,1993 व 1994 के लिये।

समंक सितम्बर 1991,1992,1993 व 1994 के लिये।

चयनित मुख्य सूचक

सकल घरेलू उत्पाद

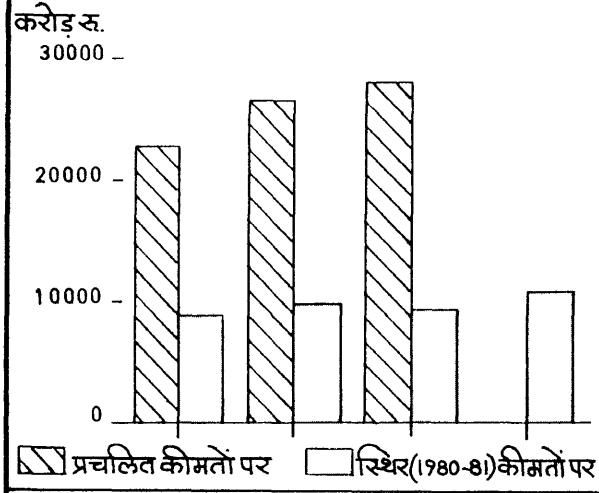

विद्युत उत्पादन (उत्पादन एवं क्रय)

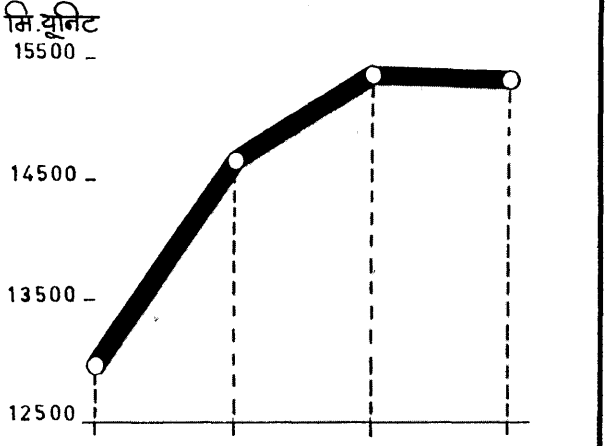

सकल घरेलू उत्पाद में वृहद् क्षेत्रों का प्रतिशत

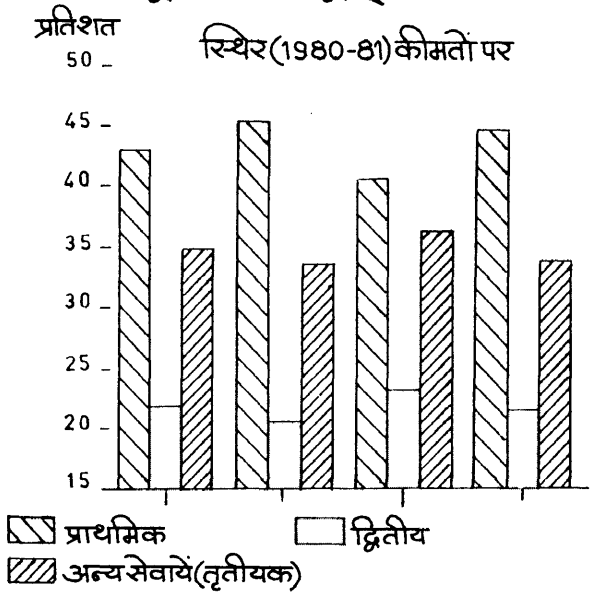

सामान्य थोकभाव सूचकांक

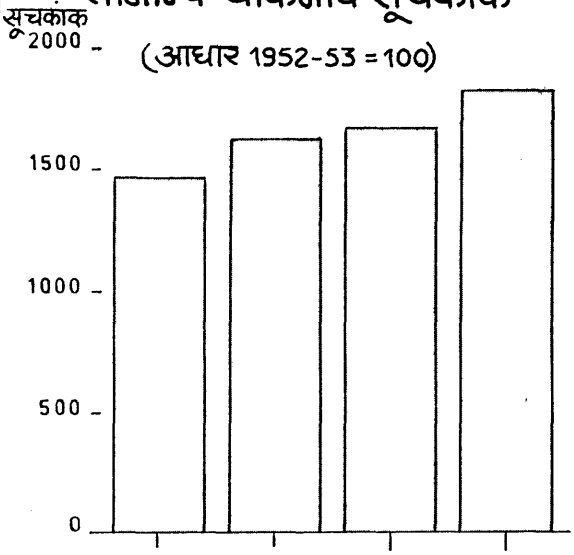

कुल खाद्यान्न उत्पादन

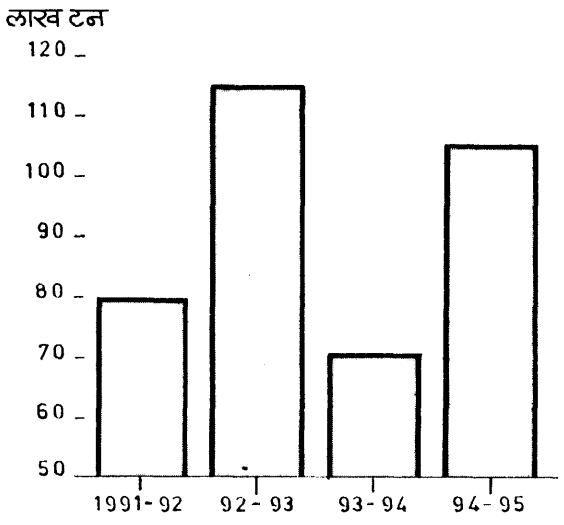

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सारव

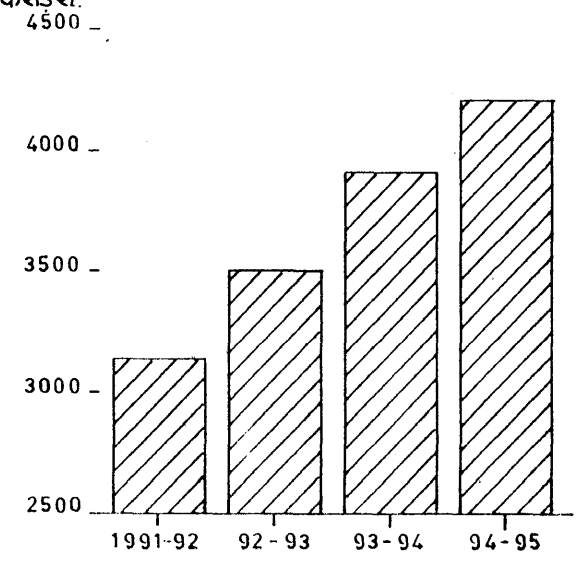

1. सामान्य पुनरावलोकन 1994-95

वृहद आर्थिक परिदृश्य

राजस्थान राज्य 3.42 लाख वर्ग कि०मी० क्षेत्र में फैला देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जिसकी 1040 कि०मी० लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएँ पाकिस्तान के साथ लगी है तथा राज्य की सीमाएँ पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात राज्य से भी जुड़ी हुई है। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान 31 ज़िलों में बंटा हुआ है, तथा ये ज़िले पुनः 213 तहसीलों एवं 237 पंचायत समितियों में विभक्त है।

राजस्थान राज्य की प्रमुख विशेषताएँ निम्न सारणी में दर्शाई गई है:

	मद	वर्ष	इकाई	विवरण
1-	क्षेत्रफल	1991	लाख वर्ग कि०मी०	3.42
2-	ज़िले	1994	संख्या	31
3-	उपखण्ड	1991	संख्या	90
4-	तहसीलें	1991	" "	213
5-	जिला परिषदें	1994	" "	31
6-	पंचायत समितियाँ	1991	" "	237
7-	ग्राम पंचायतें	1994	" "	9173
8-	कुल गाँव	1991	" "	39810
9-	कुल आबाद गाँव	1991	" "	37889
10-	कुल कस्बे	1991	" "	222

राजस्थान की स्थलाकृति में विश्व की सबसे पुरानी पर्वत माला अरावली पहाड़ियों की प्रमुखता है। अरावली पहाड़ियाँ राज्य के मुख्य भाग से होती हुई 692 कि०मी० तक फैली हुई है। 11 ज़िलों एवं राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60 प्रतिशत पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भारत का महा रेगिस्तान "थार" कहलाता है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 4.40 करोड़ है। (अक्टूबर 1994 को राज्य की अनुमानित जनसंख्या 4.81 करोड़ है।)

राजस्थान की जनसंख्या के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार है:

1- जम्मू कश्मीर एवं उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर वर्ष 1981-91 में अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है।

2- वर्ष 1991 में राजस्थान मे प्रति 1000 पुरुषों पर 913 महिलाओं की संख्या अखिल भारतीय स्त्री पुरुष अनुपात 929 से कम है।

3- राज्यों मे बिहार को छोड़ कर वर्ष 1991 मे राज्य की साक्षरता दर 38.55 प्रतिशत सबसे कम है।

4- राजस्थान में महिला साक्षरता केवल 20.44 प्रतिशत हैं जो देश में सबसे कम है। अखिल भारतीय महिला साक्षरता का प्रतिशत 39.29 प्रतिशत है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या घनत्व 129 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है, तथा ज़िलेवार जनसंख्या घनत्व में काफ़ी असमानताएँ हैं। राज्य की जलवायु सामान्यतया शुष्क रहती है। राज्य में वर्षा की कमी ही नहीं बल्कि उसमें वर्ष दर वर्ष और कमी के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देश के 17 प्रमुख राज्यों में राजस्थान का दसवाँ स्थान है, जिसका कारण विरासत में मिला कमज़ोर आर्थिक आधार है। राज्य अपने सीमित साधनों को जुटाने की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है।

राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अर्थ व्यवस्था मे कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कुल राज्य आय का लगभग आधा भाग कृषि एवं उससे सम्बद्ध कार्यकलापों से उपलब्ध होता है। कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई अति आवश्यक है। राज्य में सतही जल स्रोतों की कमी है । वर्षा के अभाव एवं विषमता के कारण भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है, अतः कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने पर निरंतर बल दिया जा रहा है। वर्ष 1950-51 के 33.80 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन कि तुलना में वर्ष 1994-95 में 105.37 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। वर्ष 1951-52 से शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 1994 में राज्य में संतोषजनक वर्षा हुई, जिससे वर्ष 1994-95 मे अधिक मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन की आशा है। वर्ष 1994-95 में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 49.57 प्रतिशत अधिक खाद्यान्न उत्पादन संभावित है। वर्ष 1994-95 मे 18.20 लाख टन दालो के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जो कि पिछले वर्ष से 70.25 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1991-92 के 27.11 लाख टन रिकार्ड उत्पादन को पार कर वर्ष 1994-95 में तिलहन का उत्पादन 32.69 लाख टन होने की संभावना है।

देश के 10.4 प्रतिशत भू भाग में फैले इस राज्य में केवल 1.04 प्रतिशत सतही जल उपलब्ध है तथा इस दृष्टि से राजस्थान के लिए जल एक जटिल संसाधन है। कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में जल बचत के साधन अपना कर जल के सजग उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है। सरकार की दूसरी नीति अपने हिस्से के अन्तर्राज्यीय जल के समुचित उपयोग की है। इस दिशा में सम्बंधित राज्यों के साथ "यमुना जल बंटवारा" एक ऐतिहासिक समझौता है, जिसके फलस्वरूप राज्य के पूर्वी भाग में 111.9 करोड़ घन मीटर जल उपलब्ध हो सकेगा।

हाल ही में राज्य सरकार ने एक विस्तृत औद्योगिक नीति तैयार की है, जो राज्य में अधिक विनियोजन के अवसर जुटाने में सहायक होगी। इस औद्योगिक नीति से नए उद्योगों को प्रोत्साहन एवं रियायतें उपलब्ध होगी।

औद्योगिक नीति 1994 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा नियमों एवं कार्य विधि में सुधार एवं सरलीकरण, त्वरित आदानों को सुनिश्चित करने, आधारभूत ढाँचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, रोज़गारोंमुखी एवं ग्रामीण उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन देने जैसे अनेक उपाय किए गए है।

राज्य सरकार के सुधारवादी एवं नवीनतम उपायों के कारण राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में आशातीत परिवर्तन आया है। पूर्व वर्षों की तुलना में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के साथ उसमें विविधताएं आई हैं।

इस समय राज्य सिंथेटिक यार्न , सीमेंट, टी०वी० पिक्चर ट्यूब्स, रसायन एवं खाद यहाँ तक विभिन्न प्रकार की इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं आदि का बड़ा उत्पादक है।

खान एवं खनिज क्षेत्र में राजस्थान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिन खनिजों की बहुलता के कारण राज्य भूगर्भीय रूप से सम्पन्न है तथा जिन महत्वपूर्ण खनिजों से राज्य का नाम बहुलता के साथ जुड़ा है, उनमें अलौह धातु (शीशा, जस्ता एवं ताम्बा) तथा लौह धातु जैसे टंगस्टन एवं अनेक औद्योगिक खनिज सम्मिलित है।

लघु खनिज विशेषतः सजावटी पत्थर जैसे मार्बल , कोटा स्टोन, सैंड स्टोन आदि के क्षेत्र में राजस्थान का एक विशेष स्थान है तथा देश के कुल लघु खनिज उत्पादन मूल्य में राजस्थान का लगभग 30 प्रतिशत योगदान है।

राज्य में खनिज विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए है। पिछले चार दशकों में बहुत से नए खनिज भण्डारों की खोज की गई है। वर्तमान में राज्य में लगभग 42 वृहद तथा 23 लघु खनिजों का दोहन किया जा रहा है।

प्रतिस्पर्धात्मक एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित खुले बाज़ार की अर्थ व्यवस्था की ओर झुकाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने खनिज नीति 1994 की घोषणा की है, जो की मुख्यतः जनजाति एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक द्वारा राज्य की खनिज सम्पदा के शीघ्र दोहन में सहायक होगी। नई खनिज नीति के अन्तर्गत खनन क्षेत्र में मुख्यतः अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए नियोजन के अवसरों में वृद्धि होगी।

राज्य का खनिज एवं भू विज्ञान विभाग तथा राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम खनिज स्रोतों के त्वरित एवं वैज्ञानिक तरीक़ों से दोहन के लिए कार्य कर रहे है। उत्पादन से सम्बंधित सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा एक आवश्यक आदान है। अतः राज्य योजनाओं में ऊर्जा विकास को सदैव प्राथमिकता दी गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल योजना प्रावधान का लगभग 28.31 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। फ़रवरी 1995 तक 30654 गाँवों का विद्युतीकरण तथा 4.78 लाख कुओं को ऊर्जाकृत किया जा चुका है।

राज्य के त्वरित आर्थिक विकास हेतु यातायात एवं संचार साधनों का विकसित होना परम आवश्यक है। यातायात एवं संचार की दृष्टि से राजस्थान एक अर्ध-विकसित राज्य है। जल मार्गों के न होने एवं रेल प्रणाली के अपर्याप्त विस्तार के कारण सड़कें ही राज्य में आवागमन का प्रमुख साधन हैं।

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रथम सड़क नीति का अनुमोदन किया गया है। सड़क नीति के अनुसार संस्थाओं / व्यक्तिगत ठेकेदारों से ठेके पर सड़कों का निर्माण कराया जा सकेगा जिससे सड़कों का तीव्र विकास होगा, और राज्य के आधार भूत ढाँचे को विकसित करने में मदद मिलेगी।

राज्य में अनेक स्थानों पर छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के वर्तमान में चल रहे कार्यों, तथा प्रस्तावित भावी कार्यक्रमों में तत्परता से अग्रसर है। यह आशा कि जाती है कि वर्ष 1995-96 के अन्त में कुल 2000 कि०मी० विद्यमान छोटी रेलवे लाइन (मीटर गेज) को बड़ी लाइन (ब्रोड गेज) में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिससे राज्य के उद्योग एवं खनिज विकास के लिए बहुत बड़ी सुविधा सुलभ हो सकेगी। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर बड़ी रेलवे लाइन से बंबई, दिल्ली और कलकत्ता से जुड़ चुका है। इसके अतिरिक्त जोधपुर एवं बीकानेर नगर भी बड़ी रेलवे लाइन से जुड़ गए है।

विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन का राज्य की अर्थव्यवस्था एवं जनजीवन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। निश्चित अंतराल में थोक एवं फुटकर मूल्य स्तर में परिवर्तन थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से परिलक्षित होता है। राज्य में वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में थोक एवं फुटकर मूल्य दोनों में ही वृद्धि का रुख देखा गया। राष्ट्रीय स्तर पर भी वर्ष 1994 में मूल्य स्तर में बढोत्तरी का रुख रहा।

राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुसरण में, राज्य के विकास की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य - राज्य का तीव्र विकास, अधिकतम रोज़गार अवसरों का सृजन, क्षेत्रीय असमानताओं एवं ग़रीबी उन्मूलन, मूल न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता एवं बड़े पैमाने पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना आदि है।

राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 11500 करोड़ रुपये का है, जो की सातवीं पंचवर्षीय योजना से 283 प्रतिशत अधिक है। यह उदव्यय गुजरात राज्य के लगभग बराबर तथा पंजाब उड़ीसा, मध्यप्रदेश एवं तमिलनाडु से अधिक है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति योजना उदव्यय सातवीं योजना के 875 रुपये से बढ़कर 2613.64 रुपये हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति विनियोजन आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं तमिलनाडु आदि राज्यों से अधिक है।

राज्य की 1993-94 की वार्षिक योजना 1700 करोड़ रुपये की थी एवं वर्ष 1994-95 की योजना हेतु 2450 करोड़ रुपये रखे गए है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 1994-95 की योजना का उद्व्यय 44.12 प्रतिशत अधिक है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है की योजना आयोग, भारत सरकार ने राज्य के संसाधनों से राजस्व जुटाने में किए गए प्रयासों एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की सराहना की है।

बैंकों द्वारा ऋण वितरण, निवेश एवं विकास हेतु महत्वपूर्ण संसाधन है। एन.आर.वाई., पी.एम.आर.वाई, आई.आर.डी.पी., एवं अनुसूचित जाति विकास निगम आदि के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बैंकों का सक्रिय योगदान है। बैंक शाखाओं के विस्तार विशेषतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विस्तार से ग़रीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कमज़ोर वर्गों को ऊपर उठाने के राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं विभिन्न ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में विशेष मदद मिली है।

बैंक जनसंख्या अनुपात (1991 की जनगणना के अनुसार) से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में सितम्बर 1994 को प्रति 13970 की आबादी पर एक बैंक तथा क्षेत्रफल के आधार पर 109 वर्ग कि०मी० में एक बैंक शाखा कार्यरत थी।

निश्चित समयावधि मे राज्य आय एवं प्रति व्यक्ति आय अर्थ व्यवस्था की सम्पूर्ण स्थिति को दर्शाती है। राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि अधिकांशतः कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है, क्योंकि कृषि उत्पादन राज्य घरेलू उत्पादन का सबसे बड़ा अंशदायी है, तथा इसका दूसरे क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः राज्य आय में मानसून के उतार चढ़ाव की स्थिति के कारण काफ़ी परिवर्तन आते है। अग्रिम अनुमानो के आधार पर (स्थिर 1980-81) के कीमतों पर वर्ष 1994-95 का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 9576 करोड़ रुपये आँका गया है, जबकि वर्ष 93-94 में यह 8187 करोड़ रुपये था। इस प्रकार पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 1994-95 में शुद्ध घरेलू उत्पाद में 16.97 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

वर्ष 1993-94 में 1760 रुपये की तुलना में वर्ष 1994-95 में स्थिर (1980-81) मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2016 रुपये अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

राज्य में शैक्षिक विकास हेतु अनवरत प्रयास किए जा रहे है। महिला शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के साथ शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार व प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण पर वर्ष 1994-95

में अधिक बल दिया गया। राज्य में महाविद्यालय स्तर तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।

वर्ष 1990-91 में प्रारम्भ किया गया सम्पूर्ण साक्षरता अभियान वर्ष 1994-95 में भी चालू रहा, जिसके तहत अजमेर तथा डूंगरपुर ज़िले पूर्व में ही सम्पूर्ण साक्षर घोषित किए जा चुके है।

सन् 2000 ई. तक सबके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य रक्षा स्कीम के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य में विशेष प्रयास किए जा रहे है, फलस्वरूप राज्य की जनता के स्वास्थ्य में सुधार आया है।

राज्य में चेचक व अन्य महामारियों एवं छूत की बीमारियों पर काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। सीमित परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राज्य में सघन परिवार कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

राज्य के शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे है। 1991 की जनगणना के अनुसार दिसम्बर, 1994 तक राज्य के कुल 37889 आबाद गाँवो में से 36629 गाँवों में स्वच्छ पेय जल सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है। ग़रीबी, अपर्याप्त रोज़गार के अवसर एवं मूलभूत सुविधाओं की कमी आदि ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी समस्याएँ है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं पंचायत समितियों के माध्यम से संचालित आई०आर०डी०पी०, जे०आर०वाई०, डी०डी०पी०, डी०पी०ऐ०पी० जैसे अनेक कार्यक्रमों से मूलभूत सुविधाओं का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों में ग़रीबी मिटाने तथा अतिरिक्त रोज़गार के अवसर जुटाने हेतु प्रयास किए जा रहे है। सर्वांगीण ग्रामीण विकास हेतु वर्ष 1994-95 में टी०ए०डी०, अपना गाँव अपना काम, तीस ज़िले तीस काम एवं ढाकरा आदि विभिन्न कार्यक्रम भी राज्य में चलाए जा रहे है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राज्य के ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध करवाई जा रही है। जनवरी, 1995 के अंत में कुल 16798 उचित मूल्य की दुकानें राज्य में कार्यरत थी।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत राज्य में उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण अदालतें कार्यरत है।

*****

2. राज्य घरेलू उत्पाद एवं वित्त

2.1 राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान राज्य के आर्थिक विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक है।

प्रति व्यक्ति आय, राज्य की अर्थ व्यवस्था को वास्तविक एवं तुलनात्मक रूप से मापने हेतु काम में ली जाती है। इसको क्षेत्रीय विषमताओं को मापने का भी एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। इसका उपयोग योजना कारों जैसे योजना आयोग एवं वित्त आयोग द्वारा योजनाओं के श्रोतों एवं करों को विभिन्न राज्यों में बाँटनें के लिए भी किया जाता है।

प्रचलित एवं स्थिर क़ीमतों (1980-81) पर राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्तमान विश्लेषण में सम्मिलित है। वर्ष 1994-95 के आय अनुमान अग्रिम एवं सम्भावित हैं, जो कि अर्थ व्यवस्था के अनुभागों में संभावित उत्पादन एवं प्रवृत्ति पर आधारित हैं। अतः इनका उपयोग पूर्ण सावधानी से किया जाना चाहिए।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

एक निश्चित समय में राज्य की समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य (ह्रास का प्रावधान करने से पूर्व) को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता हैं।

अर्थ व्यवस्था के वृहद क्षेत्रों के अनुसार, स्थिर मूल्यों (1980-81) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 1990-91 व आगामी वर्षों के नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं।

स्थिर क़ीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रूपये)

वर्ष	प्राथमिक		गौण			योग तृतीयक	सकल राज्य घरेलू उत्पाद कालम 3+6+7
	कृषि (पशुपालन सहित)	योग प्राथमिक +	विनिर्माण	उपयोगिता*	योग गौण @		
1	2	3	4	5	6	7	8
1990-91(प्रा.)	4104	4437	1130	224	1928	3102	9467
	(43.35)	(46.87)	(11.94)	(2.37)	(20.36)	(32.77)	(100.00)
1991-92(प्रा.)	3468	3848	1139	248	1964	3127	8939
	(38.80)	(43.05)	(12.74)	(2.77)	(21.97)	(34.98)	(100.00)
1992-93(प्रा.)	4114	4514	1148	289	2050	3342	9906
	(41.53)	(45.57)	(11.59)	(2.92)	(20.69)	(33.74)	(100.00)
1993-94(त्व.)	3342	3785	1217	307	2167	3392	9344
	(35.77)	(40.51)	(13.02)	(3.29)	(23.19)	(36.30)	(100.00)
1994-95(अग्रिम)	4384	4834	1291	313	2307	3652	10793
	(40.62)	(44.79)	(11.96)	(2.90)	(21.37)	(33.84)	(100.00)

* उपयोगिता विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति को प्रदर्शित करती है।

प्रा० - प्रावधानिक त्व० - त्वरित

\+ वानिकी, मत्स्य एवं खनन सम्मिलित है। @ निर्माण सम्मिलित है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

सकल घरेलू उत्पाद में से ह्रास को घटाने के पश्चात् शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है।

वर्ष 1993-94 में प्रचलित क़ीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 24285 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया, जो कि वर्ष 1992-93 में 23168 करोड़ रुपये था। इस प्रकार यह 4.82 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

स्थिर (1980-81) क़ीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान जो वर्ष 1992-93 में 8807 करोड़ रुपये थे, घटकर वर्ष 1993-94 में 8187 करोड़ रुपये हो गए, जो 7.04 प्रतिशत की कमी दर्शाते हैं। अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 1994-95 के अनुमान 9576 करोड़ रुपये अनुमानित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। (सूखाग्रस्त वर्ष 1993-94 की तुलना में, वर्ष 1994-95 में, कृषि उत्पादन वृद्धि के कारण अनुमानों में उछाल रहा है)

प्रति व्यक्ति आय

प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में जनसंख्या का भाग देने के उपरान्त प्राप्त की जाती है।

प्रचलित क़ीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1992-93 में 5086 रुपये थी वह वर्ष 1993-94 में 5220 रुपये हो गई। इस प्रकार 2.63 प्रतिशत वृद्धि हुई।

वास्तविक रूप में प्रति व्यक्ति आय (स्थिर मूल्य 1980-81 के आधार पर) वर्ष 1992-93 में 1934 रुपये थी, वह घटकर वर्ष 1993-94 में 1760 रुपये हो गई, जो 9 प्रतिशत कमी को प्रदर्शित करती है। वर्ष 1994-95 की प्रति व्यक्ति आय 2016 रुपये अनुमानित की गई है, जो पिछले वर्ष की प्रतिव्यक्ति आय 1760 रुपये से 14.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

क्षेत्रीय संरचना

अर्थ व्यवस्था के वृहद क्षेत्रानुसार स्थिर (1980-81) मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक निम्न प्रकार हैं :-

स्थिर मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रूपये)

वर्ष	प्राथमिक		गौण			योग तृतीयक	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कालम संख्या 3+6+7
	कृषि (पशुपालन सहित)	योग प्राथमिक +	विनिर्माण	उपयोगिता*	योग गौण @		
1	2	3	4	5	6	7	8
1990-91(प्रा.)	3854	4122	951	75	1564	2787	8473
	(45.49)	(48.65)	(11.22)	(0.89)	(18.46)	(32.89)	(100.00)
1991-92(प्रा.)	3209	3519	948	102	1591	2791	7901
	(40.62)	(44.54)	(12.00)	(1.29)	(20.14)	(35.32)	(100.00)

1	2	3	4	5	6	7	8
1992-93(प्रा.)	3848	4176	946	133	1654	2977	8807
	(43.69)	(47.42)	(10.74)	(1.51)	(18.78)	(33.80)	(100.00)
1993-94(त्व.)	3069	3437	1002	147	1753	2997	8187
	(37.49)	(41.98)	(12.24)	(1.80)	(21.41)	(36.61)	(100.00)
1994-95(अग्रिम)	4105	4477	1063	150	1876	3223	9576
	(42.87)	(46.75)	(11.10)	(1.57)	(19.59)	(33.66)	(100.00)

* उपयोगिता विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, को दर्शाती है।
प्रा० - प्रावधानिक त्व० - त्वरित
\+ वानिकी मत्स्य एवं खनन सम्मिलित है @ निर्माण सम्मिलित है।

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से अर्थ व्यवस्था की संरचना में निम्न बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तथा इससे राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के क्षेत्रीय घटकों में पिछले वर्षों से हुए बदलाव भी प्रदर्शित होते हैं।

1- प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य और खनन सम्मिलित है, अभी भी वे राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रमुखता बनाए हुए हैं, फिर भी तुलनात्मक अनुपात प्राथमिक क्षेत्र का द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का वर्ष 1990-91 से कम ज़्यादा होता रहा है।

2- द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, उपयोगिता (विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति) निर्माण आदि सम्मिलित हैं,का योगदान निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 1990-91 में 18.46 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1994-95 में 19.59 प्रतिशत हो गया।

3- तृतीय क्षेत्र में यातायात, संचार, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, बैंक व्यापार एवं बीमा, स्थावर सम्पदा, सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाएँ सम्मिलित हैं, का योगदान 1990-91 में 32.89 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर वर्ष 1994-95 में 33.66 प्रतिशत हो गया।

2.2 अष्टम पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 1994-95

वर्ष 1992-93 व 1993-94 की वार्षिक योजनाओं पर क्रमशः 1405.72 करोड़ रुपये व 1743.32 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना का सम्भावित व्यय 2450 करोड़ रुपये है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वृहद क्षेत्रानुसार, वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 का वास्तविक व्यय व 1994-95 का सम्भावित व्यय निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

योजना उद्व्यय एवं व्यय

(करोड़ रूपये)

क्र०सं०	क्षेत्र	आठवीं योजना का उद्व्यय (1992-97)	व्यय 1992-93	व्यय 1993-94	संभावित व्यय 1994-95
1		2	3	4	5
1-	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ :	1286.92 (11.19)	128.15 (9.12)	161.00 (9.24)	245.79 (10.03)
2 -	ग्रामीण विकास	1021.75 (8.88)	100.71 (7.16)	116.67 (6.69)	193.86 (7.91)
3 -	विशिष्ट क्षेत्रीय योजना	84.00 (0.73)	1.10 (0.08)	1.52 (0.09)	3.61 (0.15)
4 -	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1919.99 (16.70)	260.32 (18.52)	288.34 (16.54)	387.94 (15.83)
5 -	ऊर्जा	3255.49 (28.31)	395.60 (28.14)	499.60 (28.66)	649.36 (26.51)
6 -	उद्योग एवं खनिज	536.02 (4.66)	81.96 (5.83)	88.12 (5.05)	119.44 (4.88)
7 -	यातायात	783.97 (6.82)	80.24 (5.71)	142.60 (8.18)	181.89 (7.42)
8 -	वैज्ञानिक सेवाएँ एवं अनुसंधान	19.96 (0.17)	2.93 (0.21)	3.31 (0.19)	4.37 (0.18)
9 -	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ	2461.62 (21.41)	333.09 (23.69)	412.69 (23.67)	613.91 (25.06)
10-	आर्थिक सेवाएँ	71.72 (0.62)	8.88 (0.63)	11.54 (0.66)	18.47 (0.75)
11-	सामान्य सेवाएँ	58.56 (0.51)	12.74 (0.91)	17.93 (1.03)	31.36 (1.28)
	योग	11500.00 (100.00)	1405.72 (100.00)	1743.32 (100.00)	2450.00 (100.00)

नोट : कोष्टक के समंक प्रतिशत दर्शाते हैं।

2.3 बैंकिंग

देश में तीव्र आर्थिक विकास से अधिकांश जन साधारण के जीवन स्तर में सुधार आया है लेकिन, फिर भी ग़रीबी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसकी ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों ने विकास की गति को प्रभावित किया है। राज्य के सीमित संसाधनों से जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करना कठिन है, अतः समग्र विकास हेतु संस्थागत वित्त एवं ऋण आदि दूसरे उपाय भी नितांत आवश्यक है।

राज्य सरकार योजनान्तर्गत, ढाँचा गत विकास एवं मानव संसाधन के विकास हेतु प्रयत्नशील है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर औसत प्रति व्यक्ति आय का अन्तर बढ़ रहा है। अतः राज्य में विकास को गति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों, एवं व्यक्तियों की आय बढ़ाने हेतु संसाधन जुटाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

बैंकों द्वारा ऋण वितरण, राज्य के विकास एवं विनियोजन के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत है। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के विकास के लिए एन. आर. वाई.,पी. एम. आर. वाई.,आई. आर. डी. पी. जैसे ऋण आधारित कार्यक्रम, एवं अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बैंकों की सहायता से राज्य में चलाए जा रहे हैं। विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक शाखाओं के विस्तार, विशेषकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विस्तार से ,गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वर्गों के उत्थान के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। बैंक शाखाओं की जमा राशि एवं ऋण वितरण की तुलनात्मक स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है।

(वर्ष के सितम्बर माह तक)

क्र० सं०	मद	राजस्थान		भारत	
		1993	1994	1993	1994
1 -	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक				
	(अ) कार्यालयों की संख्या	966	1068	14465	14550
	(ब) जमा (करोड़ रु.)	393	564	7279	9131
	(स) ऋण (करोड़ रु.)	181	233	4712	5509
2 -	अन्य अनुसूचित व्यापारिक बैंक				
	(अ) कार्यालयों की संख्या	2044	2082	47005	47506
	(ब) जमा (करोड़ रु.)	7454	9154	278606	336733
	(स) ऋण(करोड़ रु.)	3731	3977	162397	184531
3 -	योग				
	(अ) कार्यालयों की संख्या	3010	3150	61470	62056
	(ब) जमा(करोड़ रु.)	7847	9718	285885	345864
	(स) ऋण (करोड़ रु.	3912	4210	167109	190040

उपरोक्त तालिका यह प्रदर्शित करती है कि सितम्बर 1994 में सितम्बर 1993 की तुलना में बैंक जमा राशि व ऋण दोनों में वृद्धि हुई। राजस्थान में जमा राशि में वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में 23.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 20.98 प्रतिशत थी। राजस्थान में ऋण व जमा राशि का अनुपात सितम्बर 1994 में 43.32 प्रतिशत रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 54.95 प्रतिशत था। सितम्बर 1993 में यह अनुपात राजस्थान व राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः 49.86 व 58.45 प्रतिशत था। राजस्थान में वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में कुल ऋण 7.62 प्रतिशत बढ़ा, जबकि भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 13.72 प्रतिशत रही।

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में सितम्बर 1994 में एक बैंक कार्यालय 13970 व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान कर रहा था, तथा 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बैंक कार्यालय स्थापित था।

*****

3. मूल्य स्थिति एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

लाभों के उचित वितरण एवं विकास की गति को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यों में स्थिरता आवश्यक है। मुद्रास्फीति ग़रीबों को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि उनकी आय मूल्यों के अनुरूप नहीं बढ़ पाती है। थोक भाव सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य के द्वारा पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 1994 में राज्य अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है।

3.1 थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1952-53=100)

वर्ष 1994 में राजस्थान राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक 1827.6 रहा, जो वर्ष 1993 के 1668.70 से 9.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । थोक मूल्य सूचकांक के "खाद्य वर्ग " में सर्वाधिक वृद्धि 12.22 प्रतिशत, औद्योगिक कच्चे माल वर्ग में 6.78 प्रतिशत, "ईधन शक्ति प्रकाश एवं उपस्नेहक वर्ग" में 2.74 प्रतिशत तथा विनिर्मित पदार्थ वर्ग में 2.52 प्रतिशत रही।

माह मार्च एवं दिसम्बर 1994 को छोड़कर, वर्ष 1994 के अन्य माहों में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि का रुख रहा। इन दो महीनों में पिछले महीनों से क्रमशः 3.52 प्रतिशत एवं 0.93 प्रतिशत की कमी हुई। शेष सभी महीनों में सामान्य थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि की प्रवृत्ति रही।

वर्ष 1994 में प्रमुख वर्गों के थोक भाव सूचकांक में पिछले दो वर्षों से प्रतिशत विचलन निम्नलिखित तालिका से दर्शाया गया है।

थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1952-53=100)

क्र.सं. वृहद वर्ग	वार्षिक औसत			पिछले वर्ष से प्रतिशत विचलन	
	1992	1993	1994	1993	1994
1 2	3	4	5	6	7
1-खाद्य वर्ग	1558.4	1578.8	1771.8	1.31	12.22
2-औधोगिक कच्चे माल वर्ग	1570.9	1555.3	1660.8	(-)0.99	6.78
3-ईधन, शक्ति,प्रकाश एवं उपस्नेहक वर्ग	3005.3	3076.7	3160.91	2.38	2.74
4-विनिर्मित पदार्थ वर्ग	1668.9	1843.4	1889.93	10.46	2.52
5-सामान्य सूचकांक	1622.7	1668.7	1827.61	2.83	9.52

3.2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100)

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार किए जाते हैं जिसमें राज्य के जयपुर एवं अजमेर केन्द्र सम्मिलित हैं। वर्ष 1994 में खुदरा मूल्यों में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति रही।

वर्ष 1994 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जयपुर केन्द्र पर 9.80 प्रतिशत और अजमेर केन्द्र पर 10.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वर्ष 1993 में यह वृद्धि दर जयपुर केन्द्र के लिए 7.46 प्रतिशत व अजमेर केन्द्र के लिए 4.12 प्रतिशत थी।

जयपुर एवं अजमेर केन्द्र के समस्त वर्गानुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किए गए हैं :-

वर्गानुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

जयपुर केन्द्र **(आधार वर्ष 1982=100)**

वर्ग	जयपुर केन्द्र			प्रतिशत विचलन	
	1992	1993	1994	1994 का 1993 से	1993 का 1992 से
1	2	3	4	5	6
1- खाद्य	248	266	295	10.90	7.26
2- पान,सुपारी,तंबाकू एवं मादक पदार्थ	292	318	356	11.95	8.90
3- ईंधन,शक्ति एवं प्रकाश	195	210	219	4.29	7.69
4- आवास	146	148	154	4.05	1.37
5- वस्त्र,बिस्तर तथा जूते	174	184	210	14.13	5.75
6- विविध	253	2 74	97	8.39	8.30
7- सामान्य	228	245	269	9.80	7.46

अजमेर केन्द्र **(आधार वर्ष 1982=100)**

	अजमेर केन्द्र			प्रतिशत विचलन	
	1992	1993	1994	1994 का 1993 से	1993 का 1992 से
1	2	3	4	5	6
1-खाद्य	243	249	287	15.26	2.47
2-पान,सुपारी,तम्बाकू एवं मादक पदार्थ	297	320	337	5.31	7.74
3- ईंधन,शक्ति एवं प्रकाश	229	233	239	2.58	1.75
4- आवास	300	308	314	1.95	2.67
5- वस्त्र,बिस्तर तथा जूते	207	224	248	10.71	8.21
6- विविध	219	238	255	7.14	8.68
7- सामान्य	243	253	280	10.67	4.12

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1994 में दोनों केन्द्रों के सामान्य औसत सूचकांकों की वृद्धि में सभी समूहों का सामूहिक योगदान रहा है।

जयपुर, अजमेर एवं अखिल भारतीय स्तर के वर्ष 1982 के आधार पर पिछले पाँच वर्षों के औसत सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निम्नलिखित तालिका में दिये गए हैं।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

वर्ष	जयपुर केन्द्र		अजमेर केन्द्र		अखिल भारतीय	
		% विचलन गत वर्ष की तुलना में		%विचलन गत वर्ष की तुलना में		% विचलन गत वर्ष की तुलना में
1990	184	8.87	190	11.11	186	8.77
1991	210	14.13	217	14.21	212	13.98
1992	228	8.57	243	11.98	237	11.79
1993	245	7.46	253	4.11	252	6.33
1994	269	9.80	280	10.67	278	10.32

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 1991 में जयपुर, अजमेर एवं अखिल भारतीय स्तर के सूचकांकों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 14.13 प्रतिशत, 14.21 प्रतिशत एवं 13.98 प्रतिशत की वृद्धि रही जो कि पिछले पाँच वर्षों में सर्वाधिक है। वर्ष 1994 में सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पिछले वर्ष की तुलना में अजमेर केन्द्र में 10.67 प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर 10.32 प्रतिशत एवं जयपुर केन्द्र में 9.80 प्रतिशत रही।

3.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियमित एवं पर्याप्त मात्रा में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएँ उपलब्ध करवा रही है।

राज्य में कुल कार्यरत (जनवरी, 1995) 16798 उचित मूल्य की दुकानों में से 12631 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत थी। इन दुकानों के माध्यम से मार्च, 1994 से जनवरी, 1995 के दौरान 3.80 लाख टन गेहूँ, 0.08 लाख टन चावल, 1.68 लाख टन चीनी और 3.17 लाख किलो लीटर मिट्टी का तेल वितरित किया गया।

जनवरी, 1992 से राज्य के जनजाति, रेगिस्तानी एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आर०पी०डी०एस० पद्धति की वितरण व्यवस्था लागू है। 22 जिलों के 122 चयनित खण्डो में आर०पी०डी०एस० के अतिरिक्त अनुदानित मूल्यों पर गेहूँ और चावल वितरित किए जा रहे है।

*****

4 उद्योग एवं खनिज

4.1 उद्योग

राज्य की औद्योगिक नीति 1994 का मुख्य उद्देश्य कार्यविधि में सरलीकरण, शीघ्रता से प्रकरणों का निस्तारण, आर्थिक प्रोत्साहन एवं विभिन्न अन्य उपायों द्वारा राज्य में शीघ्र औद्योगिक विकास करना है। इसके अतिरिक्त नवीन औद्योगिक नीति में राज्य के लघु एवं ग्रामीण उद्योग रोजगारोन्मुख उद्योग एवं महिला उद्यमियों हेतु पर्याप्त सहयोग दिये जाने की व्यवस्था की गई है। निर्यात वर्धन की राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए निर्यात वृद्धि पर विशेष महत्व दिया गया है। राज्य के औद्योगिक विकास हेतु उद्योग विभाग एवं अन्य निगम व बोर्ड जैसे रीको, राजसीको,राज्य वित्त निगम तथा राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड आदि द्वारा समन्वित प्रयास किए जा रहे है।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) द्वारा दिसम्बर, 1994 तक स्थापित 206 औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा रही है। रीको द्वारा वृहद एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है । वर्ष 1994-95 में (दिसम्बर, 1994 तक) 31.49 करोड़ रुपये के सावधि ऋण स्वीकृत किए जाकर 19.60 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत स्वीकृत चार विकास केन्द्रों बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़ एवं आबूरोड में वर्ष 1994-95 के दौरान कार्य प्रगति पर रहा। इसके अतिरिक्त राज्य में दो लघु विकास केन्द्र जोधपुर एवं उदयपुर की योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई, जिसमें से जोधपुर केन्द्र को स्वीकृत किया जा चुका है एवं 45.17 करोड़ रुपये इसके क्रियान्वयन पर व्यय किए जा चुके हैं।

राज्य में लघु एवं मध्यम पैमाने के उद्योगों को राज्य वित्त निगम भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है। वर्ष 1994-95 (दिसम्बर, 1994 तक) के दौरान 989 औद्योगिक इकाइयों को 94 करोड़ रुपये स्वीकृत एवं 72.53 करोड़ रुपये वितरित किए गए। आलोच्य अवधि में राज्य वित्त निगम द्वारा 87.63 करोड़ रुपये ऋण की वसूली की गई।

राज्य उद्योग विभाग, लघु उद्योग तथा हस्तशिल्प इकाइयों जिनमें कि वृहत पैमाने के उद्योगों की तुलना में कम पूँजी विनियोजन से अधिक रोज़गार की क्षमता निहित होती है के त्वरित विकास के लिए ध्यान दे रहा हैं। इन इकाइयों के विकास के लिए प्रोत्साहन एवं रियायतों के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश, सहायता तथा सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। वर्ष 1994-95 के दौरान लघु उद्योग तथा हस्तशिल्प की 4000 इकाइयों के पंजीयन के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर 1994 तक 2809 इकाइयों को पंजीकृत किया गया। इन इकाइयों में 106.55 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया तथा 14823 व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त हुआ। अब तक राज्य में 170209 लघु उद्योग तथा हस्तशिल्प इकाइयों का पंजीयन किया जा चुका है जिनमें 1423.33 करोड़ रुपये का विनियोजन तथा 6.51 लाख व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त हुआ है।

प्रधानमन्त्री रोज़गार योजना सर्वप्रथम वर्ष 1993 में शहरी क्षेत्र में आरम्भ की गई थी, परन्तु चालू वर्ष में यह योजना राज्य के शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत बेरोज़गार युवकों को स्वयं की औद्योगिक इकाई, व्यवसाय एवं सेवा उद्योग स्थापित करने हेतु एक लाख रुपये तक का ऋण/ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं। इस ऋण हेतु किसी प्रतिभूति गारन्टी की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत इकाई की लागत के 15 प्रतिशत तक (अधिकतम 7500 रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में

चयनित आवेदकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान है। प्रशिक्षण के दौरान 300 रुपये प्रति माह प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में दिये जाते हैं। उद्योग विभाग द्वारा 200 परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर जिला औद्योगिक केन्द्रों को बेरोज़गार युवकों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 1994-95 के दौरान 8300 के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 1994 तक 4783 बेरोज़गार युवक लाभान्वित हुए।

राज्य स्तर पर उद्यमियों को एक ही स्थान पर आवश्यक दिशा-निर्देश, सहायता तथा सुविधाएँ प्रदान करने हेतु उद्योग विभाग में एक औद्योगिक सूचना ब्यूरो कार्यरत है। सभी ज़िलों में उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने हेतु जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत है।

राजस्थान लघु उद्योग निगम, लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान करता है। राजस्थान के हस्तशिल्प को लोकप्रिय करने एवं विपणन हेतु अनेक एम्पोरियम कार्यरत है।

4.2 **खादी एवं ग्रामोद्योग**

खादी एवं ग्रामोद्योग अपेक्षाकृत कम पूँजी विनियोजन से रोज़गार के अवसरों के सृजन में विशेष रूप से सहायक है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की देख रेख में इन इकाइयों के संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1993-94 के दौरान ऊनी एवं सूती खादी का उत्पादन मूल्य 31.51 करोड़ रुपये था, जिसके वर्ष 1994-95 में बढ़ कर 34.50 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। वर्ष 1993-94 में ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन मूल्य 197.61 करोड़ रुपये था, जिसके वर्ष 1994-95 में बढ़कर 207.10 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1994-95 के दौरान 4.27 लाख व्यक्तियों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए, जबकि 1993-94 में 4.17 लाख व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया था।

4.3 **कारखाना एवं बायलर्स**

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, राजस्थान, राज्य में पंजीकृत निर्माणियों के लिए प्राधिकृत अधिकारी है। इस विभाग का मुख्य कार्य भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, भारतीय बायलर्स अधिनियम 1923 एवं वेतन भुगतान अधिनियम 1936 को लागू करवाना है। औद्योगिक कामगारों के स्वास्थ्य,सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करना विभाग का मुख्य कार्य है। वर्ष 1994-95 के दौरान (दिसम्बर 1994 तक) 674 नई निर्माणियों का पँजीकरण किया गया तथा 15037 श्रमिकों को रोज़गार प्राप्त हुआ।

चयनित महत्वपूर्ण उत्पादन की वर्ष 1993 एवं 1994 की तुलनात्मक स्थिति (प्रावधानिक) निम्नांकित सारणी में दर्शाई गई है।

कुल चयनित मदों का औद्योगिक उत्पादन

क्र०सं०	मद	इकाई	उत्पादन		वर्ष 1993 की तुलना से 1994 में प्रतिशत परिवर्तन
			1993	1994 (प्रावधानिक)	
1	2	3	4	5	6
1-	शक्कर	टन	26261.70	15245.33	(-)41.95
2-	स्प्रिट(सभी प्रकार)	"000 लीटर	17646.93	16667.43	(-) 5.55
3-	वनस्पति घी	टन	33841.31	39816.94	17.66
4-	नमक	लाख मै.टन	12.96	11.42	(-)11.88
5-	यूरिया	"000 मै.टन	406.65	374.46	(-) 7.92
6-	सुपर फास्फेट	" "	71.36	69.92	(-) 2.02
7-	सीमेंट	" "	4810.25	5870.71	22.05
8-	अभ्रक की ईटें	"000 संख्या	81797.68	2107.04	17.21
9-	जस्ते की छड़े	"000 मै.टन	83.14	100.71	21.13
10-	कैडमियम अंतिम उत्पादन	टन	164.19	133.70	(-)18.57
11-	रेलवे वैगन	संख्या	1872	600	(-)67.95
12-	बाल बियरिंग	लाख संख्या	183.52	203.90	11.11
13-	पानी के मीटर	संख्या	47422	40935	(-)13.68
14-	रेडिएटर्स	" "	3365	2272	(-)32.48
15-	लेपित एवं पुनः लेपित पत्थर	"000 स्क्वायर मीटर	200.97	220.28	9.61
16-	बिजली के मीटर	संख्या	876522	1138755	29.92
17-	नायलोन धागा	टन	3438.04	3956.39	15.08
18-	पोलिएस्टर धागा	""	13510.72	19832.68	46.79
19-	कॉस्टिक सोडा	""	39131	42251	7.97
20-	कैलशियम कार्बाइड	""	47405	45318	(-)4.40
21-	पी०वी०सी०रेजिन	""	34272	32195	(-)6.06
22-	पी०वी०सी०कम्पाउण्ड	""	4607	5100	10.70
23-	सल्फ्युरिक ऐसिड	""	226.35	327.72	44.79
24-	कॉपर "काथ्रोड्स"		21131	32144	52.12
25-	सूती कपड़ा	लाख मीटर	422.41	373.22	(-)11.64
26-	सूती धागा	"000 टन	54.62	58.28	6.70

उपरोक्त सारणी से प्रकट होता है कि वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 मे चयनित मदों के उत्पादन में मिश्रित प्रवृत्ति रही। गत वर्ष की तुलना में 26 चयनित मदों में से 14 मदों के उत्पादन में वृद्धि दृष्टिगत हुई है जबकि 12 मदों के उत्पादन में कमी रही। इन मदों के उत्पादन में विचलन की सीमा इस प्रकार है:-

वर्ष 1994 में वर्ष 1993 की तुलना में विचलन प्रतिशत		मद
1.1	10 प्रतिशत तक वृद्धि	लेपित एवं पुनः लेपित पत्थर,कॉस्टिक सोडा एवं सूती धागा
1.2	10 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि	वनस्पति घी, अभ्रक की ईटें, बाल बियरिंग्स, नाईलोन धागा एवं पी.वी.सी. कम्पाउण्ड
1.3	20 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि	सीमेंट,जस्ते की छड़े, बिजली के मीटर, पोलियस्टर धागा, सल्फ़्यूरिक ऐसिड
1.4	50 से 100 प्रतिशत तक वृद्धि	कॉपर कैथोड्स
1.5	100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि	शून्य
2.1	10 प्रतिशत तक कमी	स्पिरिट (सभी प्रकार) यूरिया, सुपर फ़ॉस्फ़ेट, कैलशियम कार्बाइड, पी.वी.सी. रेज़िन
2.2	10 से 20 प्रतिशत तक कमी	नमक, कैडमियम अन्तिम उत्पादन,पानी के मीटर, सूती कपड़ा
2.3	20 से 50 प्रतिशत तक कमी	चीनी, रेडिएटर्स
2.4	50 से 100 प्रतिशत तक कमी	रेलवे वैगन

4.4 **खनिज**

हाल ही में राज्य सरकार ने नई खनिज नीति 1994 की घोषणा की है जिसके मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीक से राज्य में उपलब्ध खनिज का त्वरित गति से दोहन करना है। खनिज आधारित उद्योगों एवं प्रोन्नत प्रक्रिया द्वारा मूल विकास से निर्यात एवं मानव संसाधनों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे खनिज आधारित उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी एवं रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। नई खनिज नीति के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बड़े पैमाने पर खनन पट्टे दिये गए हैं, ढ़ाचागत विकास से सम्बन्धित कार्य राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को सौपें गए हैं। तदानुसार सड़क, विद्युत आदि सुविधाएँ खनिज निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी। पट्टेधारी, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की खनिज सम्पदा के आधारभूत विकास हेतु आवश्यक धनराशि का भुगतान करेंगे।

वर्ष 1994-95 में तीन खनिज सर्वेक्षण एवं प्रोस्पेक्टिव योजनाओं के अंतर्गत 72 परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया है। दिसम्बर, 1994 तक के निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं।

कार्य	इकाई	लक्ष्य (दिसम्बर' 94 तक)	उपलब्धियाँ (दिसम्बर' 94 तक)	प्रतिशत उपलब्धियाँ
1- आर.एम.एस.	वर्ग कि.मी.	3625	3625	100.00
2- आर.जी.एम.	" "	325	260.25	80.07
3- डी.जी.एम.	" "	20.50	28.09	137.02
4- ड्रिलिंग	मीटर	11050	9822.10	88.89

वर्ष 1994-95 के दौरान ग्रेनाइट डेलिनिएशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई हैं । अजमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, एवं राजसमंद ज़िलों के कुल 170 से अधिक प्लाट डेलीनिएटेड किए गए ।

सानू क्षेत्र में एस०एम०एस०ग्रेड लाइम स्टोन के दोहन का कार्य जारी रहा। वर्ष 1994-95 में जैसलमेर ज़िले में खुईआला एवं तुलसी राम की ढाणी क्षेत्रों में ड्रिलिंग का कार्य हाथ में लिया गया। वर्ष के दौरान सिरोही ज़िले के गारिया एवं बून्दी ज़िले के पालगुटा कोलजी क्षेत्रों में सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन की खोज का कार्य प्रगति पर है।

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम संयुक्त क्षेत्र अथवा स्वयं के खनिज आधारित उद्योगों, परियोजनाओं एवं उपक्रमों को प्रोन्नत करने/विकास करने एवं संचालित करने में कार्यरत है। निगम खनन कार्य के अतिरिक्त खानों के विकास एवं खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु परामर्श का कार्य भी करता है। निगम राज्य के 13 ज़िलों में विभिन्न स्थानों पर स्वयं की खानों का व्यावसायिक रूप से संचालन तथा लाइम स्टोन, रॉक फ़ॉस्फ़ेट, जिप्सम, फैल्सपार एवं ग्रेफ़ाइट के उत्पादन एवं विक्रय का कार्य कर रहा है।

4.5 श्रम

औद्योगिक सम्बन्ध

औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादकता एवं उत्पादन में वांछित वृद्धि हेतु औद्योगिक शांति परमावश्यक है। वर्ष 1994-95 में (दिसम्बर,1994 तक) राज्य में 35 हड़तालें/तालाबन्दी हुई जिससे 14528 श्रमिक प्रभावित हुए, तथा 3.48 लाख मानव दिवसों की हानि हुई, जब कि वर्ष 1993-94 में 43 हड़तालें/तालाबन्दी हुई, जिससे 14942 श्रमिक प्रभावित हुए तथा 4.10 लाख मानव दिवसों की हानि हुई।

राज्य में वर्ष 1994-95 के आरम्भ में 3710 पंजीकृत श्रमिक संगठन थे, जिनके सदस्यों की संख्या 6.48 लाख थी। दिसम्बर, 1994 तक 138 नवीन संगठनों को पंजीकृत किया गया जिनके सदस्यों की संख्या 0.16 लाख है। वर्ष के दौरान 963 श्रमिक संगठनों को वार्षिक विवरण जमा नहीं कराने के कारण अपंजीकृत किया गया। इस प्रकार दिसम्बर, 1994 तक पंजीकृत श्रमिक संगठनों की संख्या 2885 थी।

न्यूनतम मज़दूरी

श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु एक जनवरी, 1995 से अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिकों के न्यूनतम दैनिक मज़दूरी में निम्न तालिका के अनुसार वृद्धि की गई है।

श्रमिक	न्यूनतम दैनिक मज़दूरी (रुपयों में)	
	2.7.1990 को	1.1.1995 से
1. अकुशल	22.00	32.00
2. अर्ध्दकुशल	23.50	33.00
3. कुशल	25.00	34.00

4.6 रोज़गार

नियोजित विकास का एक मुख्य उद्देश्य रोज़गार के अवसर सृजन करने का है, अतः रोज़गार के अवसर एवं विभिन्न वर्गों के बेरोजगारों की सूचना रखना आवश्यक है। वर्ष 1994 में राज्य में पंजीकृत निर्माणियों में औसतन प्रतिदिन रोज़गार 3.10 लाख रहा जबकि 1993 में औसत प्रतिदिन रोज़गार 2.95 लाख था।उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योगों में वर्ष 1993-94 में 6.30 लाख औसत दैनिक रोज़गार -नियोजन की तुलना में वर्ष 1994-95 (दिसम्बर, '94 तक) में 6.51 लाख औसत प्रतिदिन रोज़गार रहा।खादी एवं ग्रामोद्योग के अन्तगर्त वर्ष 1994-95 में 4.27 लाख व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध कराया जावेगा।इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास एवं ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत रोज़गार के अवसर सुलभ करवाए जा रहे हैं।

राजस्थान में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में अनुमानित रोज़गार की स्थिति निम्न प्रकार है :

(लाख व्यक्तियों में)

वर्ष	राजस्थान		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1	2	3	4
1992	9.73	2.31	12.04
1993	9.77	2.32	12.09
1994 (मार्च, '94 तक)	9.85	2.39	12.24

पंचायत समिति स्तर पर रोज़गार शिविरों का भी आयोजन किया गया जिससे ग्रामीण युवाओं को मार्गदर्शन के द्वारा रोज़गार एवं स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित किया गया। रोज़गार निदेशालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के रिक्त पदों, प्रतियोगिता परीक्षा , प्रशिक्षण , छात्रवृत्ति एवं विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों की सूचना पाक्षिक समाचार पत्र " रोज़गार संदेश " में प्रकाशित की जाती है।

*****

5. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

5.1 मानसून

राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है तथा कृषि मानसून पर निर्भर करती है। सितम्बर, 1994 में कुछ समय तक शुष्क मौसम के बावजूद वर्षा की स्थिति वर्ष 1994 में कुल मिलाकर संतोषप्रद रही। परिणाम स्वरूप प्रचुर मात्रा में कृषि उत्पादन की आशा है। जून, जुलाई व अगस्त, 1994 में औसत से अधिक वर्षा हुई जिससे रबी फ़सल के अंतर्गत अधिक क्षेत्र में फ़सल बोए जाने को बढ़ावा मिला। वर्ष 1993-94 में कम व असमान वर्षा के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ था जब कि चालू वर्ष में कुल अनाज का उत्पादन 105 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य से अधिक होने की आशा है, किन्तु फिर भी यह वर्ष 1992-93 के रिकार्ड उत्पादन 114 लाख टन को पार नहीं कर पाएगा।

5.2 कृषि उत्पादन

राज्य आयोजना में कृषि उत्पादन की अहम् भूमिका है क्योंकि राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 45 प्रतिशत के लगभग रहता है, एवं जनसंख्या का लगभग 68 प्रतिशत इस क्षेत्र में कार्यरत है।

गत तीन वर्षों के प्रमुख फ़सलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं :

फ़सल	क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में)			उत्पादन (लाख टनों में)		
	1992-93 संशोधित	1993-94 अंतिम	1994-95 संभावित	1992-93 संशोधित	1993-94 अंतिम	1994-95 संभावित
अनाज						
खरीफ़	69.01	60.92	66.36	44.97	22.70	35.28
रबी	24.95	21.92	21.08	55.24	37.06	51.89
दालें						
खरीफ़	19.49	20.54	19.56	6.23	2.75	5.42
रबी	14.92	12.62	15.49	8.35	7.94	12.78
खाद्यान्न						
खरीफ़	88.50	81.46	85.92	51.20	25.45	40.70
रबी	39.87	34.54	36.57	63.59	45.00	64.67
कुल	128.37	116.00	122.49	114.79	70.45	105.37
तिलहन						
खरीफ़	9.73	11.71	12.21	7.23	6.41	8.35
रबी	23.83	24.35	24.08	18.18	17.62	24.34
कुल	33.56	36.06	36.29	25.41	24.03	32.69
गन्ना	0.24	0.21	0.19	11.29	10.20	8.90
कपास*	4.76	5.18	4.61	10.16	8.39	10.78

* उत्पादन लाख गाँठों में।

यद्यपि राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन में गत वर्षों की अपेक्षा बढोत्तरी हुई है फिर भी इसमें उतार चढ़ाव परिलक्षित है, जो कि मुख्यतः वर्षा की अनिश्चितता तथा इसके असमान वितरण के कारण है।

वर्ष 1994-95 में खाद्यान्न के अन्तर्गत 122.49 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल बोए जाने का अनुमान है, जबकि वर्ष 1993-94 में कुल बोया गया क्षेत्रफल 116 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 1994-95 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 105.37 लाख टन होने का अनुमान है जो कि वर्ष 1993-94 में 70.45 लाख टन था। इस प्रकार खाद्यान्न उत्पादन में 49.57 प्रतिशत बढोत्तरी की आशा है।

राज्य में कुल अनाज उत्पादन में अधिकतम योगदान खरीफ़ में बाजरा, मक्का, ज्वार तथा रबी में विशेषतः गेहूँ का रहता है। तथापि खरीफ़ में चावल, छोटे अनाज तथा रबी में जौ चना आदि भी बोया जाता है।

वर्ष 1994-95 में खरीफ़ अनाज उत्पादन 35.28 लाख टन होने की सम्भावना है, जो कि वर्ष 1993-94 में 22.70 लाख टन था। रबी अनाज उत्पादन वर्ष 1993-94 में 37.06 लाख टन की तुलना में वर्ष 1994-95 में 51.89 लाख टन होने की आशा है।

दलहन आहार में प्रोटीन स्त्रोत का एक महत्वपूर्ण संघठक है, तथा ऊर्जा व खनिज का भी अच्छा स्त्रोत है। यह निम्न एवं मध्यम आय वर्गीय परिवारों में संतुलित आहार देने में सहायक है।

खरीफ़ दालों का उत्पादन वर्ष 1993-94 के 2.75 लाख टन की तुलना में, वर्ष 1994-95 में 5.42 लाख टन होना अनुमानित है, जो कि 97.09 प्रतिशत अधिक है। रबी दालों का उत्पादन वर्ष 1993-94 के 7.94 लाख टन की तुलना में, वर्ष 1994-95 में 12.78 लाख टन होने की सम्भावना है। इस प्रकार कुल दालों के उत्पादन में वर्ष 1994-95 में 70.25 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है।

राजस्थान में तिलहन के उत्पादन में खरीफ़ मौसम में मूँगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी तथा रबी मौसम में राई-सरसों, तारामीरा, अलसी सम्मिलित है। सोयाबीन एवं राई-सरसों के उत्पादन मे वृद्धि के कारण पिछले वर्षों में तिलहन उत्पादन में उल्लेखनीय बढोत्तरी दर्ज हुई है। बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 1994-95 में 32.69 लाख टन रिकार्ड स्तर पर उत्पादन होने की संभावना है।

गन्ना राज्य की महत्वपूर्ण फ़सल होने के बावजूद भी गत वर्षों में इसके उत्पादन, क्षेत्र एवं उत्पादकता में लगातार कमी हो रही है। गन्ने का उत्पादन वर्ष 1993-94 के 10.20 लाख टन की तुलना में, वर्ष 1994-95 में 8.90 लाख टन होने की आशा है, जो गत तीन वर्षों में गन्ने का उत्पादन निम्नतम है।

कपास एक महत्वपूर्ण "नगदी फसल" है, जो राज्य में विशेष कर गंगानगर ज़िले में बोई जाती है। गंगानगर के अतिरिक्त यह बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, पाली, बीकानेर ज़िलों के कुछ भागों में भी बोई जाती है। वर्ष 1994-95 में कपास का उत्पादन बढ़ कर 0.78 लाख टन होने की आशा है।

गत वर्षों में कृषि उत्पादन व उत्पादकता का स्तर, क्षेत्रफल, सूचकांकों द्वारा निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता के सूचकांक (आधार वर्ष 1979-82 =100)

वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1989-90	103.09	165.94	155.53
1990-91	114.38	211.43	165.06
1991-92	107.68	182.33	147.41
1992-93	117.03	216.67	157.22
1993-94	109.36	156.38	122.04

5.3 **कृषि विस्तार एवं आदान प्रबन्धन**

अधिक उत्पादन की प्राप्ति हेतु अच्छे बीजों की उपलब्धि आवश्यक है, तदानुसार राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु "उन्नत बीज क़िस्म कार्यक्रम" प्रारम्भ करने की कृषि व्यूह रचना अपनाई गई है। फ़सल की उपज में उर्वरक का उपयोग एक मुख्य निर्धारक भूमिका प्रदान करता है।

राज्य में अनियमित मानसून व मौसम की विपरीत स्थिति का कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु कृषि विभाग द्वारा कृषि विस्तार एवं आदान कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। राज्य में कृषि विस्तार एवं आदान प्रबन्धन कार्यक्रमों की वर्ष 1993-94 व 1994-95 की उपलब्धियाँ निम्न तालिका में अभिलेखित की गई है:

मद	इकाई	मौसम	1993-94 उपलब्धियाँ	लक्ष्य	1994-95 उपलब्धियाँ (सम्भावित)
1- अधिक उपज वाली फ़सलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	लाख है.	ख़रीफ़	14.56	16.60	12.41
		रबी(गेहूं)	14.83	15.00	14.00
2- अधिक उपज वाली क़िस्मों के बीजों का वितरण	000क्वि.	ख़रीफ़	40.80	49.90	42.70
		रबी(गेहू)	140.50	110.00	120.00
3- अन्य उन्नत बीजों का वितरण	000क्वि.	ख़रीफ़	47.10	40.30	52.90
		रबी(गेहूं)	37.50	37.00	40.90
4- उर्वरकों का वितरण	000टन	ख़रीफ़	227.00	246.60	263.10
		रबी	275.00	379.50	379.50
5- जीवाणु कल्चर पैकेट्स का वितरण	पैकेट्स लाख नम्बरों में	ख़रीफ़	1.67	4.50	0.43
		रबी	0.47	3.00	0.64
6- पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	लाख है.	ख़रीफ़	45.00	38.00	31.50
		रबी	34.07	36.00	36.00

5.4 **सिंचाई**

राज्य में कुल बोए गए क्षेत्रफल का औसतन 27.20 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है। सिंचाई के चार प्रमुख स्त्रोतों में नहरें, तालाब, कुएँ तथा नल कूप हैं। वर्ष 1992-93 में कुल सिंचित क्षेत्रफल का 58.90 प्रतिशत कुएँ व नलकूपों से, 36.27 प्रतिशत नहरों से, तथा 4.83 प्रतिशत तालाबों व अन्य स्त्रोतों से सिंचित किया गया।

वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक क्षेत्र वार सिंचित क्षेत्र का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

(क्षेत्रफल 000 हैक्टेयर में)

सिंचाई के स्त्रोत	शुद्ध सिंचित क्षेत्र			कुल सिंचित क्षेत्र		
	1990-91	1991-92	1992-93	1990-91	1991-92	1992-93
1- नहरें	1354	1424	1428	1768	1856	1990
2- तालाब	184	163	207	200	181	230
3- कुएँ एवं नलकूप	2341	2702	2803	2658	3170	3231
4- अन्य	25	54	33	26	57	35
कुल	3904	4343	4471	4652	5264	5486

सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु राज्य का सिंचाई विभाग विभिन्न वृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में प्रयासरत है। वर्ष 1994-95 हेतु 280.34 करोड़ रुपये का प्रावधान विभिन्न वृहत, मध्यम और अन्य कार्यो के लिए रखा गया है जिसमें 93 करोड़ रुपये इंदिरा गांधी नहर परियोजना, एवं 23 करोड़ रुपये माही परियोजना के सम्मिलित हैं। वर्ष 1994-95 में 79.87 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें से 2670 हैक्टेयर क्षेत्र में विश्व बैंक की सहायता से, माही बज़ाज़ सागर परियोजना अन्तर्गत सिंचाई क्षमता का सृजन किया जावेगा। बाँधों की सुरक्षा परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त एफ. आर. पी. सहायता से 14 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

योजना अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 93 करोड़ रुपये, एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 52 करोड़. रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से क्रमशः 47.62 करोड़ रुपये एवं 32.59 करोड़ रुपये जनवरी 1995 तक व्यय किए जा चुके है, जब कि वर्ष 1993-94 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 79.61 करोड़ एवं 52 करोड़ रुपये केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत व्यय किए गए थे।

5.5 **पशुपालन**

राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन/पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि अल्प आय वर्ग के लघु व सीमान्त कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को लाभप्रद रोज़गार उपलब्ध कराने में सहायक है।

राजस्थान पशु सम्पदा में सम्पन्न एवं बड़ा राज्य है। वर्ष 1992 की पशु गणना के अनुसार राज्य में 477.73 लाख (प्रावधानिक) पशु धन उपलब्ध था। राज्य के पश्चिमी ज़िले देशी पशु धन हेतु प्रसिद्ध हैं।

समग्र (एकीकृत) पशु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 से 8 कि.मी. की दूरी पर पशु स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु जयपुर व बीकानेर संभागों में कार्यरत संस्थाओं का पुनर्गठन कर 749 उप केन्द्र स्थापित किए गए हैं। राज्य के दक्षिणी एवं पूर्वी भागों के 12 ज़िलों की 40 पंचायत समितियों में "गोपाल" योजना निरन्तर जारी है। राजस्थान डेयरी फ़ेडरेशन के सहयोग से जयपुर, भरतपुर, अलवर व दौसा ज़िलों में पशु विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अजमेर ज़िले के रामसर ग्राम में बकरियों के विकास व उनके लिए चारा उत्पादन हेतु एक बकरी प्रजनन केन्द्र कार्यरत है।

शूकर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अलवर ज़िले में "विदेशी नस्ल के शूकर पालन फार्म" स्थापित किया गया है। राज्य कुक्कुट फ़ार्म जयपुर में कुक्कुट विकास हेतु एक नवीन पद्धति "केज सिस्टम" विकसित की जा रही है। राज्य में 6 कुक्कुट फ़ार्म एवं 16 सघन कुक्कुट विकास केन्द्र कार्यरत हैं।

5.6 **दुग्ध विकास**

राष्ट्रीय दुग्ध विकास मन्डल के सहयोग से राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड सहकारिता के आधार पर राज्य में दुग्ध विकास कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। यह कार्यक्रम मूल रूप से ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को शहरी उपभोक्ताओं से सामंजस्य स्थापित करने के लिए चलाया जा रहा है दुग्ध संघ की गतिविधियाँ किसानों के द्वारा स्वयं संचालित की जाती है, और दुग्ध प्रबन्ध सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं को अच्छी क़िस्म का दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराना, पशु स्वास्थ्य रख रखाव एवं दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाया जाना सुनिश्चित करना है। दिसम्बर 1994 के अन्त में, राज्य में लगभग 9 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रक्रिया क्षमता के 10 संयंत्र एवं 4 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध चिलिंग (शीतल) क्षमता के 24 संयंत्र कार्यरत थे।

राज्य के समस्त ज़िलों में 16 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के माध्यम से एकीकृत दुग्ध विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1994-95 में (दिसम्बर, 1994 तक) 84 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ गठित की गई तथा 212 बन्द समितियों को पुनर्जीवित किया गया। दिसम्बर 1994 के अन्त तक कुल कार्यशील समितियों की संख्या 2862 तथा इनकी कुल सदस्य संख्या 361654 थी। वर्ष 1994-95 (अप्रैल, 1994 से दिसम्बर, 1994) में औसतन 3.15 लाख लीटर दूध प्रतिदिन एकत्रित किया गया।

राज्य में 4 पशु आहार संयंत्रों के माध्यम से दुग्ध संघ पशुओं को पोषक आहार उपलब्ध करवा रहा है। वर्ष 1994-95 में (दिसम्बर, 1994 तक) इन संयंत्रों द्वारा 40507 टन पशु आहार का उत्पादन तथा 40505 टन पशु आहार का विपणन किया गया।

5.7 **भेड़ पालन**

राज्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भेड़ पालन तेज़ी से एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है क्योंकि यह व्यवसाय जनसंख्या के बहुत बड़े भाग विशेषतः समाज के कमज़ोर वर्गों को अतिरिक्त आय एवं रोज़गार के अवसर प्रदान करता है। राज्य के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भागों में कमज़ोर वर्गों के लिए भेड़ पालन उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। वर्ष 1992 की पशु गणना के अनुसार राज्य में 121.68 लाख(प्रावधानिक) भेड़ें थी, जो कि देश में भेड़ों की कुल संख्या का लगभग 25 प्रतिशत है। राज्य में 2 लाख से अधिक परिवार ऊन उत्पादन व्यवसाय में लगे हुए हैं तथा राज्य में लगभग 170 लाख कि.ग्रा. ऊन का उत्पादन तथा 30 लाख से अधिक भेड़ व बकरियों का मांस प्राप्त किया जाता है।

भेड़ों में बीमारियों की रोक थाम हेतु दवाइयों की खुराकें, छिड़काव एवं टीका करण आदि कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं।

बीमारियों की रोकथाम के उपायों के अतिरिक्त अच्छी क़िस्म के ऊन उत्पादन के लिए उन्नत भेड़ें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चयनित एवं वर्णसंकर नस्लों के प्रजनन के कार्यक्रम भी राज्य में चलाए जा रहे हैं।

5.8 मत्स्य पालन

राज्य में मत्स्य विकास हेतु लगभग 3.30 लाख हैक्टेयर सतही जल क्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से 1.20 लाख हैक्टेयर वृहद एवं मध्यम जलाशयों, 1.80 लाख हैक्टेयर छोटे तालाबों एवं 0.30 लाख हैक्टेयर नदियों/नहरों के रूप में हैं। वार्षिक लक्ष्य 12000 टन के विरुद्ध दिसम्बर 1994 तक 12220 टन मत्स्य का उत्पादन हुआ।

राज्य में 15 मत्स्य फ़ार्म विकास अभिकरण कार्यरत हैं, इनमें से प्रत्येक को एक हैक्टेयर जल क्षेत्र आवन्टित किया गया है। इन अभिकरणों द्वारा मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वर्ष 1993-94 तक 6262 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा उन्हें 3827 हैक्टेयर जल क्षेत्र आवन्टित किया गया। वर्ष 1994-95 में (दिसम्बर, 1994 तक) 270 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा कर उन्हें 150 हैक्टेयर जल क्षेत्र आवन्टित किया गया।

5.9 वन

पर्यावरण संरक्षण तथा जैविक वनस्पति संतुलन बनाए रखने के लिए वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।

राजस्थान देश का द्वितीय बड़ा प्रदेश है किन्तु राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 9 प्रतिशत वन के रूप में वर्गीकृत है जब कि राष्ट्रीय वन नीति में कुल क्षेत्रफल के 33.33 प्रतिशत क्षेत्र में वनों की सिफ़ारिश की गई है। इसलिए वनों का अनवरत विकास राज्य के लिए एक विचारणीय पहलू है।

पौधारोपण, वन एवं चारागाह विकास के कार्य को गति प्रदान करने के दृष्टिकोण से विशिष्ट परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। विश्व बैंक की सहायता से 19 गैर मरुस्थलीय ज़िलों में "राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना" क्रियान्वित की जा रही है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में ओ. ई.सी. एफ. (जापान) सहायता से वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास परियोजना चलाई जा रही है। ओ.ई.सी. एफ. जापान से सहायता प्राप्त अरावली वृक्षारोपण परियोजना चालू वर्ष में 10 ज़िलों में प्रारम्भ की गई है। राज्य योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन प्रदान करने के कार्यक्रमों के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास के कार्य भी वर्ष 1994-95 में क्रियान्वित किए गए हैं। वर्ष 1994-95 में (जनवरी, 1995 तक) 87206 हैक्टेयर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर पौधरोपण का कार्य संपादित किया गया तथा 336 लाख पौधे वितरित किए गए। स्थानीय व्यक्तियों को वनों के रख रखाव एवं प्रबन्ध में सम्मिलित करने हेतु ग्राम स्तर पर 869 वन संरक्षण एवं प्रबन्ध समितियाँ गठित की गई हैं।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वानिकी कार्य में कार्यरत श्रमिकों के लिए खाद्य इकाइयाँ वितरित की जाती हैं। एक खाद्य इकाई के अन्तर्गत 2 कि.ग्रा. गेहूँ, 200 ग्राम दालें एवं 80 मि.लि.वनस्पति तेल होता है। एक खाद्य इकाई प्रतिदिन 5 सदस्यों वाले श्रमिक परिवार को वितरित की जाती है। एक खाद्य इकाई की एवज में एक श्रमिक की दैनिक मज़दूरी में से 7 रुपये की कटौती की जाती है। वर्ष 1994-95 में (दिसम्बर,1994 तक) 20.86 लाख खाद्य इकाइयाँ वितरित की गई।

वर्ष 1989-90 के अन्त तक राज्य में कुल 31753.57 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र था जिसमें से 12272.71 वर्ग कि.मी. आरक्षित वन, 16116.97 वर्ग कि.मी. संरक्षित वन एवं 3363.89 वर्ग कि.मी. अवर्गीकृत वन क्षेत्र था।

5.10 **वन्य जीव संरक्षण**

वन्य जीव संपदा की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध राज्य है। आकार व भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य विभिन्न दुर्लभ पशु व पक्षियों की संरक्षण स्थली है जैसे भारतीय बस्टर्ड, चीता, तेंदुआ, चिंकारा, बारासिंघा, भेड़िया, सारस, बत्तख आदि।

राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान, 23 अभयारण्य तथा 33 निषेध क्षेत्र हैं। अभी तक राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों एवं निषेध क्षेत्रों के सुधार एवं विकास पर विशेष बल दिया गया था, किन्तु आठवीं पंचवर्षीय योजना में वन्य जीव संरक्षण और इसके प्रबन्धन को भी विशेष महत्व दिया गया है।

*****

6. आधारभूत ढाँचागत विकास

6.1 विद्युत

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल विभिन्न पन बिजली योजनाओं की खोज एवं क्रियान्विति तथा विद्युत संवहन एवं वितरण के कार्यों में संलग्न है । कोटा ताप बिजलीघर, माही जल परियोजना, व्यास, चम्बल एवं सतपुड़ा परियोजना राज्य में विद्युत आपूर्ति के प्रमुख स्त्रोत है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र के राजस्थान अणु शक्ति, सिंगरोली ताप विद्युत परियोजना, रिहन्द, अन्ता, औरैया, नरौरा एवं दादरी गैस, उंचाहार ताप विद्युत एवं टनकपुर परियोजना राज्य की विद्युत आपूर्ति में योगदान करते है। वर्ष 1993-94 के अंत में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 2985 मेगावॉट थी। वर्ष 1994-95 में (फ़रवरी 95 तक) इसमें 3.80 मेगावॉट उत्पादन की क्षमता को जोड़ा गया। कोटा तापीय ऊर्जा स्टेशन की दो इकाइयों के पुराने हो जाने के कारण विद्युत उत्पादन में कमी हुई है अतः संलग्न अन्य संयन्त्रो से ऊर्जा क्रय करने के प्रयास किए गए एवं इस प्रकार ऊर्जा क्रय में वृद्धि हुई। वर्ष 1993-94 में 7888 मिलियन यूनिट की तुलना मे वर्ष 1994-95 में 6914 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन होने की संभावना है।

विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में विद्युत उत्पादन क्रय एवं उपभोग की गत तीन वर्षो की स्थिति निम्न प्रकार है।

(मि०यू०में)

मद	वर्ष		
	1992-93	1993-94	1994-95 (प्रावद्यानिक)
1	2	3	4
1- उत्पादन (शुद्ध)	7961.650	7888.344	6913.880
2- क्रय	6704.853	7486.512	8415.270
3- योग(1+2)	14666.503	15374.856	15329.150
4- उपभोग			
(अ) अन्य राज्यों/ व्यवस्थाओं	501.548	272.636	500.000
(ब) सामान्य व्यवस्था (उपभोक्ता एवं शक्ति)	138.444	138.408	140.000
(स) राजस्थान के उपभोक्ता	10528.862	11091.430	11533.380
(1) घरेलू	1345.647	1545.331	1495.880
(2) अ-घरेलू	483.166	531.412	530.540
(3) औद्योगिक	4361.465	4378.917	4861.320
(4) कृषि	3361.306	3653.031	3596.110
(5) सार्वजनिक जलप्रदाय	450.511	465.695	510.930
(6) सार्वजनिक प्रभाग	48.261	54.322	50.750
(7) अन्य	478.506	462.722	487.850

राज्य लगातार विद्युत की कमी/कटौती से ग्रस्त है, तथा विद्युत उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर कृषि/औद्योगिक उपभोग में अनिवार्य कटौती की जाती है। फिर भी कृषि कार्यो हेतु औसतन आठ घन्टे प्रतिदिन विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है।

वर्ष 1993-94 तक 30004 ग्रामों (राज्य के कुल ग्रामों का 80.02 प्रतिशत) का विद्युतीकरण किया जा चुका था । वर्ष 1994-95 में (फ़रवरी 1995 तक) इसके के अतिरिक्त 650 ग्राम विद्युतीकरण किए जा चुके हैं। इस प्रकार अब तक कुल 30654 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। वर्ष 1994-95 में (फ़रवरी 95 तक) 24128 कुओं का विद्युतीकरण किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 4.78 लाख कुओं को ऊर्जाकृत किया जा चुका है।

वर्ष 1993-94 में विद्युत उपभोग 11091.430 मिलियन यूनिट की तुलना में वर्ष 1994-95 में लगभग 11533.38 मिलियन यूनिट होने की संभावना है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 1994-95 में लगभग 263 यूनिट होने का अनुमान है, जबकि गत वित्तीय वर्ष में यह 236 यूनिट था।

6.2 **गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत-रैडा**

राज्य में सौर एवं वायु ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावनाएँ है। राजस्थान एक रेगिस्तानी क्षेत्रों की बहुलता वाला प्रदेश है जहाँ सूर्य के किरणों का प्रभाव अधिक रहता है। ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की अच्छी संभावनाएँ है। ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु, सौर ऊर्जा के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य हुए है। इसके अतिरिक्त सौर पम्पो, सामुदायिक टेलिविज़न सैटों का प्रसार, एस.पी.बी. लाइट के विस्तार हेतु भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। 35 मेगावॉट सोलर तापीय ऊर्जा परियोजना का संयन्त्र मथानिया में लगाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसको प्राथमिकता के आधार पर स्थापित करने हेतु विश्व बैंक से सिफ़ारिश की गई है।

गर्मी के महीनों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु ऊर्जा की अधिकता रहती है। किन्तु पूरे वर्ष औसतन वायु गति के अनुसार आर्थिक रूप से वायु ऊर्जा उत्पादन व्यावहारिक नहीं है क्योंकि वर्ष भर वायु के तेज़ गति के कारण झंझावातों की आशंका को ध्यान में रखते हुए अरावली पहाड़ियों में वायु नियन्त्रण स्टेशन स्थापित किए गए है। वर्ष 1994 में पवन चक्की लगाने हेतु, पानी को ऊपर ले जानें के लिए रेडा द्वारा एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

6.3 **परिवहन व संचार**

- **सड़कें**

राजस्थान भारत में उन कुछ राज्यों में से एक हैं जहाँ औसत सड़क लम्बाई राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। वर्ष 1994-95 में सड़कों की लम्बाई प्रति 100 वर्ग कि०मी० पर 62.0 कि०मी० के राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य में मात्र 32.5 कि०मी० ही है। वर्ष 1993-94 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नियंत्रित की जाने वाली सड़कों की लम्बाई 63078 कि०मी० थी जो वर्ष 1994-95 में बढ़कर 64588 कि०मी० हो गई।

सड़कें क्षेत्र विशेष के विकास की सूचक होती हैं अतः राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रारम्भ से ही इस ओर समुचित ध्यान दिया जा रहा है।

गत तीन वर्षो में सड़क लम्बाई की श्रेणी वार स्थिति निम्न प्रकार है।

(किलो मीटर में)

सड़कों के प्रकार	1992-93			1993-94		
	पक्की	कच्ची	योग	पक्की	कच्ची	योग
1	2	3	4	5	6	7
1-राष्ट्रीय राजमार्ग	2846	-	2846	2846	-	2846
2-राज्य राजमार्ग	7111	40	7151	8647	73	8720
3-मुख्य जिला सड़कें	3487	151	3638	3051	161	3212
4-अन्य जिला सड़कें	12960	2107	15067	12412	1982	14394
5-ग्रामीण सड़कें	22395	8184	30579	23338	8329	31667
6-सीमावर्ती सड़कें	2239	-	2239	2239	-	2239
योग	51038	10482	61520	52533	10545	63078

सड़कों के प्रकार	1994-95		
	पक्की	कच्ची	योग
1	8	9	10
1-राष्ट्रीय राजमार्ग	2846	-	2846
2-राज्य राजमार्ग	8657	63	8720
3-मुख्य जिला सड़कें	3091	121	3212
4-अन्य जिला सड़कें	13317	1882	15194
5-ग्रामीण सड़कें	24198	8179	32377
6-सीमावर्ती सड़कें	2239	-	2239
योग	54343	10245	64588

सड़क मार्गो के समुचित विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा हाल ही में "सड़क नीति" की घोषणा की गई है। जिसकी मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार है।

1- 1971 की जनसंख्या अनुसार 1000 या उससे अधिक आबादी वाले ग्रामों को अष्टम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बी०टी० सड़कों द्वारा जोड़ना ।

2- 1981 एवं 1991 की जनसंख्या के अनुसार 1000 या अधिक आबादी वाले ग्रामों को नवम पंचवर्षीय योजना के अंत तक सड़कों से जोड़ना । नवम पंचवर्षीय योजना के अंत तक जनसंख्या को आधार नहीं मानते हुए सभी पंचायत मुख्यालयों को बी.टी. सड़कों से जोड़ना।

3- सभी ऐसे ग्राम जिनकी जनसंख्या 750 या अधिक है एवं जनजाति/मरुस्थल क्षेत्र में आते है को नवम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बी.टी. सड़कों से जोड़ना।

4- मुख्य शहरी केन्द्रो पर बाईपास निर्माण।

5- राज्य उच्च मार्ग (हाईवें) एवं जिला मार्गों को चौड़ा करना।

6- राज्य उच्च मार्ग पर अन्तर्राज्यीय सड़को, मिसिंग लिंक्स एवं सी०डी० वर्क्स का निर्माण करना ।

उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे जवाहर रोज़गार योजना, रोज़गार गारन्टी योजना, तीस ज़िले तीस काम आदि के स्त्रोतों का उपयोग भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्य पुलों, सुरंगों एवं बाईपास आदि के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं एवं निजी विनियोजकों का भी सहयोग लिया जावेगा। इस कार्य में लगी पूँजी की वसूली टॉल टैक्स के माध्यम से की जावेगी। विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत चार राज्य उच्च मार्गो को चौड़ा करने एवं उनका दर्जा बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है।

- <u>सड़क परिवहन</u>

वर्ष 1993-94 में कुल 14.09 लाख मोटर वाहनों की तुलना में वर्ष 1994-95 में मोटर वाहनों की संख्या लगभग 15.47 लाख हो गई। इस प्रकार वर्ष 1994-95 में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 9.79 प्रतिशत की वृद्धि रही।

विगत तीन वर्षों (1992 से 1994 तक) में राज्य के परिवहन विभाग में पंजीकृत विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैं।

(संख्या)

परिवहन साधन का प्रकार	वर्ष में वाहनों की संचयी संख्या			वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में प्रतिशत वृद्धि
	1992	1993	1994	
1	2	3	4	5
1- मोटर रिक्शा	90	90	90	-
2- आटो/मोटर साइकिल एवं स्कूटर	837840	920437	1020054	10.82
3- ऑटो रिक्शा	19504	20982	23168	10.42
4- टेम्पो				
(1) सामान ढोनेवाले	936	1121	1371	22.30
(2) यात्री वाहन	3679	3947	4182	5.95

1	2	3	4	5
5- कार एवं स्टेशन वैगन	59992	636777	68881	8.00
6- जीप	45783	50512	55822	10.51
7- ट्रैक्टर	166401	182156	197386	8.36
8- ट्रेलर	40878	42208	42701	1.17
9- टैक्सी	10717	11446	12171	6.33
10- बस व मिनी बस	26601	28450	30870	8.51
11- ट्रक व अन्य सामान ढोनेवाले वाहन	77045	81331	87232	7.26
12- अन्य	2567	2604	2667	2.42
योगः	1292033	1409061	1546595	9.76

वर्ष 1994-95 में (दिसम्बर, 1994 तक) 9122 सामान ढोने वाले वाहन, 1325 स्टेज कैरिजेज़ एवं 2969 अनुबंधित वाहनों को स्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किए गए। चालू वर्ष में 6167 कि०मी० क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 87 नए मार्ग खोले गए। इसके अतिरिक्त राज्य में प्रदूषण नियंत्रण हेतु 32 स्मोक मीटर एवं 22 गैस एनेलाइज़र दिसम्बर, 1994 तक प्रयुक्त किए गए है।

*****

7. सामाजिक आधारभूत विकास

7.1 मानव संसाधन विकास

राजस्थान शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य है। महिला साक्षरता की स्थिति राज्य में शोचनीय है। शहरी एवं ग्रामीण तथा पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में काफ़ी अन्तर है। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार को छोड़ कर राज्य में 38.55 प्रतिशत साक्षरता का स्तर अन्य सभी राज्यों से कम है। 39.29 प्रतिशत अखिल भारतीय महिला साक्षरता की तुलना में राजस्थान में 20.44 प्रतिशत महिला साक्षरता है।

राज्य में शिक्षा के विकास के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें महाविद्यालय स्तर तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क व्यावसायिक एवं प्रावैधिक शिक्षा तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने को निरुत्साहित करना सम्मिलित है।

14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण राज्य का मुख्य लक्ष्य है। इसके महत्व को स्वीकारते हुए प्राथमिक शिक्षा को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

राज्य में वर्ष 1994-95 में कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों का विवरण निम्नानुसार है :-

(संख्या में)

संस्थाएँ	सरकारी	गैर सरकारी	योग
1- प्राथमिक विद्यालय	31397	3213	34610
2- उच्च प्राथमिक विद्यालय	9152	1919	11071
3- माध्यमिक विद्यालय	2854	360	3214
4- उच्च माध्यमिक विद्यालय	967	290	1257

प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों के प्रवेश में वृद्धि एवं उन्हें अध्ययन रत बनाए रखने हेतु राज्य में वर्ष 1994-95 में पहली बार लड़कियों के लिए कक्षा एक से आठवीं तक तथा लड़कों के लिए कक्षा एक से पाँच तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 10.22 लाख रुपये के मूल्य की पुस्तकें वितरित की गई और 45.68 लाख विद्यार्थियों को (15.36 लाख बालिकाओं को सम्मिलित करते हुए) लाभान्वित किया गया।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए " सीडा" के सहयोग से राज्य के 25 विकास खण्डों में लोक जुम्बिश परियोजना क्रियान्वित की जा रही हैं। "सीडा" के सहयोग से "शिक्षा कर्मी योजना" प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत गाँवों के शिक्षित युवकों, पुरुष एवं महिला दोनों को प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वयं के गाँवों में अध्यापक के रूप में रोज़गार दिया गया है। ये शिक्षा कर्मी दिन के समय स्कूल चलाते हैं और उन बच्चों के लिए जो दिन के समय अपनी रोज़ी के लिए व्यस्त हैं, रात्रि पाली भी चलाते हैं। इस योजना के प्रभावशाली क्रियान्विति हेतु एक स्वशासित बोर्ड का गठन किया गया।

शिक्षा कर्मी योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 1141 स्कूल एवं 2452 रात्रि पाली स्कूल 26 ज़िलों में कार्यरत हैं, जिनमें 2751 शिक्षक कर्मियों को लगाया गया, 84162 बच्चे दिन के समय के स्कूलों के माध्यम से तथा 24528 बच्चे रात्रि पाली स्कूलों के माध्यम से लाभान्वित किए गए।

सन 2000 तक सबको शिक्षा और पूर्ण साक्षरता को ध्यान में रखते हुए आलोच्य वर्ष में शिक्षा के उद्व्यय को काफ़ी बढ़ाया गया है। वर्ष 1994-95 में शिक्षा पर 223.45 करोड़ रुपये का उद्व्यय रखा गया जो कि वर्ष 1993-94 में 125 करोड़ रुपये था। इस प्रकार मौलिक शिक्षा के उद्व्यय को 119 प्रतिशत बढ़ाया गया तथा पूर्ण साक्षरता के उद्व्यय को 105 प्रतिशत बढ़ाया गया। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में 43.66 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित महिलाओं की सहायता से "सरस्वती योजना" प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 1994-95 में पाँच ज़िलों में 100 सरस्वती शालाएँ खोले जाने का लक्ष्य रखा गया।

प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं। वर्ष 1990-91 में प्रारम्भ किया गया पूर्ण साक्षरता अभियान, वर्ष 1994-95 में भी जारी रहा। अजमेर एवं डूंगरपुर ज़िले पहले से ही पूर्ण साक्षर घोषित किए जा चुके हैं। भरतपुर, सीकर, पाली, टोंक, बाराँ, उदयपुर, अलवर, राजसमन्द, झुंझुनू, बूँदी, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा एवं चित्तोड़गढ़ ज़िलों मे पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम लागू किया गया है।

6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिए जो अपनी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण औपचारिक विद्यालयों में जाने में असमर्थ हैं, को प्राथमिक शिक्षा देने हेतु राज्य में 10600 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1994 में दिसम्बर तक 3200 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्वीकृत किए गए।

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु 37 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों सहित 71 सरकारी महाविद्यालय राज्य में संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 65 सहायता प्राप्त एवं 37 गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालय भी उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 1994-95 में (भरतपुर एवं गंगानगर) में दो महिला स्नातक महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत किए गए तथा राजकीय महाविद्यालयों में 14 नए विषय प्रारम्भ किए गए।

प्रावैधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पोलीटैक्नीक के माध्यम से तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

7.2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य छूत एवं अन्य बीमारियों पर नियंत्रण व उनका उन्मूलन करना तथा राज्य के लोगों को उपचार एवं बचाव से सम्बन्धित सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

वर्ष 1994-95 (दिसम्बर 1994) के दौरान संचालित एलोपैथिक चिकित्सा संस्थाओं से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं० संस्थाएँ	संख्या
1- चिकित्सालय	218
2- औषधालय	273
3- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/	1507
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	246
4- मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	118
5- उप केन्द्र	8000
6- रोगी शैय्याऐं	35663

राज्य में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर (1991 की जनगणना) 81 शैय्याऐं (दिसम्बर, 1994) तक उपलब्ध हैं।

"मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम" के अन्तर्गत दिसम्बर,1994 तक 4400599 रक्त पट्टिकाओं की जाँच के लक्ष्यों के विरुद्ध 4525430 रक्त पट्टिकाओं को एकत्रित कर जाँच की गई।

शिशु मृत्यु दर पर अंकुश रखने एवं गम्भीर रोगों से रक्षा हेतु राज्य में एक सघन बाल प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। वर्ष 1992-93 में प्रारम्भ किया गया "सुरक्षित बाल जीवन एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम " वर्ष 1994-95 में भी जारी रहा।

राष्ट्रीय "एड्स कन्ट्रोल कार्यक्रम" के अन्तर्गत " एड्स सैल " स्थापित किया गया है तथा राज्य के पाँच चिकित्सा महाविद्यालयों में "रक्त जाँच केन्द्र" स्थापित किए गए हैं।

अंधता निवारण राष्ट्रीय कार्यक्रम जो कि वर्ष 1977-78 में प्रारम्भ किया गया था, उसको वर्ष 1994-95 में विश्व बैंक की सहायता से सशक्त करते हुए मोतियाबिंद अंधता निवारण परियोजना के रूप में आगे सात वर्ष के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना अवधि के लिए 65.24 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

अन्य चिकित्सा संस्थाओं में दिसम्बर, 1994 तक राज्य में 3495 आयुर्वेदिक, 108 होम्योपैथिक , 78 यूनानी एवं 4 प्राकृतिक अस्पताल/औषधालय कार्यरत हैं। उसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक विभाग के अधीन अजमेर में 200 शैय्याओं की मोबाइल सर्जिकल इकाई भी कार्यरत हैं।

अजमेर, जोधपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में 4 आयुर्वेदिक रसायन शालाएँ संचालित की जा रही हैं। जहाँ औषधियों का निर्माण कर उन्हें आयुर्वेदिक, यूनानी एवं प्राकृतिक अस्पतालों/औषधालयों को उपलब्ध कराया जाता है।

7.3 परिवार कल्याण

"छोटे परिवार" के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण राज्य में सघन परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 1994-95 मे 2.50 लाख नसबन्दी के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर 1994 तक 1.18 लाख नसबन्दी ऑपरेशन किए गए। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा लागू की गई सामाजिक सुरक्षा नेट स्कीम राज्य के 23 ज़िलों मे क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1994-95 में नई " भारतीय जनसंख्या परियोजना IX" भी राज्य में सात वर्ष के लिए प्रारम्भ की गई है। इस परियोजनान्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं में सुधार हेतु 108 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन में राज्य के पश्चिमी ज़िलों को विशेष महत्व दिया गया है।

7.4 जल आपूर्ति

भौगोलिक विषमता, भूजल तथा सतही जल की सीमित उपलब्धता के कारण राज्य में सुरक्षित पेयजल की जटिल समस्या है। राज्य सरकार जनता को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दे रही है।

वर्ष 1994-95 में राज्य में पेयजल आपूर्ति हेतु राज्य योजनान्तर्गत 203.24 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें से 130.59 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों एवं 72.65 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। दिसम्बर, 1994 तक जल आपूर्ति के विभिन्न साधनों जैसे ट्यूबवेल, हैन्डपम्प आदि तथा परम्परागत जल स्त्रोतों एवं जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से 36629 गाँवों को सुरक्षित पेयजल योजना के अन्तर्गत लिया गया है।

वर्ष 1994-95 में 1450 गाँवों , 500 ढ़ाणियों एवं 1000 अनु० जाति/अनु० जनजाति बस्तियों में अतिरिक्त रूप से सुरक्षित पेयजल सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है।

7.5 आवास

नगरों एवं कस्बों की शहरी जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। आवास जैसी आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियोजित आर्थिक विकास प्रक्रिया में सतत प्रयास किए गए। आवासीय समस्या के समाधान हेतु राज्य के पिछड़े वर्गों को अच्छे एवं सस्ते मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 24 फ़रवरी 1970 को राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना हुई। राजस्थान आवासन मण्डल की गतिविधियों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

क्र.सं.	मद	इकाई	उपलब्धि
1-	63 शहरों/कस्बों में आवेदन पँजीकरण	संख्या	207318
2-	दिसम्बर 1994 तक निर्माण स्थिति	" "	137466
3-	पूर्ण निर्मित मकान	" "	129914
4-	निर्मित मकानों का आवंटन	" "	125244
5-	मकानों का कब्जा	" "	107829
6-	1994-95 का निर्धारित लक्ष्य	" "	11000
7-	दिसम्बर 1994 तक निर्माणाधीन मकान	" "	9698

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भवन निर्माण की नई तकनीकी जैसे सीमेंट ब्लाक्स का उपयोग, प्री कास्टेड रूफ सीलिंग आदि अपनाई गई है। भारत सरकार के सहयोग से आवास विकास संस्थान का गठन किया गया है। इस संस्थान द्वारा आधुनिक तकनीक टर्नल शटरिंग पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। जिससे निर्माण लागत/समय में कमी आई है। इसके अतिरिक्त ढाँचे वाले आवास आवंटन की योजना भी प्रारम्भ की गई है। मकानों के पँजीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए भी अभियान चलाया गया है।

7.6 पिछड़ी जातियों का कल्याण एवं समाज कल्याण

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए राज्य का समाज कल्याण विभाग विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है। इसके अतिरिक्त बच्चों, महिलाओं एवं अपंग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार हेतु भी अनेक कार्यक्रम राज्य में क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

- अनुसूचित जाति कल्याण

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की आर्थिक उन्नति करने हेतु 28 मार्च 1980 को राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की स्थापना की गई। अब इसे राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि० के रूप में में पुनर्गठित किया गया है। निगम की स्थापना से अब तक 1047710 व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं।

- अनुसूचित जनजाति कल्याण

संविधान के अनुच्छेद 46 में सरकार को अनुसूचित जाति/अनु० जन जातियों के आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों के उत्थान हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजाति क्षेत्र एवं जनजाति परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु मूल रूप रेखा तय की गई थी। क्षेत्रीय आधार पर जनजाति बहुल क्षेत्रों की मूल आधारभूत सुविधाएँ वर्ष 1974-75 में जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना बनाते समय निर्धारित की गई थी। जनजातियों में मुख्य रूप से भील,मीणा, गरासिया, डामोर एवं कथोडी राजस्थान में निवास करते हैं। घोषित उपयोजना में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तोड़गढ़ एवं सिरोही की 23 पंचायतें हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जनजाति जनसंख्या 54.75 लाख है, जिसमें से 24.01 लाख व्यक्ति जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निवास करते हैं।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजातियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान से सम्बन्धित विभिन्न विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। अनुसूचित जनजाति के विकास एवं कल्याण हेतु वर्ष 1994-95 में कुल 33312.98 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें से 21244.17 लाख रुपये राज्य योजना, 1336.30 लाख रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता 1919.30 लाख रुपये संस्थागत वित्त एवं 8813.21 लाख रुपये केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए हैं।

- महिला एवं बाल कल्याण

वर्तमान में 178 बाल विकास योजनाएँ हैं जिनमें से 139 ग्रामीण क्षेत्रों में 11 शहरी क्षेत्रों में और 28 जनजाति क्षेत्रों में है। राज्य की 237 पंचायत समितियों में से 31 ज़िलों की 167 पंचायत समितियों में इन सेवाओं का विस्तार किया जा चुका है। वर्ष 1994-95 पोषाहार कार्य क्रम के अन्तर्गत 14.80 लाख बच्चों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया जाना है।

महिलाओं के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ जैसे महिला मंडल, किशोर बालिका योजना एवं ढाकरा आदि संचालित की जा रही हैं

*****

8. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य (1) अधिक रोज़गार (2) ग्रामीणों के मध्य आय का समान वितरण एवं ग़रीबी उन्मूलन और (3) अच्छे सामाजिक व आर्थिक जीवन यापन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विनियोजन है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं/कार्यक्रम की क्रियान्विति जारी रही।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य अतिरिक्त रोज़गार के अवसर जुटाना एवं चयनित ग़रीब परिवारों का आर्थिक स्तर बढ़ाना है। वर्ष 1994-95 के दौरान 1.08 लाख परिवारों के लक्ष्य के विरुद्ध फ़रवरी, 1995 तक 0.94 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। ट्राइसम योजना के अन्तर्गत जो कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ही भाग है, ग्रामीण बेरोज़गार युवकों को स्वरोज़गार एवं मज़दूरी रोज़गार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 9000 युवकों को प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरुद्ध फ़रवरी, 1995 तक 6865 युवकों को प्रशिक्षित किया गया। 2093 प्रशिक्षित युवकों को स्वरोज़गार एवं मज़दूरी रोज़गार दिया गया।

जवाहर रोज़गार योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गार एवं अर्ध बेरोज़गार पुरुष एवं स्त्री दोनों हेतु अतिरिक्त रोज़गार के अवसर सृजन करना है। वर्ष 1994-95 के दौरान 385.21 लाख मानव दिवस रोज़गार सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध माह फ़रवरी, 1995 तक 306.27 लाख मानव दिवस रोज़गार का सृजन किया गया। फ़रवरी, 1995 तक इन्दिरा आवास योजना में 22258 मकान निर्मित कराए गए एवं जीवन धारा योजना में 2527 कुओं का निर्माण कराया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में जनोपयोगी सम्पदा के निर्माण के माध्यम से अतिरिक्त रोज़गार सृजन हेतु 1 जनवरी 1991 से अपना गाँव अपना काम योजना लागू की गई थी। वर्ष 1994-95 के दौरान फ़रवरी, 1995 तक 14.28 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। फ़रवरी, 1995 तक 1272 कार्य पूर्ण किए गए हैं और 1572 कार्य प्रगति पर हैं। संशोधित वित्तीय पद्धति के अनुसार 50 प्रतिशत जन अंशदान/पंचायतें (जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत जन अंशदान) मज़दूरी और सामग्री के रूप में होगा और 50 प्रतिशत अंशदान राज्य का जवाहर रोज़गार योजना/ अन्य योजना कोष के रूप में होगा।

मरु विकास कार्यक्रम (जो कि शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना है) के अन्तर्गत राज्य के 11 रेगिस्तानी ज़िलों के 85 खण्ड सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 के लिए 64.50 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। राज्य की 1994-95 की योजना में सूखा सम्भावित कार्यक्रम हेतु 11.33 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

बायो गैस कार्यक्रम के अन्तर्गत फ़रवरी, 1995 तक 1.72 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं और 5000 संयंत्र के लक्ष्य के विरुद्ध 3947 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।

स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को महत्व देने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि योजना निधियों में से कुछ राशि ज़िलों को हस्तान्तरित कर उनके द्वारा अति आवश्यक कार्यों के निष्पादन हेतु दी जावे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्बन्ध राशि योजना (अनटाइड फन्ड) राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत फ़रवरी, 1995 तक 489 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

स्वयं ज़िलों को प्राप्त सीमित स्थानीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के विचार से राज्य में वर्ष 1991-92 में "तीस जिला तीस काम" योजना शुरू की गई। इस योजना अन्तर्गत में ज़िले में विभिन्न प्रवृत्तियों के विकास का क्षेत्र व प्राप्त संसाधन के आधार पर प्रति वर्ष एक प्रवृत्ति पर विनियोजन किया जाता है। माह फ़रवरी, 1995 तक इस योजना के अन्तर्गत 619 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

मेवात विकास के अन्तर्गत अलवर तथा भरतपुर ज़िलो के मेव क्षेत्र में विकास हेतु दो करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। मेवात क्षेत्र में सड़क निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्र में समाज के ग़रीब वर्गों को रोज़गार उपलब्ध करवाने के विचार से रोज़गार सुनिश्चित योजना की घोषणा की गई। वर्ष 1994-95 हेतु 122 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। फ़रवरी, 1995 तक 82.60 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। यह योजना 172 पंचायत समितियों में क्रियान्वित की जा रही है।

ग़रीबी उन्मूलन एवं विकास को गति देने के उद्देश्य से एक वृहद परियोजना का एप्रोच पेपर तैयार किया जा कर विश्व बैंक सहायता हेतु स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत ज़िलों को 15 से 20 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रति वर्ष चार से पाँच वर्ष तक उपलब्ध करवाई जावेगी। प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर सर्वप्रथम राजसमंद ज़िले का चयन हुआ है। इसी प्रकार विकास हेतु 200 करोड़ रुपये की लूनी बेसिन परियोजना का एप्रोच पेपर के. एफ. डब्ल्यू. जर्मन मिशन को वित्तीय सहायता हेतु भिजवाया गया। दस्यु पीड़ित एवं डांग क्षेत्र के विकास हेतु एक विशेष योजना तैयार कर स्वीडिश इंटर नेशनल डवलपमेंट एजेन्सी (एस. आई. डी. ए.) को वित्तीय सहायता हेतु भिजवाई गई है। बाराँ ज़िले के सहारिया जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए एक परियोजना भारत सरकार को भिजवाई गई है और जिसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतों के लिए 1111 लाख रुपयों का तथा ग्रामीण आवासन हेतु 468 लाख रुपये वर्ष 1994-95 में उपलब्ध कराए गए।

ग्रामीण ग़रीब परिवारों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1994 तक 29021 भूखण्डों का आवंटन हो चुका है।

*****

9. अन्य कार्यक्रम

9.1 बीस सूत्री कार्यक्रम

बीस सूत्रीय कार्यक्रम आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन एवं ग़रीबी के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक कारगर दस्तावेज़ हैं तथा इस कार्यक्रम ने विकास को द्रुत गति प्रदान की है। सम्पूर्ण विकास की योजना अन्तर्गत इस कार्यक्रम द्वारा समग्र क्षेत्रों के विकास पर विशेष ज़ोर दिया गया है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिक उत्पादकता एवं असमानता को कम करना है।

इस कार्यक्रम में ग़रीबी हटाने, जीवन स्तर सुधारने, वातावरण एवं परिस्थितियों का विकास एवं कमज़ोर वर्ग की आय को कम होने से बचाने के कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं।

राज्य सरकार ने इस बहु आयामी कार्यक्रम के कुशल क्रियान्वयन का विशेष तरीक़ा अपनाया है जिसमें योजना कोष का आवंटन, भौतिक लक्ष्यों के परिणाम तथा कई स्तरों पर जवाब देही निश्चित की गई है। परीवीक्षण के अन्तर्गत निचले स्तर से उच्च स्तर तक सूचना प्रेषण की पद्धति को भी सुदृढ़ किया गया है।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 119 मद हैं जिनमें से 65 मदों को भौतिक लक्ष्यों के लिए चिन्हित किया गया है तथा शेष 54 मदों का परीवीक्षण मूल्यांकन आधार पर किया जा रहा है।

9.2 अकाल राहत एवं सहायता

वर्ष 1993-94 में मानसून के दौरान माह अगस्त, 1993 मे लम्बी अवधि तक सूखा होने के कारण फ़सलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर 25 ज़िलों के 22586 गाँवों को दिनांक 31 जनवरी, 94 को अभाव ग्रस्त घोषित किया गया। राज्य सरकार ने दिनांक 1 फ़रवरी, 1994 से राहत कार्य प्रारम्भ किए एवं 15 जुलाई, 1994 तक चलाए गए। राहत कार्य इस दृष्टि से स्वीकृत किए गए कि स्थाई निर्माण कार्य हो एवं पिछले वर्ष के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जावे।

माह जून, 1994 की समाप्ति तक अकाल एवं राहत कार्यों के अन्तर्गत 7.93 लाख श्रमिकों को रोज़गार उपलब्ध करवाया गया। राहत कार्यों हेतु 160.74 करोड़ रुपये जिला कलेक्टरों को आवंटित किए गए। ग्रीष्म काल में 126.26 लाख रुपये की राशि जिला कलेक्टरों को समस्या ग्रस्त गाँवों में पेय जल उपलब्ध करवाने हेतु आवंटित किए गए।

अनुग्रह सहायता योजना के अन्तर्गत 140.28 लाख रुपये आवंटित किए गए तथा 28816 व्यक्तियों को राहत प्रदान की गई। मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए 93.41 लाख रुपये एवं पशुओं के कल्याण हेतु 53.00 लाख रुपयों की दवाइयाँ क्रय की गई। बाढ़ नियन्त्रण योजना के तहत प्रभावित व्यक्तियों को राहत हेतु 92.90 लाख रुपये आवंटित किए गए। इसके अतिरिक्त वर्ष 1993 में विभिन्न संस्थाओं एवं विभागों को बाढ़ राहत कार्य हेतु 2821.31 लाख रुपये उपलब्ध करवाए गए।

9.3 अल्प बचत

राज्य की आर्थिक स्थिति में अल्प बचत की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। चूँकि कुल संकलन का 75 प्रतिशत भाग भारत सरकार से दीर्घ कालीन ऋण के रूप में वापिस लिया जा सकता

है अतः अल्प बचत कार्यक्रम का राज्य के वित्तीय संसाधनों में ठोस योगदान रहता है। राज्य सरकार ने अल्प बचत का वातावरण तैयार करने हेतु विभिन्न प्रोत्साहनों की घोषणा की है जिसके फलस्वरूप अल्प बचत के संकलन में सराहनीय वृद्धि हुई है। परिवारों, व्यक्तियों, निगमों एवं संस्थाओं की बचत को श्रृंखलित करे राज्य के आर्थिक विकास में विनियोजित किया जाता है।

अल्प बचत कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए 460 करोड़ रुपये की राशि का लक्ष्य तय किया गया है जिसके विरुद्ध 402 करोड़ रुपये माह दिसम्बर 1994 तक संकलित किए जा चुके हैं। यह लक्ष्य का 87 प्रतिशत है। वर्तमान गति को देखते हुए यह आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्यों का 120 प्रतिशत उपलब्धि होगी अर्थात 560 करोड़ रुपये की शुद्ध जमा होने की आशा है।

वर्ष 1994-95 आय-व्ययक में 350 करोड़ रुपये के अल्प बचत के लक्ष्यों के विरुद्ध फ़रवरी, 95 तक के शुद्ध संकलन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 450.31 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में केन्द्र सरकार से प्राप्त कर ली गई है।

वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में अल्प बचत की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संकलन की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

(रुपये लाखों में)

प्रतिभूतियाँ	1993-94 (1 अप्रैल से दिसम्बर 93 तक)		1994-95 (1 अप्रैल से दिसम्बर 94 तक)	
	सकल	शुद्ध	सकल	शुद्ध
1-राष्ट्रीय बचत पत्र 8 वा निर्गम	3028.88	3107.98	3759.18	3718.00
2-डाकघर बचत बैंक खाता	12849.68	(-)2292.56	15097.22	(-)671.23
3-संचयी सावधि जमा	24.01	(-) 79.26	19.39	(-) 67.72
4-आवर्ती जमा	13338.62	6145.45	16812.43	7532.62
5-डाकघर सावधि जमा	6675.65	2807.31	6594.65	863.66
6-लोक भविष्य निधि	1528.52	912.06	2086.44	1400.19
7-इंदिरा विकास पत्र	9149.76	150.23	9552.06	3723.36
8-मासिक आय योजना	4136.22	3142.38	6763.96	5426.89
9-राष्ट्रीय बचत योजना	328.61	(-)1829.68	410.90	(-)2579.36
10-किसान विकास पत्र	20063.88	18701.26	28216.22	24205.12
11-पुराने बचत पत्र	--	(-) 4766.87	--	(-)3192.28
कुल योग	71123.83	25908.30	89312.45	40359.25

उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि डाक बचत खाता, आवर्ती जमा, किसान विकास पत्र एवं इन्दिरा विकास पत्र आदि बचत योजनाएँ सर्वाधिक लोकप्रिय योजनाएँ रहीं । वर्ष 1993-94 में इन चारों योजनाओं में कुल संकलन का 77.90 प्रतिशत राशि जमा थी तथा वर्ष 1994-95 में माह दिसम्बर 94 में यह प्रतिशत बढ़कर 78.02 प्रतिशत हो गया।

*****

10. राज्य में प्रारम्भ किए गये आर्थिक एवं वित्तीय सुधार

राज्य में आर्थिक एवं वित्तीय सुधारों की प्रक्रिया में अब तक निम्न कदम उठाये गये हैं:-

1. **उद्योग एवं राजकीय उपक्रम**

(i) औद्योगिक क्षेत्रों में संस्थापन एवं रख रखाव हेतु निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति दी गई।

(ii) भारत सरकार की सर्वांगीण नीति के अन्तर्गत दूर संचार आपरेटर्स को चयनित क्षेत्रों में दूर संचार व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(iii) सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव में निजी सहभागिता की अनुमति दे दी गई है, इसके साथ ही प्राईवेट पार्टीयों को उनके द्वारा निर्मित सड़को एवं पुलों पर टॉल टैक्स वसूल करने हेतु अधिकृत भी किया गया है।

(iv) निजी क्षेत्रों को पर्यटन, होटल एवं स्वास्थ्य रक्षक क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(v) औधोगिक कार्य हेतु भूमि रूपान्तरण से संबंधित कानून एवं नियमों को संशोधित किया गया है। भूमि रूपान्तरण से उधोग क्षेत्र को बड़ी रियायत मिली है।

(vi) राज्य प्रदूषण निवारक बोर्ड द्वारा प्रदूषण निवारक क्षेत्रों के लिए जारी किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाणपत्रों की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। 155 श्रेणियों के लघु उद्योगों को इस प्रकार अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र/ अनुमति दिये जाने की शक्तियों का क्षेत्रीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है।

(vii) औद्योगिक श्रम कानूनो के अंतर्गत अलग से किए जानें वाले निरीक्षणों को समाप्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर इस कार्य हेतु तैयार की गई "चैक लिस्ट" के अनुसार औद्योगिक इकाइयों का सामान्य निरीक्षण किया जावेगा।

(viii) प्रतिदर्श आधार पर चयनित लघु उद्योग एवं अति लघु क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का श्रम कानूनों के अंतर्गत किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या घटा कर 5 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों में 10 प्रतिशत कर दी गई है।

(ix) लघु औद्योगिक इकाइयों को केवल एक ही विवरणिका देनी होगी तथा समस्त श्रम कानूनों के अंतर्गत एक ही सामान्य नोटिस प्रदर्शित करना होगा।

(x) राज्य सरकार द्वारा कल कारखाना अधिनियम (फैक्टरीज़ एक्ट) के अंतर्गत निरीक्षण किये जाने वाले उद्योगों की सूची के 15 मदों में से केवल 3 मदों में करने का निर्णय किया गया है। इसके फलस्वरूप राज्य के कुल 12600 कारखानों में से 5000 इकाइयों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से पृथक किया जा सकेगा।

(xi) विशेष आदान स्वीकृति से संबन्धित किसी प्रकरण के निस्तारण के अंतिम निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

(xii) सभी संबन्धित विभागों / संस्थाओं में कार्य के शीघ्र निस्तारण हेतु नोडल अधिकारियों का नामांकन कर दिया गया है।

(xiii) उद्योगों के लिए आवश्यक विभिन्न आदानों की उपलब्धता / स्वीकृति निष्पादन के संबन्ध में समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

राजकीय उपक्रमों के संबन्ध में निम्न सुधारात्मक कदम प्रारम्भ किए गये हैं:-

(i) उन राजकीय उपक्रमों की कार्यकुशलता व उत्पादकता में वृद्धि करना जो राज्य के विकास के लिए लाभप्रद व आवश्यक हैं।

(ii) ऐसे उपक्रम जिन से राज्य सरकार का सक्रिय संबन्ध न हो व जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता हो, उन्हें निजी क्षेत्र में देना अथवा बन्द करना।

(iii) राज्य के लिए उपयोगी इकाइयों का पुनर्गठन करना।

(iv) उद्योगों के पुनर्गठन हेतु 5 करोड़ रुपये की राशि से केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य में भी नवीनीकरण कोष स्थापित किया जा रहा है।

(v) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का लाभ देते हुए अतिरिक्त कर्मचारियों की छँटनी के लिए कदम उठाए गये हैं।

(vi) राजकीय उपक्रमों को राज्य सरकार के सुझावों के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य निष्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे वे राज्य सरकार के उद्देश्यों की पूर्ती में सहायक हों व उनकी जवाबदेही भी बनी रहे।

2. करों में सुधार

(अ) बिक्री कर

(i) राज्य में मौजूदा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम को पूर्णतया पुनः लिखा गया है तथा नये अधिनियम का प्रारूप राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है। नवीन अधिनियम के प्रारूप में विभिन्न प्रावधानों / प्रक्रियाओं का बड़े पैमाने पर सरलीकरण किया गया है।

(ii) टैक्स स्लेबों की संख्या 14 से घटा कर 10 कर दी गई है।

(iii) एक-मुश्त कर भुगतान (ग्रीन चैनल सिस्टम) प्रणाली लागू करना । यह प्रणाली ईंट भट्टों, लघु सीमेंट इकाइयों, सर्राफ़ा एवं होटल-रेस्टोरेंट पर पहले से ही लागू की जा चुकी है।

(iv) निर्माण प्रक्रिया में काम में आने वाले आदानों की बड़ी संख्या में कर को कम / मुक्त करना।

(v) ऐसे व्यवसायी जिनकी कर देनदारी 10,000 रुपये प्रतिवर्ष है उनके लिए स्व-कर निर्धारण योजना लागू करना। राज्य में कुल पंजीकृत लगभग 1.63 लाख व्यवसाइयों में से लगभग 1.20 लाख व्यवसाइयों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है।

(vi) राज्य में चैक पोस्टों की संख्या 152 से घटा कर 72 कर दी गई है जिससे सरलता पूर्वक वस्तुओं का आवागमन सुनिश्चित हो सके।

(vii) व्यवसाइयों के सर्वेक्षण / निरीक्षण हेतु मापदण्ड / दिशा निर्देश निर्धारित किए गये हैं जिसका उद्देश्य व्यवसाइयों को होने वाली परेशानियों तथा अधिकारी विशेष की मनमानी को कम किया जाना है।

(viii) जयपुर में व्यवसाइयों के अभिलेखों तथा बिक्री कर चालानों का कम्प्यूटरीकरण।

(ix) जयपुर में पंजीकरण के आवेदनों पर एक ही स्थान पर कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

(x) न्यायालयों में वादकरण के प्रकरणों की संख्या में कमी करने के उद्देश्य से व्यवसाइयों को सुविधा प्रदान करने हेतु "एमनेस्टी योजना" चालू की गई है।

(ब) **<u>मुद्रांक एवं पंजीयन</u>**

(i) पूर्व में लागू 9 विभिन्न दरों के स्थान पर 10 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की समान दर निर्धारित कर दी गई है।

(ii) पंजीयन शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(iii) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास एवं राज्य सरकार द्वारा निर्मित मकानों एवं बहुमंजिले मकानों पर पंजीयन शुल्क घटा कर 6 प्रतिशत निश्चित कर दी गई है।

(स) **<u>भूमि एवं भवन कर</u>**

(i) भूमि एवं भवन कर की छूट-सीमा एक लाख से बढा कर दो लाख कर दी गई है।

(ii) स्व-कर निर्धारण योजना एवं मूल्यांकन पद्धति को तर्क संगत एवं सरल किया गया है। स्व-कर निर्धारण योजना के अंतर्गत भूमि एवं भवन कर की लागत को 10 लाख रुपये तक बढाया गया है। कर निर्धारण के उद्देश्य के लिए सामान्य प्रकरणों में विभाग द्वारा अनुमोदित पंजीकृत मूल्य-निर्धारक द्वारा किया गया मूल्यांकन विभाग को मान्य होगा। विभागीय निरीक्षक को ऐसे कर निर्धारण प्रकरणों से अलग रखा गया है।

3. **ऊर्जा क्षेत्र**

(i) राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आधार पर निजी क्षेत्र में अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करने का निश्चय किया गया है।

(ii) कृषि के लिए विद्युत कनेक्शन दिए जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।

(iii) व्यक्तियों एवं उपभोक्ताओं को अच्छी जानकारी प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर जिला कलैक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसी उद्देश्य के लिए राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में संभागीय स्तर की समितियों का भी गठन किया गया है।

(iv) औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा "केप्टिव पावर प्लांट" लगाने हेतु प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया जा चुका है। राज्य के तीव्र औद्योगिक विकास हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों को उच्च क्षमता (एच. टी.) के विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जावेगी।

(v) राज्य विद्युत मण्डल की कार्य कुशलता एवं कार्यक्षमता बढाने के उद्देश्य से कई निर्णय लिए गये जिनमें टैरिफ में वृद्धि तथा कृषि हेतु दिए जाने वाले विद्युत कनेक्शन पर बिजली के खम्भों के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में धीरे धीरे कमी किया जाना आदि प्रमुख है।

4. **अन्य**

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं एवं सुधारों की यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

मानवीय दृष्टिकोण के उद्देश्य से कुछ सामाजिक क्षेत्रों में, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, महिलाओं / बच्चों को आवश्यक पोषाहार आदि में सुधार कार्य किये गये। समाज के मुख्य अंगो को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने हेतु राज्य सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

*****

आर्थिक स्थिति की तालिकायें
TABLES OF ECONOMIC SITUATION

1. राजस्थान की राज्य आय औद्योगिक उद्‌भव, प्रचलित कीमतों पर एवं प्रतिशत विभाजन
STATE INCOME OF RAJASTHAN BY INDUSTRIAL ORIGIN, AT CURRENT PRICES AND PERCENTAGE DISTRIBUTION

(लाख रूपये)
(Lakh Rs.)

क्षेत्र Sector	1989-90	1990-91	1991-92*	1992-93*	1993-94@
1	2	3	4	5	6
1. कृषि Agriculture	585311 (42.30)	823926 (45.07)	851510 (42.35)	1014627 (43.79)	968164 (39.87)
2. वन Forestry	23894 (1.73)	33173 (1.81)	38837 (1.93)	40755 (1.76)	42241 (1.74)
3. मत्स्य पालन Fisheries	973 (0.07)	844 (0.05)	1369 (0.07)	2486 (0.11)	3205 (0.13)
4. खनन् Mining	29354 (2.12)	41165 (2.25)	46225 (2.30)	51265 (2.21)	51198 (2.11)
5. विनिर्माण (पंजीकृत) Manufacturing (Regd.)	91214 (6.59)	131787 (7.21)	151075 (7.51)	152841 (6.60)	178489 (7.35)
6. विनिर्माण (गैर पंजीकृत) Manufacturing (Un-registered)	59078 (4.27)	73563 (4.02)	82614 (4.11)	82887 (3.58)	91290 (3.76)
7. निर्माण कार्य Construction	82946 (6.00)	103357 (5.65)	119253 (5.93)	136084 (5.87)	149031 (6.14)
8. विद्युत्, गैस तथा जल पूर्ति Electricity, Gas & Water Supply	20972 (1.52)	16594 (0.91)	26214 (1.30)	37323 (1.61)	39348 (1.62)
9. रेल्वे Railways	23252 (1.68)	29245 (1.60)	33420 (1.66)	40692 (1.76)	49929 (2.06)
10. अन्य यातायात तथा संग्रहण Other Transport & Storage	20460 (1.48)	21281 (1.16)	27902 (1.39)	32516 (1.40)	37555 (1.55)
11. संचार Communication	9116 (0.66)	11256 (0.62)	13481 (0.67)	15592 (0.67)	18578 (0.76)
12. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह Trade, Hotels & Restaurants	209891 (15.17)	275864 (15.09)	310416 (15.44)	343334 (14.82)	363521 (14.97)
13. बैंक व्यापार तथा बीमा Banking & Insurance	43639 (3.15)	50501 (2.76)	64490 (3.21)	74354 (3.21)	85727 (3.53)
14. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें Real Estate, Ownership of Dwelling & Business Services	34073 (2.46)	38705 (2.12)	43165 (2.15)	51518 (2.22)	71294 (2.94)
15. सार्वजनिक प्रशासन Public Administration	53477 (3.87)	64721 (3.54)	70814 (3.52)	85136 (3.68)	99281 (4.09)
16. अन्य सेवायें Other Services	95912 (6.93)	112159 (6.14)	129859 (6.46)	155368 (6.71)	179673 (7.40)
शुद्ध राज्य उत्पाद, प्रतिकारक लागत पर Net State Domestic Product at Factor Cost	1383562 (100.00)	1828141 (100.00)	2010644 (100.00)	2316778 (100.00)	2428524 (100.00)
प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में) Per Capita Income (Rs.)	3241	4191	4511	5086	5220

* प्रावधानिक अनुमान Provisional Estimates upto 1992-93.
कोष्ठकीय संख्याएं प्रतिशत को दर्शाती हैं Figures within bracket denote percentage.
@ त्वरित अनुमान Quick Estimates.

राज्य आय- औद्योगिक उद्भव प्रचलित कीमतों पर
STATE INCOME-BY INDUSTRIAL ORIGIN AT CURRENT PRICES

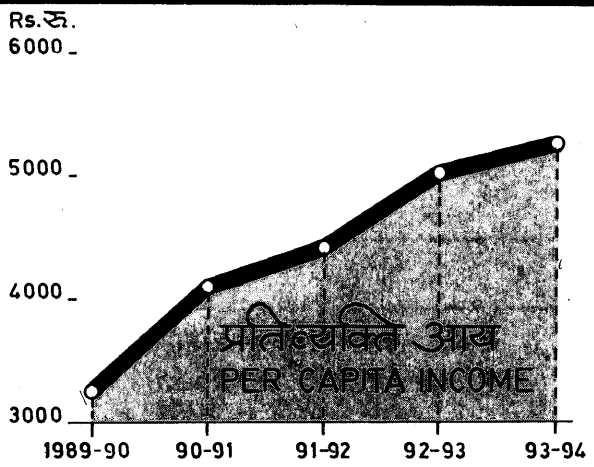

करोड़ रु.
CRORE RS.

कृषि एवं सम्बद्धित क्षेत्र
AGRI. & ALLIED SECTOR

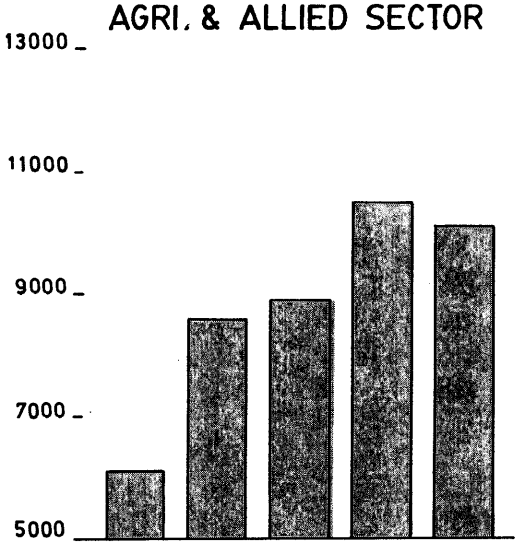

परिवहन एवं संचार
TRANSPORT & COMMUNICATION

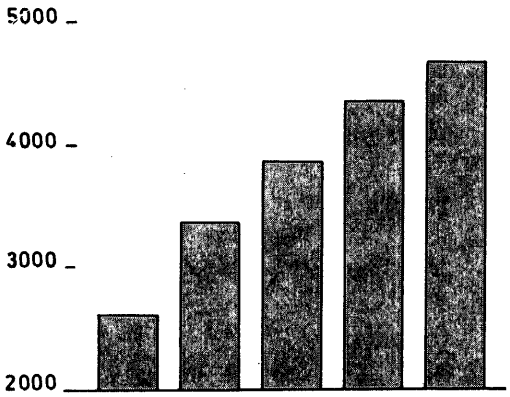

खनन् एवं विनिर्माण
MINING & MANUFACTURING

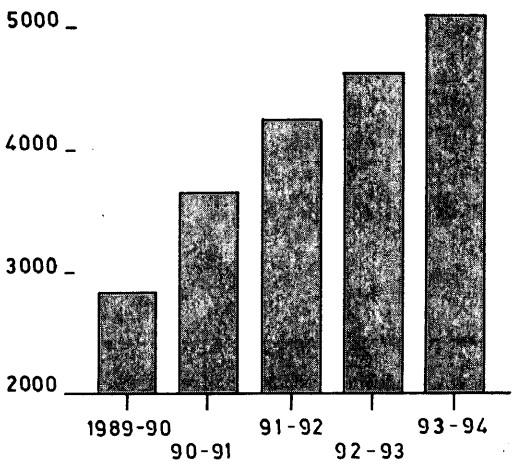

अन्य क्षेत्र
OTHER SECTORS

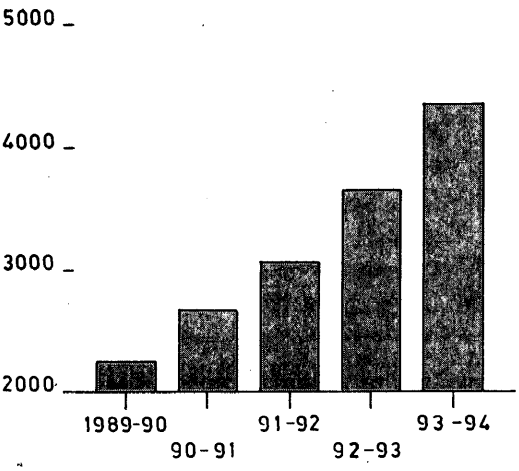

2. राजस्थान की राज्य आय-औद्योगिक उद्‌भव स्थिर (1980-81) कीमतों पर एवं प्रतिशत विभाजन

STATE INCOME OF RAJASTHAN BY INDUSTRIAL ORIGIN, AT CONSTANT (1980-81) PRICES AND PERCENTAGE DISTRIBUTION

(लाख रू. में)
(Rs. in Lakh)

क्षेत्र Sector	1989-90	1990-91	1991-92*	1992-93*	1993-94@
1	2	3	4	5	6
1. कृषि Agriculture	313365 (42.79)	385419 (45.49)	320863 (40.61)	384776 (43.69)	306924 (37.49)
2. वन Forestry	14237 (1.95)	14705 (1.74)	14799 (1.87)	14983 (1.70)	15291 (1.87)
3. मत्स्य पालन Fisheries	363 (0.05)	304 (0.04)	471 (0.06)	654 (0.07)	739 (0.09)
4. खनन् Mining	11351 (1.55)	11747 (1.39)	15739 (1.99)	17171 (1.95)	20750 (2.53)
5. विनिर्माण (पंजीकृत) Manufacturing (Regd.)	48441 (6.61)	58862 (6.95)	55691 (7.05)	53996 (6.13)	58678 (7.17)
6. विनिर्माण (गैर पंजीकृत) Manufacturing (Un-registered)	37524 (5.12)	36236 (4.28)	39136 (4.95)	40562 (4.61)	41518 (5.07)
7. निर्माण कार्य Construction	37609 (5.14)	53837 (6.35)	54165 (6.86)	57537 (6.53)	60446 (7.38)
8. विद्युत्, गैस तथा जल पूर्ति Electricity, Gas & Water Supply	10045 (1.37)	7472 (0.88)	10175 (1.29)	13334 (1.51)	14700 (1.80)
9. रेल्वे Railways	4785 (0.65)	5507 (0.65)	5975 (0.76)	5766 (0.66)	6012 (0.73)
10. अन्य यातायात तथा संग्रहण Other Transport & Storage	9641 (1.32)	8868 (1.05)	9068 (1.15)	9793 (1.11)	10166 (1.24)
11. संचार Communication	2807 (0.38)	2891 (0.34)	3155 (0.40)	3490 (0.40)	3670 (0.45)
12. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह Trade, Hotels & Restaurants	113934 (15.56)	127574 (15.06)	123995 (15.69)	134154 (15.23)	128134 (15.65)
13. बैंक व्यापार तथा बीमा Banking & Insurance	30059 (4.10)	30792 (3.63)	34194 (4.33)	34950 (3.97)	35723 (4.36)
14. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें Real Estate, Ownership of Duelling & Business Services	26458 (3.61)	27137 (3.20)	28240 (3.57)	28239 (3.21)	28110 (3.43)
15. सार्वजनिक प्रशासन Public Administration	25818 (3.53)	27832 (3.28)	26150 (3.31)	28386 (3.22)	30589 (3.74)
16. अन्य सेवायें Other Services	45935 (6.27)	48077 (5.67)	48300 (6.11)	52944 (6.01)	57272 (7.00)
शुद्ध राज्य उत्पाद, प्रतिकारक ल Net State Domestic Product at Factor Cost	732372 (100.00)	847260 (100.00)	790116 (100.00)	880735 (100.00)	818722 (100.00)
प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में) Per Capita Income (Rs.)	1716	1942	1773	1934	1760

* प्रावधानिक अनुमान Provisional Estimates.
कोष्ठकीय संख्याएं प्रतिशत को दर्शाती हैं। Figures within bracket denote percentage.
@ त्वरित अनुमान Quick Estimates

राज्य आय- औद्योगिक उद्भव स्थिर(1980-81) कीमतों पर
STATE INCOME- BY INDUSTRIAL ORIGIN AT 1980-81 PRICES

प्रति व्यक्ति आय
PER CAPITA INCOME

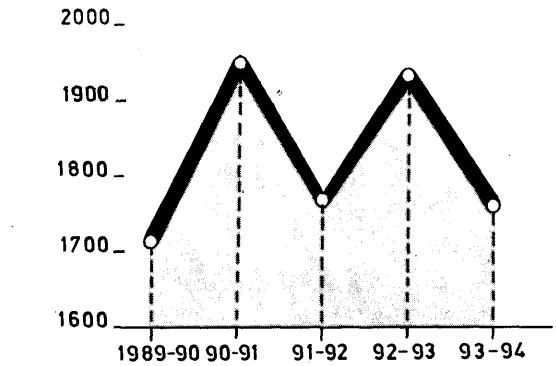

करोड़ रु.
CRORE RS.

कृषि एवं सम्बद्धित क्षेत्र
AGRI. & ALLIED SECTOR

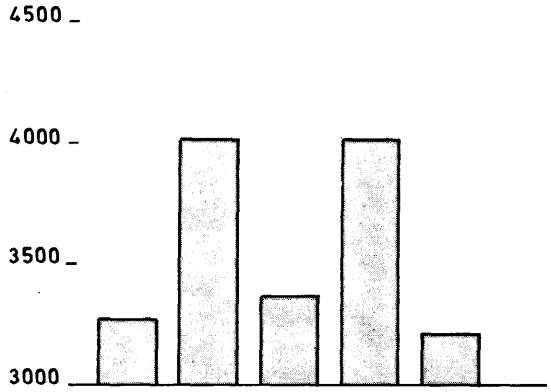

परिवहन एवं संचार क्षेत्र
TRANSPORT & COMMUNICATION

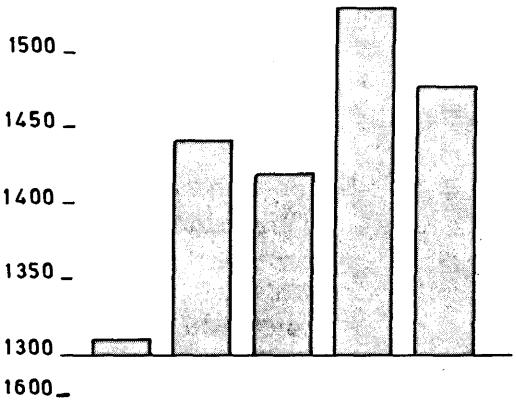

खनन् एवं विनिर्माण क्षेत्र
MINING & MANUFACTURING

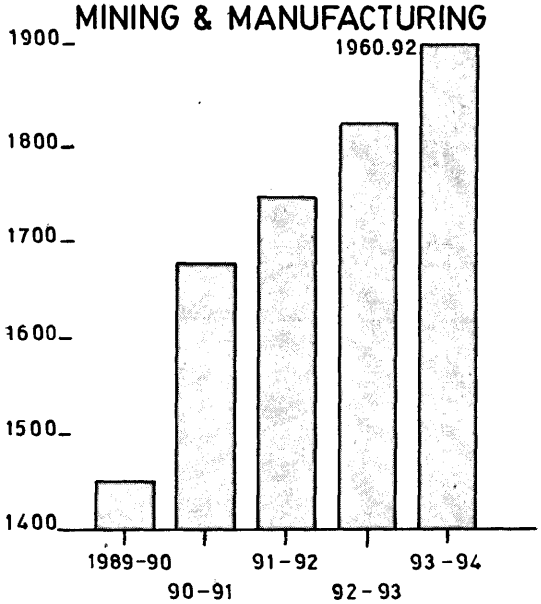

अन्य क्षेत्र
OTHER SECTORS

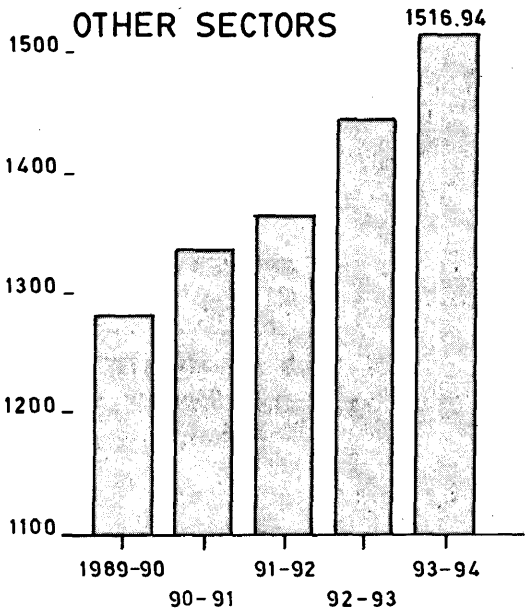

3. राजस्थान में कृषि उत्पादन के सूचकांक
INDEX NUMBER OF AGRICULTURE PRODUCTION IN RAJASTHAN
आधार 1979-80 से 1981-82 = 100
Base

फसल Crop	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 #
1	2	3	4	5	6	7
1. अन्न Cereals	174.62	143.08	177.89	139.79	195.56	118.23
अ - रबी Rabi	138.25	118.22	149.99	156.20	175.30	117.66
ब - खरीफ Kharif	239.27	187.26	227.51	110.72	231.61	119.31
2. दालें Pulses	138.08	98.13	146.07	77.52	124.10	90.44
3. कुल खाद्यान्न Total Food Grain	163.75	129.70	168.43	121.25	174.29	109.97
4. तिलहन Oilseeds	398.47	391.54	506.98	587.33	500.99	455.19
5. रेशे (कपास एवं सण) Fibres(Cotton & Sanhemp)	137.46	224.28	209.22	191.31	230.30	188.81
6. मसालें Spices and Condiments	255.74	439.83	310.52	232.91	419.68	308.96
7. तरकारियां Vegetables	857.42	985.50	763.35	643.73	743.61	596.28
8. अन्य फसलें Other Crops *	57.77	61.53	97.87	107.70	90.28	81.81
9. कुल अखाद्य फसलें Total Non-Food	307.56	323.28	398.11	447.54	400.71	357.92
10. समस्त फसलें All Crops	190.67	165.94	211.43	182.33	216.67	156.38

* गन्ना एवं तम्बाकू सम्मिलित है।
* Includes Sugarcane and Tobacco.
# अन्तिम Final.

कृषि उत्पादन के सूचकांक

INDEX NUMBERS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

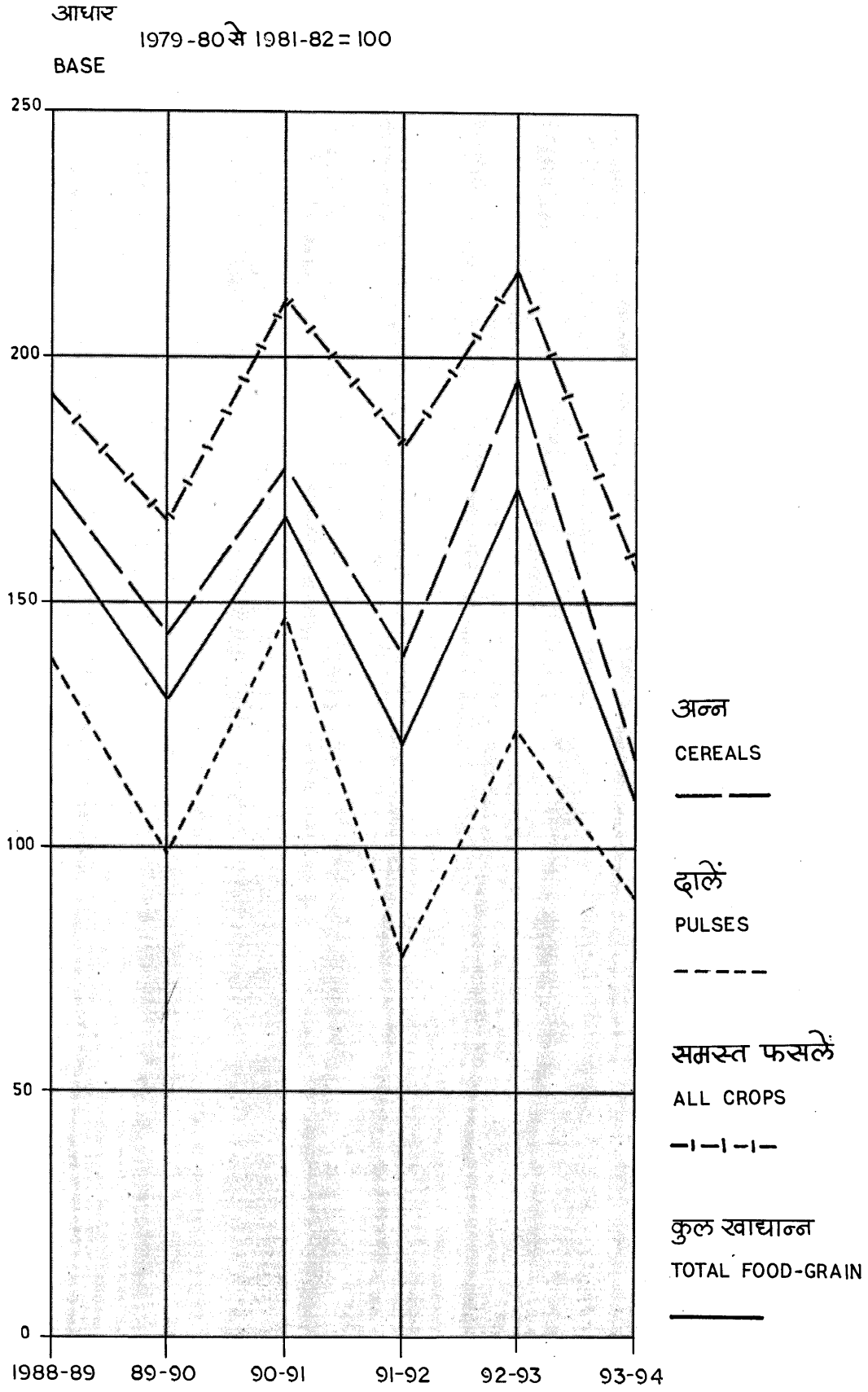

कृषि उत्पादन के सूचकांक

INDEX NUMBERS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

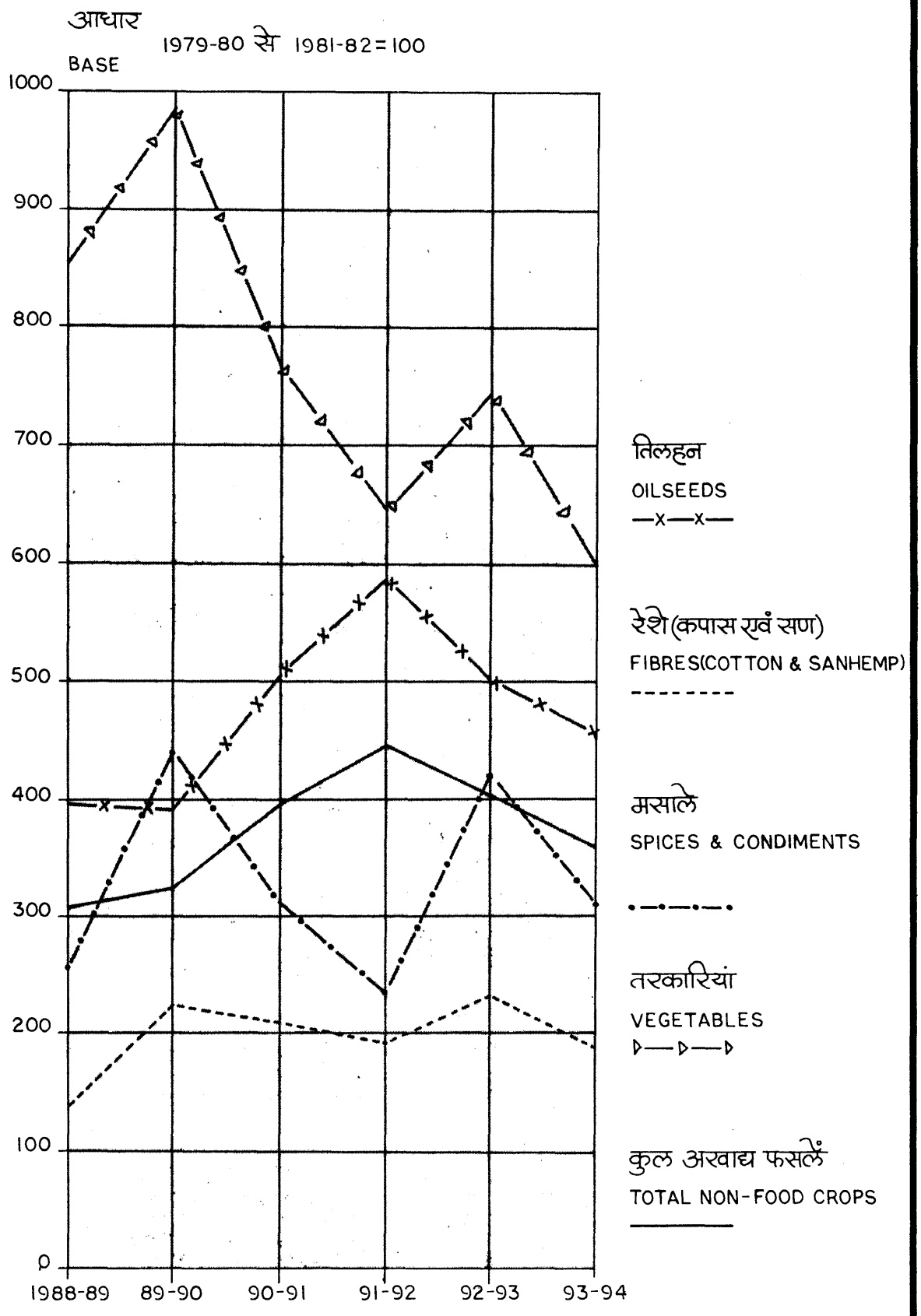

4. औद्योगिक उत्पादन
INDUSTRIAL PRODUCTION

मद Items	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994*
1	2	3	4	5	6	7	8
1. सीमेन्ट Cement '000 टन '000 M. Tonnes	3947	4175	4263	4774	4828	4810	5871
2. शक्कर Sugar '000 टन '000 M. Tonnes	9	12	13	25	39	26	15
3. यूरिया Urea '000 टन '000 M. Tonnes	301	343	372	363	351	407	374
4. सुपर फास्फेट Super Phosphate '000 टन '000 M. Tonnes	103	109	76	134	103	71	70
5. बाल बियरिंग Ball Bearings लाख संख्या Lakh No.	139	136	157	177	163	184	204
6. विद्युत मीटर Electric Meters हजार संख्या '000 No.	868	931	908	991	875	877	1139
7. नमक Salt '000 टन '000 M. Tonnes	1038	934	1055	1441	1181	1296	1142
8. पोलियेस्टर धागा Polyster yarn '000 टन '000 M. Tonnes	18.22	16.98	16.69	14.94	14.51	13.51	19.83

* प्रावधानिक PROVISIONAL

औद्योगिक उत्पादन INDUSTRIAL PRODUCTION

लाख मै.टन
LAKH TONNES

सीमेन्ट
CEMENT

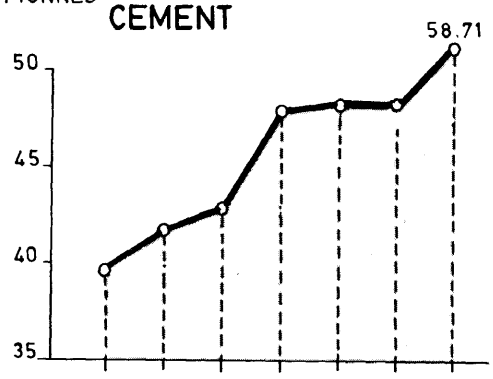

लाख संख्या
LAKH Nos.

बाल बियरिंग
BALL BEARINGS

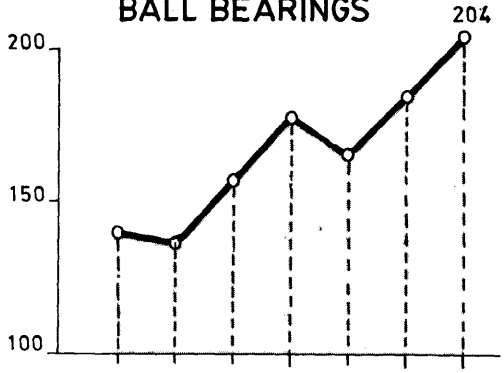

मै.टन
TONNES

शक्कर
SUGAR

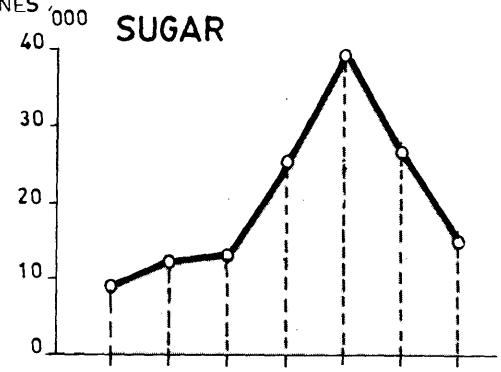

संख्या
Nos.

विद्युत मीटर
ELECTRIC METERS

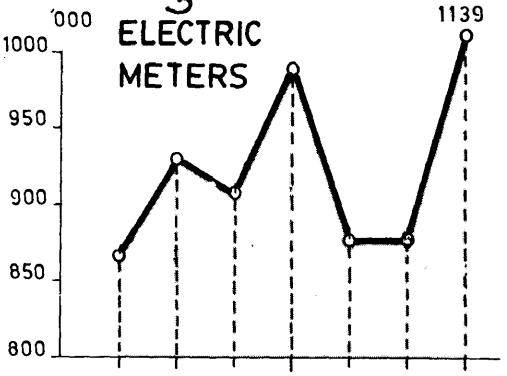

मै.टन
TONNES

यूरिया
UREA

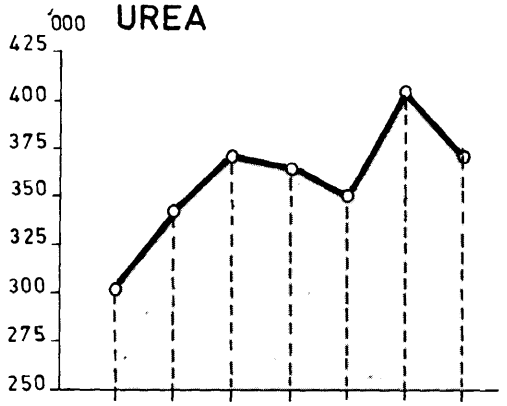

मै.टन
TONNES

नमक
SALT

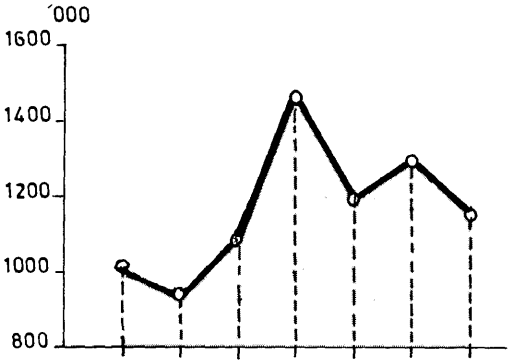

मै.टन
TONNES

सुपर फास्फेट
SUPER PHOSPHATE

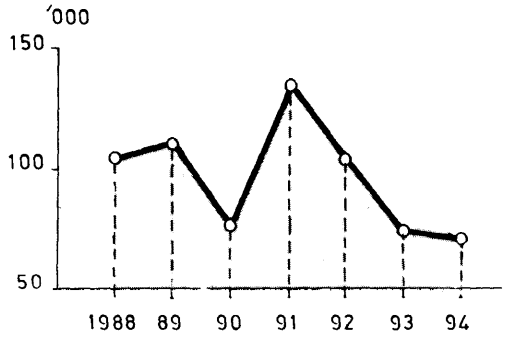

मै.टन
TONNES

पोलियेस्टर धागा
POLYSTER YARN

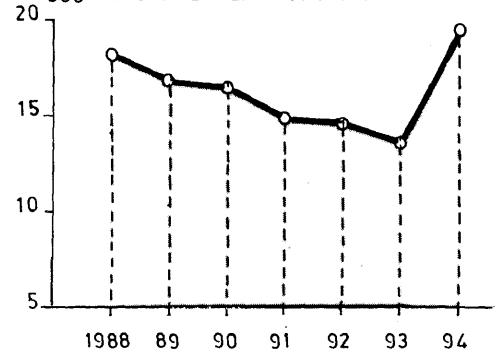

5. राजस्थान के थोक भाव सूचकांक
INDICES OF WHOLESALE PRICES IN RAJASTHAN

(आधार 1952-53=100)
Base

वर्ग Group	1989	1990	1991	1992	1993	1994
1	2	3	4	5	6	7
1. खाद्यान्न वस्तुयें Food Articles	1069.10	1141.80	1384.30	1558.50	1578.80	1771.80
2. औद्योगिक कच्चा माल Industrial Raw Materials	813.30	918.40	1497.60	1570.90	1555.30	1660.80
3. ईंधन, शक्ति एवं उपस्नेहक Fuel, Power And Lubricants	1870.50	2246.90	2900.10	3005.30	3076.70	3160.91
4. विनिर्मित वस्तुयें Manufactured Goods	1127.40	1272.40	1556.20	1668.90	1843.40	1889.93
5. सामान्य सूचकांक General Index	1087.20	1182.10	1467.80	1622.70	1668.70	1827.61

राजस्थान के थोक भाव सूचकांक
INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES IN RAJASTHAN

आधार BASE 1952-53 = 100

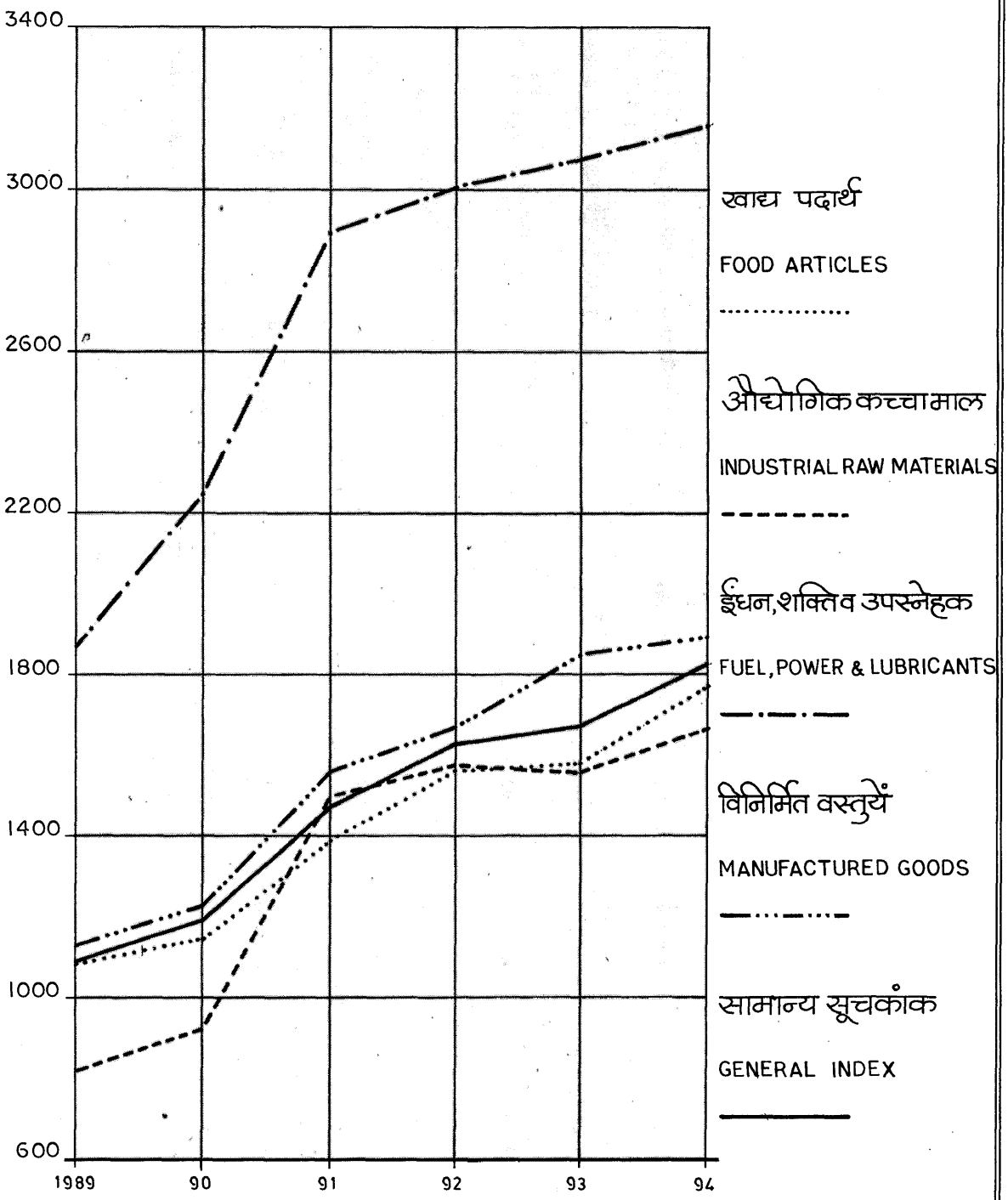

6. उपभोक्ता भाव सूचकांक
INDICES OF CONSUMER PRICES

वर्ग Group	1989	1990	1991	1992	1993	1994
1	2	3	4	5	6	7
अजमेर Ajmer						
(आधार 1982=100) Base						
(i) खाद्य Food	170	184	217	243	249	287
(ii) सामान्य General	171	190	217	243	253	280
जयपुर Jaipur						
(आधार 1982=100) Base						
(i) खाद्य Food	174	186	219	248	266	295
(ii) सामान्य General	169	184	210	228	245	269

उपभोक्ता भाव सूचकांक
CONSUMERS' PRICE INDEX NUMBERS

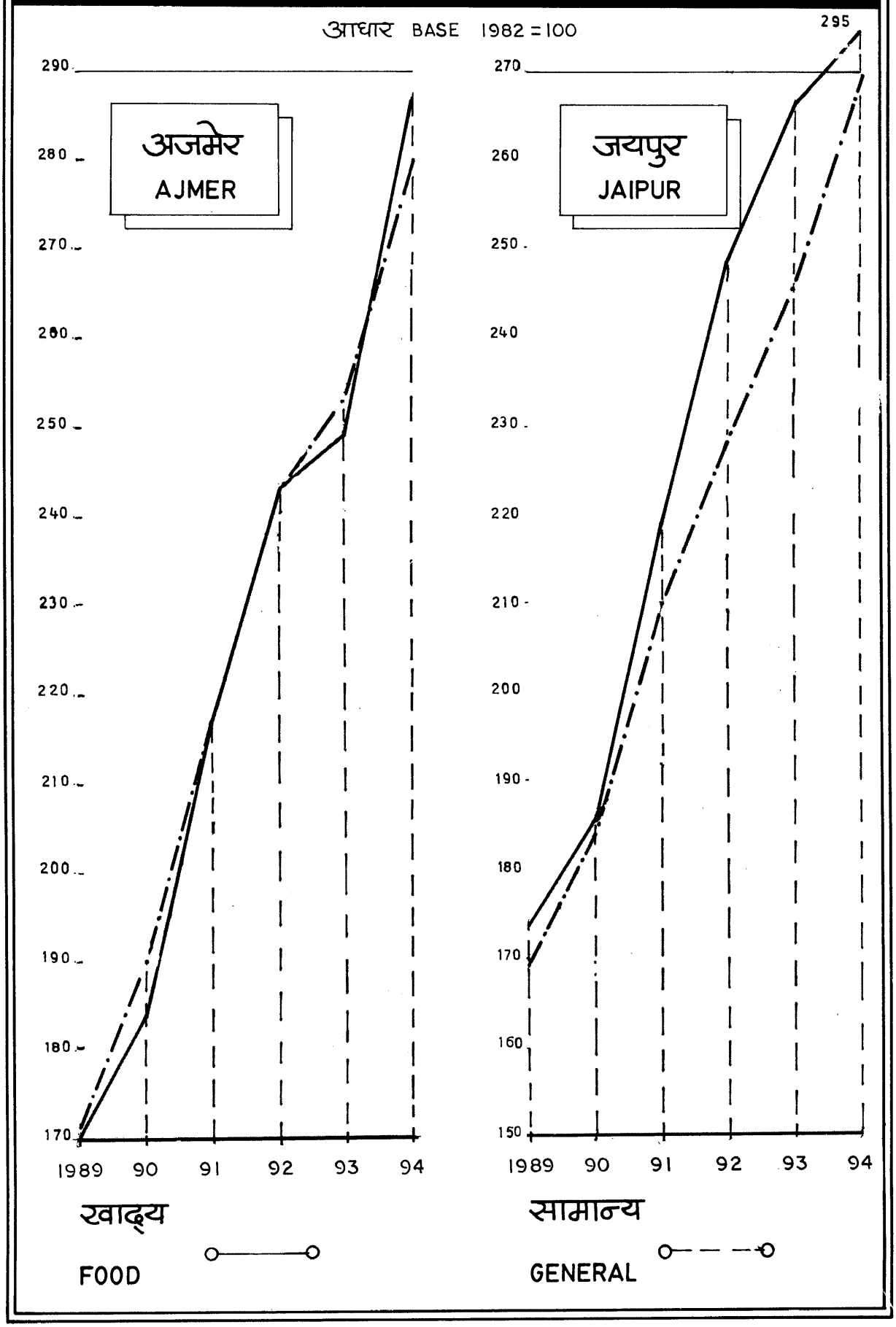

7. राजस्थान में अकाल/अभाव स्थिति से हुई क्षति
LOSS DUE TO FAMINE/SCARCITY CONDITION IN RAJASTHAN

कृषि वर्ष Agriculture Year	प्रभावित जिलों की संख्या No. of Distts. affected	प्रभावित ग्रामों की संख्या Number of Villages affected	प्रभावित जनसंख्या (लाखों में) Population affected (in Lakh)	भू-राजस्व * निलंबित (लाख रू) Land Revnue Suspended (Lakh Rs.)
1	2	3	4	5
1981-82	26	23246	200.12	646.15
1982-83	26	22606	171.62	515.68
1983-84	-	-	-	-
1984-85	21	10276	92.02	237.19
1985-86	26	26859	219.80	559.76
1986-87	27	31936	252.70	702.62
1987-88	27	36252	317.37	753.81
1988-89	17	4497	43.45	127.02
1989-90	25	14024	120.67	255.62
1990-91	-	-	-	-
1991-92	30	30041	269.00	325.87
1992-93	12	4376	34.66	29.06
1993-94	25	22586	246.81	491.36
1994-95	-	-	-	-

* वित्तीय वर्ष के समंक
Figures For Financial Year

राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

STATEWISE IMPORTANT ECONOMIC INDICATORS

राज्य STATE	देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत Percentage of Area to total area of the Country	भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 1991 Percentage of Population to Total Population of India 1991	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि.मि. 1991 Density of Population Per Sq K.M. (1991)	नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 1991 Percentage of Urban Population to total Population (1991)	साक्षरता का प्रतिशत 1991 Literacy Percentage * (1991)
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	8.44 (5)	7.8 (5)	241 (10)	26.84 (7)	45.11 (12)
2. आसाम Assam	2.40 (13)	2.6 (12)	284 (8)	11.08 (16)	53.42 (10)
3. बिहार Bihar	5.30 (9)	10.2 (2)	497 (3)	13.17 (15)	38.54 (16)
4. गुजरात Gujarat	5.97 (7)	4.9 (9)	210 (12)	34.40 (2)	60.91 (5)
5. हरियाणा Haryana	1.35 (16)	1.9 (14)	369 (7)	24.79 (9)	55.33 (9)
6. हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	1.70 (14)	0.6 (16)	92 (16)	8.70 (17)	63.54 (4)
7. जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	6.77 (6)	0.9 (15)+	76 (17)+	23.83 (10)+	N.A.
8. कर्नाटक Karnataka	5.85 (8)	5.3 (7)	234 (11)	30.91 (4)	55.98 (8)
9. केरल Kerala	1.18 (17)	3.4 (11)	747 (2)	26.44 (8)	90.59 (1)
10. मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	13.50 (1)	7.8 (5)	149 (14)	23.21 (11)	43.45 (13)
11. महाराष्ट्र Maharashtra	9.38 (3)	9.3 (3)	257 (9)	38.69 (1)	64.87 (2)
12. उड़ीसा Orissa	4.75 (10)	3.7 (10)	202 (13)	13.43 (14)	48.55 (11)
13. पंजाब Punjab	1.54 (15)	2.4 (14)	401 (6)	29.72 (5)	57.14 (7)
14. राजस्थान Rajasthan	10.43 (2)	5.2 (8)	129 (15)	22.88 (12)	38.55 (15)
15. तमिलनाडु Tamilnadu	3.96 (11)	6.6 (6)	428 (5)	34.20 (3)	63.72 (3)
16. उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	8.97 (4)	16.4 (1)	472 (4)	19.89 (13)	41.71 (14)
17. पश्चिम बंगाल West Bengal	2.68 (12)	8.0 (4)	766 (1)	27.39 (6)	57.72 (6)
अखिल भारत All India	100.00	100.0	267	25.71	52.11

साक्षरता दर 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या से सम्बंधित है।

* The literacy rates relate to the population aged 7 and above.

+ राज्य की अनुमानित जनसंख्या पर आधारित ।

Based on estimated population of state.

राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक(क्रमश:)
STATEWISE IMPORTANT ECONOMIC INDICATORS(Contd.)

राज्य STATE	औसत कृषि जोत (हैक्टेयर) Average size of holdings (Hect.) (1990-91)	प्रति व्यक्ति खाद्यानों का त्रिवार्षिक औसत उत्पादन (कि.ग्रा.) Trinnel Average Per Capita Foodgrain Production(Kg.) (1988-89 to 90-91)	बोये गये क्षेत्रफल का प्रति हैक्टेयर खाद का उपभोग (कि.ग्राम) consumption of fertilizer Per Hectare of cropped area (Kg.) (1991-92)*	प्रति लाख जनसंख्या पर श्रमिकों का दैनिक औसत रोजगार (संख्या) Average daily employment of factory workers per lakh of Population(No.)1989*	उधोगों से प्रति व्यक्ति आय वृध्दि (रूपये) Per Capita value added in industries (Rs.) (1988-89)*
1	7	8	9	10	11
1. आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	1.56	188.6 (7)	120.3 (3)	949 (9)	296 (11)
2. आसाम Assam	1.31 +	123.4 (13)	9.7 (17)	509 (13)	159 (16)
3. बिहार Bihar	0.87 +	127.7 (12)	57.4 (11)	576 (11)	314 (10)
4. गुजरात Gujarat	2.93	111.0 (15)	70.6 (9)	1721 (2)	859 (2)
5. हरियाणा Haryana	2.43	567.4 (2)	106.0 (4)	1543 (6)	641 (4)
6. हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	1.20	132.2 (10)	34.3 (14)	275 (17)	610 (5)
7. जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	0.86 +	117.3 (14)	46.5 (12)	364 (16)	46 (17)
8. कर्नाटक Karnataka	2.13	108.5 (16)	76.6 (7)	1709 (3)	374 (7)
9. केरल Kerala	0.33	36.5 (17)	75.8 (8)	990 (8)	327 (9)
10. मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	2.63	224.3 (4)	35.7 (13)	787 (10)	280 (13)
11. महाराष्ट्र Maharashtra	2.21	158.8 (9)	64.4 (10)	1599 (4)	1130 (1)
12. उड़ीसा Orissa	1.47	191.9 (6)	21.4 (16)	446 (14)	292 (12)
13. पंजाब Punjab	3.61	923.6 (1)	168.3 (1)	1752 (1)	556 (6)
14. राजस्थान Rajasthan	4.11	194.0 (5)	23.4 (15)	570 (12)	211 (15)
15. तमिलनाडु Tamilnadu	0.93	129.7 (11)	130.1 (2)	1568 (5)	688 (3)
16. उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	0.92	243.0 (3)	89.0 (6)	423 (15)	229 (14)
17. पश्चिम बंगाल West Bengal	0.90	177.6 (8)	91.0 (5)	1384 (7)	347 (8)
अखिल भारत All India	1.68 +	193.8	70.7	1014	433

* प्रावधानिक Provisional.

+ वर्ष 1985-86 के आंकडे Figures for the year 1985-86

राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक (क्रमश:)
STATEWISE IMPORTANT ECONOMIC INDICATORS (Contd.)

राज्य STATE	प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग (कि.वा.) Per Capita Consumption of electricity (kwh.)* (1991-92)	कुल ग्रामो से विद्युतीकृत ग्रामो का प्रतिशत Percentage of Electrified Villages to Total Villages (May 93)	प्रति लाख जनसंख्या पर मोटर गाडियों की संख्या Number of motor vechiles per lakh of population (31-3-1991)	प्रति हजार वर्ग किलो मीटर पर रेल मार्ग की लम्बाई (की.मी.) Railway route length per '000 Sq. of Area (Km.) (1991-92)
1	12	13	14	15
1. आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	288 (8)	100.0 (1)	2196 (9)	18.49 (10)
2. आसाम Assam	98 (17)	97.7 (2)	1265 (15)	31.45 (4)
3. बिहार Bihar	115 (16)	70.3 (8)	1209 (16)	30.57 (6)
4. गुजरात Gujarat	507 (2)	100.0 (1)	4968 (2)	26.94 (8)
5. हरियाणा Haryana	460 (3)	100.0 (1)	3237 (4)	33.90 (3)
6. हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	207 (11)	100.0 (1)	1298 (14)	4.78 (16)
7. जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	189 (13)	95.3 (3)	N.A.	0.35 (17)
8. कर्नाटक Karnataka	299 (6)	100.0 (1)	3186 (5)	15.98 (13)
9. केरल Kerala	196 (12)	100.0 (1)	2226 (7)	25.32 (9)
10. मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	267 (9)	91.8 (4)	2207 (8)	13.31 (14)
11. महाराष्ट्र Maharashtra	432 (4)	100.0 (1)	3425 (3)	17.68 (11)
12. उड़ीसा Orissa	298 (7)	70.2 (9)	1339 (12)	12.86 (15)
13. पंजाब Punjab	622 (1)	100.0 (1)	6555 (1)	42.89 (2)
14. राजस्थान Rajasthan	232 (10)	82.0 (5)	2041 (10)	17.02 (12)
15. तमिलनाडु Tamilnadu	334 (5)	100.0 (1)	2755 (6)	30.83 (5)
16. उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	174 (14)	75.1 (6)	1364 (11)	30.29 (7)
17. पश्चिम बंगाल West Bengal	151 (15)	74.9 (7)	1318 (13)	43.00 (1)
अखिल भारत All India	270	84.2	2541	19.00

* उपयोगिता और अनउपयोगिता
Utilities and Non-Utilities.

राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक
STATEWISE IMPORTANT ECONOMIC INDICATORS

राज्य STATE	प्रति लाख जनसंख्या पर बैंको की संख्या (सितम्बर,1994) No. of Banking Offices per lakh of population (Sept.,94)	प्रति व्यक्ति बैंक निषेप (रुपये) (सितम्बर,1994) Per Capita Bank Deposit (Sept.,94) Rs.	प्रति व्यक्ति बैंक साख (रुपये) (सितम्बर,1994) Per Capita Bank credit (Sept.,94) Rs.	अष्टम योजना का उदव्यय (करोड रुपये) (1992-97) 8th Plan outlay (Crore Rs.) (1992-97)	प्रचलित कीमतो पर वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की औसत प्रति व्यक्ति राज्य आय (रुपये) Per capita State Income (at current prices) Average of 1990-91 to 1992-93 (+)(Rs.)
1	16	17	18	19	20
1. आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	6.8 (9)	2551 (11)	1835 (7)	10500 (7)	5353 (7)
2. आसाम Assam	5.1 (16)	1361 (17)	563 (16)	4662 (14)	4555 (12)
3. बिहार Bihar	5.3 (15)	1488 (15)	507 (17)	13000 (3)	2624 (17) *
4. गुजरात Gujarat	7.9 (6)	4821 (4)	2034 (6)	11500 (5)	6526 (4)
5. हरियाणा Haryana	7.4 (8)	3686 (7)	1695 (9)	5700 (12)	8611 (2)
6. हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	13.6 (1)	4280 (5)	1158 (10)	2502 (16)	5356 (6)
7. जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	9.4 (4)	3643 (8)	889 (11)	4000 (15)	4045 (13)
8. कर्नाटक Karnataka	9.2 (5)	3612 (10)	2359 (4)	12300 (4)	4908 (9) *
9. केरल Kerala	9.7 (3)	5149 (3)	2185 (5)	5460 (13)	4589 (11)
10. मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	6.2 (12)	1694 (14)	871 (13)	11100 (6)	3947 (14) *
11. महाराष्ट्र Maharashtra	6.8 (9)	9079 (1)	5534 (1)	18520 (2)	7225 (3) *
12. उड़ीसा Orissa	6.4 (11)	1420 (16)	762 (15)	10000 (9)	3286 (16) *
13. पंजाब Punjab	10.4 (2)	7440 (2)	2946 (3)	6570 (11)	9666 (1)
14. राजस्थान Rajasthan	6.6 (10)	2046 (13)	887 (12)	11500 (5)	4596 (10)
15. तमिलनाडु Tamilnadu	7.7 (7)	4008 (6)	3451 (2)	10200 (8)	5810 (5)
16. उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	5.8 (14)	2176 (12	768 (14)	21000 (1)	3932 (15)
17. पश्चिम बंगाल West Bengal	5.9 (13)	3641 (9)	1812 (8)	9760 (10)	5313 (8)
अखिल भारत All India	6.9	3826	2102	186235	5599

+ प्रावधानिक Provisional

* प्रचलित कीमतों पर वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की ऑसत प्रति व्यक्ति राज्य आय (रुपये)
Per Capita State Income (at current prices) Average of 1989-90 to 1991-92. (Rs.)

राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

STATEWISE IMPORTANT ECONOMIC INDICATORS

राज्य STATE	प्रति व्यक्ति राजस्व (रुपये) Per Capita Revenue 1994-95(B.E.) (Rs.)	प्रति व्यक्ति कर राजस्व Per Capita Tax-Revenue 1994-95(B.E.) (Rs.)	केन्द्रीय करों का प्रति व्यक्ति अंश Per Capita Share in Central Taxes 1994-95(B.E.) (Rs.)	प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय Per Capita Revenue Expenditure 1994-95(B.E.) (Rs.)	प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय Per Capita Development Expenditure 1994-95(B.E.) (Rs.)
1	21	22	23	24	25
1. आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	1166.29 (13)	807.47 (10)	264.93 (8)	1265.64 (12)	850.87 (11)
2. आसाम * Assam	1246.29 (9)	536.24 (16)	316.73 (4)	1169.64 (13)	735.12 (14)
3. बिहार Bihar	844.99 (17)	484.32 (17)	292.52 (5)	865.66 (17)	530.10 (16)
4. गुजरात Gujarat	1584.97 (7)	1225.12 (3)	221.24 (14)	1565.13 (7)	977.86 (7)
5. हरियाणा Haryana	2419.14 (1)	1183.49 (4)	175.31 (17)	2706.94 (1)	1564.96 (2)
6. हिमाचल प्रदेश * Himachal Pradesh	2120.22 (3)	1005.05 (7)	573.73 (2)	2444.48 (2)	1574.82 (1)
7. जम्मू एवं कश्मीर* Jammu & Kashmir	2257.65 (2)	926.80 (9)	655.39 (1)	2052.82 (3)	1135.22 (4)
8. कर्नाटक Karnataka	1718.24 (5)	1261.53 (2)	234.56 (12)	1671.98 (6)	1147.27 (3)
9. केरल * Kerala	1222.32 (10)	945.74 (8)	236.62 (11)	1427.16 (9)	883.70 (10)
10. मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	1163.75 (14)	683.63 (14)	258.91 (10)	1168.06 (14)	752.33 (13)
11. महाराष्ट्र Maharashtra	1603.74 (6)	1148.17 (5)	195.76 (15)	1721.70 (5)	943.72 (8)
12. उड़ीसा Orissa	1181.27 (12)	694.77 (13)	376.37 (3)	1306.05 (11)	844.39 (12)
13. पंजाब Punjab	1838.93 (4)	1431.49 (1)	195.37 (16)	2029.06 (4)	993.19 (6)
14. राजस्थान Rajasthan	1274.30 (8)	734.31 (11)	267.24 (7)	1375.96 (10)	897.30 (9)
15. तमिलनाडु * Tamilnadu	1219.32 (11)	1009.40 (6)	268.29 (6)	1448.02 (8)	1000.68 (5)
16. उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	869.71 (16)	572.39 (15)	262.21 (9)	1002.73 (16)	530.05 (17)
17. पश्चिम बंगाल * West Bengal	914.89 (15)	722.75 (12)	228.47 (13)	1025.07 (15)	681.34 (15)

कोष्ठीय संख्या राज्य की श्रेणी को दर्शाती है ।

Figure with in brackets denotes State Rankings.

आंकड़े वर्ष 1993-94 से सम्बंधित है।

* Figures relates to year. 1993-94

Economic Review

1994-95

KEY INDICATORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Particulars	Unit	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95@
1	2	3	4	5	6
1. Gross Domestic Product	Rs.in Crores				
(a) At current Prices		22986	26458	28015	
(b) At constant (1980-81) Prices		8939	9906	9344	10793
*2. Economic Growth Rate as per advanced estimates	Percent				
(a) At current Prices		10.99	15.10	5.88	
(b) At constant (1980-81) Prices		(-)5.58	10.82	(-)5.67	15.51
3. Broad Sectors as a percentage of GSDP at constant (1980-81) prices	Percent				
(a) Primary		43.05	45.57	40.51	44.79
(b) Secondary		21.97	20.69	23.19	21.37
(c) Other service sector (Tertiary)		34.98	33.74	36.30	33.84
4. Index for Agricultural Production (Base 1979-82=100)	Index	182.33	216.67	156.38	N.A.
5. Total Foodgrain Production	Lakh Tonnes	79.81	114.79	70.45	105.37
6. Index for Industrial Production of Manufacturing (Base 1970=100)	Index	272.71	269.17	335.19	Under preparation

1	2	3	4	5	6
+7. General Wholesale Price Index (Base 1952-53=100)					
(a) Index Number	Index	1467.8	1622.7	1668.7	1827.61
(b) Percentage Increase		24.17	10.55	2.83	9.52
+8. General Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 1982=100)					
(a) Jaipur Centre	Index	210	228	245	269
(b) Ajmer Centre		217	243	253	280
9. Power Production (Generation + Purchase)	In million unit	12979.59	14666.50	15374.86	15329.15
-Percentage increase	Percent	16.47	13.00	4.83	(-)0.30
#10. Scheduled Commercial Bank credit	Rs. in Crores	3141.61	3507.37	3912.41	4210.48
-Percentage increase	Percent	13.22	11.64	11.55	7.62

@ Figures for 1994-95 are provisional
* Depicts percentage growth in GSDP over previous year
+ WPI/CPI are for the calendar year 1991, 1992, 1993 and 1994
# Figures for the Sept., 1991, 1992, 1993 and 1994

*****

SELECTED KEY INDICATORS

GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT

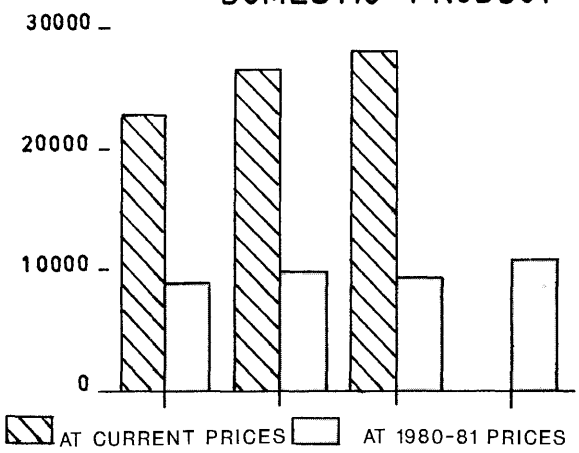

INCREASE IN POWER PRODUCTION (GENERATION & PURCHASE)

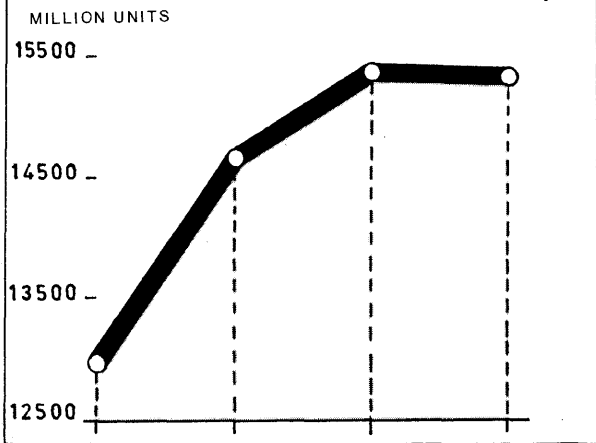

BROAD SECTORS AS A PERCENTAGE OF GSDP AT (1980-81) PRICES

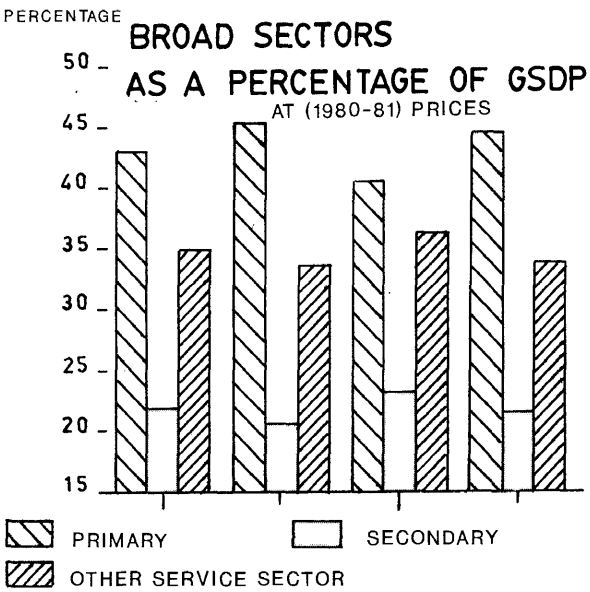

GENERAL WHOLESALE PRICE INDEX (BASE 1952-53=100)

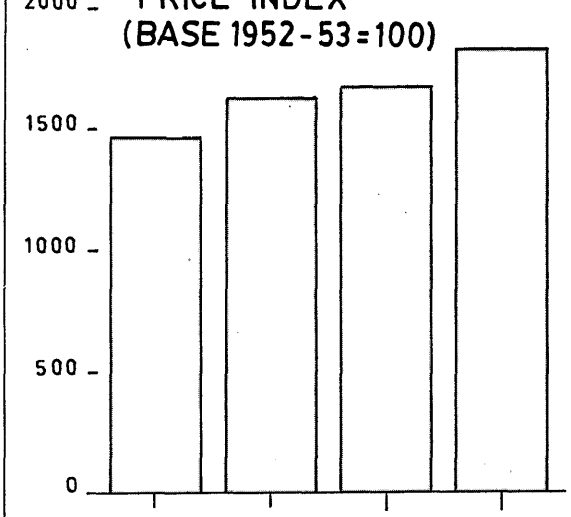

TOTAL FOODGRAIN PRODUCTION

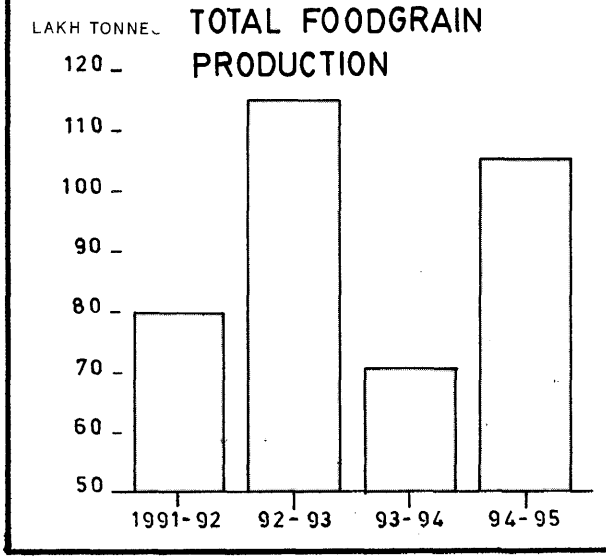

SCHEDULED COMMERCIAL BANK CREDIT

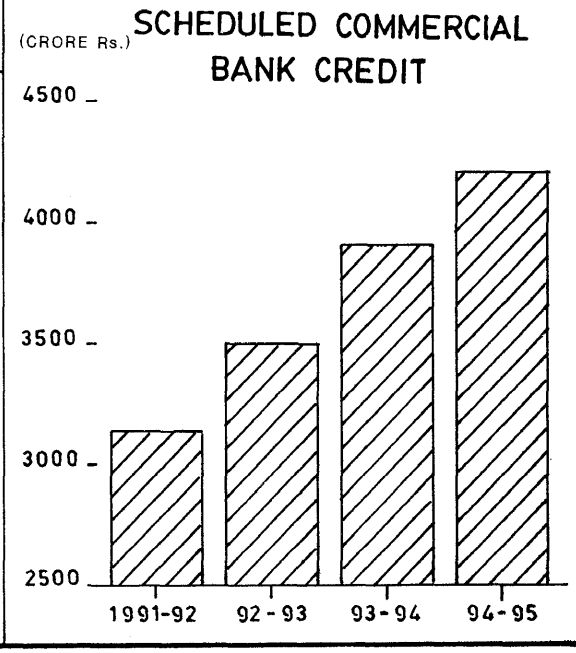

1. GENERAL REVIEW 1994-95

MACRO ECONOMIC OVERVIEW

Rajasthan is the second largest State in the Country having 3.42 lakh sq.km. area. It has a 1040 Km. long international border with Pakistan and is adjacent to the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat. Administratively, Rajasthan is divided into 31 districts, which are further sub-divided into 213 tehsils and 237 panchayat samities.

The salient features of Rajasthan are given in the table below:-

Item	Year	Unit	Particular
1. Area	1991	Lakh Sq.Km.	3.42
2. Districts	1994	Number	31
3. Sub-Divisions	1991	Number	90
4. Tehsils	1991	Number	213
5. Zila Parishads	1994	Number	31
6. Panchayat Samities	1991	Number	237
7. Village Panchayats	1994	Number	9173
8. Total Villages	1991	Number	39810
9. Inhabited Villages	1991	Number	37889
10. Towns	1991	Number.	222

The topography of Rajasthan is dominated by the Aravali range of mountains - one of the oldest mountain systems in the World. The Aravali hill range runs through the heart of the State and extending for 692 Km. The region to the west and north-west comprising of 11 districts and nearly 60 percent of the total area of the State is known as the Great Indian Desert " The THAR".

The population of the State according to 1991 Census is 4.40 crores (the projected mid year population of the State as on 1st October, 1994 is 4.81 Crores). Some of the important characteristics of Rajasthan's population are :-

1. The growth rate in Rajasthan during 1981-91 is the highest amongst the States except Jammu & Kashmir and North-Eastern States.
2. Sex Ratio of 913 females per 1000 males in Rajasthan in 1991 is lower than All India ratio of 929.
3. The literacy level of 38.55 percent (1991) in the State is the lowest amongst the States except Bihar.
4. Female literacy in Rajasthan is 20.44 percent only which is the lowest in the country as compared to All India female literacy of 39.29 percent.

The density of population (1991 census) is 129 per sq. km. There are large variations in density of population from district to district.

The climate of the State in general is characterised as driest in the country and having a large variations. The rainfall in the State is not only meagre but also varies from year to year and creates drought conditions frequently.

Rajasthan State ranks 10th amongst the 17 major States of the country in terms of per capita income, with its weak resource base primarily because of a poor heritage at the time of its formation. The State has all along been making all out efforts for tapping its limited resources.

Rajasthan is a predominently agrarian State. Agriculture plays an important role in the State's economy as nearly half of the total State Income is generated by agriculture and allied activities. Irrigation is an essential input for agriculture production. The surface water resources in the State are scarce. The ground water table, owing to

scanty and erratic rainfall, is getting deeper and deeper. Agriculture, thus is still dependent on monsoon. A great emphasis is being continuously given to augment the agriculture production in the State. The foodgrain production is estimated to be 105.37 lakh tonnes during 1994-95 in comparison to 33.80 lakh tonnes in 1950-51. Net irrigated area has increased nearly four fold since 1951-52.

The year 1994 witnessed satisfactory and evenly distributed rains raising expectations of a bumper production of foodgrains in 1994-95. The foodgrain production during 1994-95 is likely to be higher by 49.57 percent over 1993-94. The production of pulses is likely to be 18.20 lakh tonnes during 1994-95 which is more by 70.25 percent than last year. The Oilseeds production is also likely to achieve the record level of 32.69 lakh tonnes in 1994-95 surpassing the earlier record of 27.11 lakh tonnes during 1991-92.

Water is a critical resource on account of the fact that the State, which occupies 10.4 percent of the country's geographical area, has only 1.04 percent of the total surface water of the country. Stress is being laid on efficient water utilisation by adoption of water saving devices in agriculture and other fields. Another strategy adopted by the State relates to fuller utilisation of its share in Inter-State waters. The historic agreement has been finalised among the basin States of Yamuna water and it would augment the water availability in the Eastern part of the State by 111.9 crores cubic meter.

Recently the State Government has formulated a comprehensive Industrial Policy, which will help in creating better investment climate in the State. The policy provided an attractive package of incentives and concessions to new industries. A number of measures like improving/ simplifying rules and procedures, ensuring speedy inputs, increasing role of private sector in infra-structural development and providing encouragement to employment oriented investment as well as to

rural industries etc. have been taken up for achieving the objectives of the Industrial Policy 1994.

Due to corrective and innovative measures of the Government, the industrial scene has changed considerably in the State. The industrial production has not only increased but has also diversified over the years. The State is now a producer of a wide range of porducts such as synthetic yarn, cement, T.V. picture tubes, chemicals and fertilizers and even sophisticated electronic items.

Rajasthan occupies an important place in the field of minerals. The State is geologically so endowed with a wide range of minerals. Important minerals with which the name of this State is intimately associated are that of non-ferrous metals (lead, zinc and copper) and ferrous metals such as tungsten and number of industrial minerals.

In the field of minor minerals particularly of dimensional and decorative stones such as marble, kota stone and sand stone, the State occupies a unique position by contributing about 30 percent of the total value of minor minerals being produced in the country.

Significant changes have taken place in the field of mineral development in the State. During the last four decades many new mineral deposits have been discovered. At present about 42 major minerals and 23 varieties of minor minerals are being exploited.

Looking to the move towards an open market economy based on competitiveness and international out-look, the State Government has declared a Mineral Policy, 1994, which will help to explore mineral wealth of the State expeditiously by adopting modern exploration techniques particularly in the tribal and remote areas. Under the New Mineral Policy, employment opportunities in the mining sector, particularly for the persons belonging to scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections will be increased.

The State Mines & Geological Department and Rajasthan State Mineral Development Corporation are functioning for speedy and scientific exploration of mineral resources in the State.

Power is an essential input to all productive economic activities. The development of power sector has always been accorded a very high priority in the State's plans. In the Eighth Five Year Plan, about 28.31 percent of the total plan outlay has been earmarked for this sector. 30654 villages have been electrified upto February, 1995. Besides 4.78 lakhs wells have been energised in the State.

A well developed net-work of transport and communication is a basic infrastructure for rapid economic development. Rajasthan is an under-developed State from the point of view of transport and communication. In the absence of internal waterways and inadequate expansion of railways, roads provide the major infrastructural link.

Recently, the first "Road Policy" of the State has been approved by the Government. According to the Policy, roads could be constructed on contract basis by any institution or person, and it is hoped that a rapid development of roads will take place as a result. It will help in creating basic infrastructure in the State.

The State is poised towards taking a major leap forward with the on-going and proposed programme of conversion of metre gauge railway lines into broad gauge at several places. It is expected that by the end of the 1995-96, a total of about 2000 Km. of existing metre gauge railway lines would get converted into broad gauge, thus offering a great facility for development of

industries and minerals in the State. Jaipur - the Capital city of Rajasthan has already been linked to Bombay, Delhi and Calcutta. Jodhpur and Bikaner have also been brought on the broad-gauge net-work recently.

Movement in prices of various commodities has a significant impact both on the economy of the State and life of the people. Changes in the level of wholesale and retail prices at specific intervals, are revealed through Wholesale Price Index Numbers and Consumer Price Index Numbers for industrial workers. During 1994, a rising trend has been visible in both wholesale and retail prices over 1993 in the State. Which is in line with the trend noticed at the All India level during 1994.

In conformity with National objectives and keeping in view the aspirations and development needs of the State, the broad objectives of the State's Eighth Five Year Plan are :- faster growth , generation of larger employment apportunities , substantial reduction in poverty and regional disparities , provision of basic minimum facilities and greater people's participation.

The State's Eighth Five Year Plan amounts to Rs. 11500 crores, which is 283 percent more than the size of the Seventh Plan. This outlay is nearly equal to that of Gujarat and more than that of Punjab , Orissa, Madhya Pradesh , Tamil-Nadu etc.

The per capita plan outlay during the Eighth Five Year Plan has increased to Rs. 2613.64 from Rs. 875 in Seventh Plan. Further, the per-capita outlay in the State during Eighth Plan is higher than the States like Tamil Nadu , Andhra Pradesh, Madhya Pradesh etc.

The size of Annual Plan 1993-94 was to the tune of Rs. 1700 crore and Rs. 2450 crores for 1994-95. There is an increase of 44.12 percent in the plan outlay for the year 1994-95 over the previous year.

The Planning Commission , Government of India has praised the efforts made for resource mobilisation and steps taken regarding efficient financial management by the Government of Rajasthan.

Credit through banks is an important source for investment and development. Banks are actively involved in the implementation of the various programmes like NRY, PMRY, IRDP, RSCDC Schemes etc. The expansion of bank branches, particularly the regional Rural Banks has helped in execution of various rural development programmes thus fulfilling the National cause of upliftment of the weaker sections living below the poverty line.

The Bank population ratio (as per 1991 census) indicates that there was one bank office for a population of 13970 in Rajasthan as on Sept., 1994. The position of area coverage per bank office was 109 sq.kms. in the State.

State Domestic Product and the per capita income reflect the overall performance of the economy during a given period. Growth in State Domestic Product is largely dependent on the trend of agricultural production , as agriculture is the highest contributor to SDP, and has overall impact on other sectors as well. The State Domestic Product, thus is subjected to wide fluctuations depending on the monsoon conditions.

As per advance estimates, Net State Domestic Product at constant (1980-81)prices works out to Rs. 9576 crores for 1994-95 as compared to Rs. 8187 crores during 1993-94 and marked an increase of 16.97 percent over the previous year.

Per Capita Income at constant (1980-81)prices works out to Rs. 2016 for the year 1994-95 as compared to Rs. 1760 for 1993-94 indicating an increase of 14.55 percent.

Continuous efforts are being made for development of education in the State. Universalisation of primary education, expansion of educational facilities with more stress on girls education etc. remained the thrust areas during the year 1994-95 also. Free education upto the college level is being provided to girls in the State .

The total literacy campaign started in the year 1990-91 in the state continued during 1994-95. Ajmer and Dungarpur districts have already been declared as totally literate districts.

Towards the objective of "Health for all by 2000 A.D." considerable efforts have been made through strengthening and expanding the health care system. As a result, the general health condition of the people of State, has shown inprovement.

Smallpox has been completely eradicated. Other epidemic and communicable diseases have been controlled to a great extent in the State.

In order to achieve the small family norm, an intensive family welfare programme is being carried out in the State.

Concerted efforts are being made to solve the drinking water problem in both rural and urban areas of the state. By December, 1994, 36629 villages have been covered with potable water supply out of total 37889 populated villages (1991 Census) in the State.

As per 1991 census nearly, seventy percent population of the State lives in rural areas. Poverty, malnutrition, inadequate employment opportunities and lack of infrastructural facilities in rural areas are the major problems. Continous efforts are being made to alleviate rural poverty, by providing additional employment

opportunities through creation of rural infrastructure under various programmes like IRDP, JRY, DDP, DPAP, etc. Which are being implemented through the District Rural Development Agencies.

Besides, various other programmes like Apna Gaon Apna Kam, Tees Zile Tees Kaam and DWCRA etc. were also implemented for participatory rural development of the State during the year 1994-95 .

Public Distribution System has been working through a net work of fair price shops, both in rural and urban areas in the State to provide essential commodities at the reasonable prices fixed by the Government. A total number of 16798 fair price shops were functioning by the end of January, 1995 in the State.

Under the Consumer Protection Act, 1986, consumers protection forums at State level as well as at all the districts level are functioning for safeguarding the consumer's interest.

*****

2. STATE DOMESTIC PRODUCT AND FINANCE

2.1 STATE DOMESTIC PRODUCT

Estimates of State Domestic Product are one of the most important economic indicators to measure the economic development of a State.

The per capita State Domestic Product is used to determine both the absolute and relative performance of the economy of the State. It is regarded as an important tool to measure the regional disparities as well. It is also used by policy makers like Planning Commission and Finance Commission for allocation of plan resources and distribution of taxes and duties in different states.

In the present analysis the estimates of State Domestic Product are at constant (base 1980-81) and current prices. The estimates for the year 1994-95 are advance and tentative and are based on likely production, trend and projections, hence should be used carefully.

GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT

Sum of the products of all goods and services in monetory terms of the State within a given period is Gross State Domestic Product (before making any provision for depreciation)

The composition of Gross State Domestic Product by broad sectors of economy from 1990-91 onwards at constant (1980-81) prices is given in the following table:-

GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT (Rs. in crores)

Year	Primary		Secondary			Total Tertiary •	Total (GSDP) Col. 3+6+7
	Agriculture including animal husbandry	Total Primary #	Manufacturing	Utilities *	Total Secondary @		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1990-91	4104	4437	1130	224	1928	3102	9467
(P)	(43.35)	(46.87)	(11.94)	(2.37)	(20.36)	(32.77)	(100.00)
1991-92	3468	3848	1139	248	1964	3127	8939
(P)	(38.80)	(43.05)	(12.74)	(2.77)	(21.97)	(34.98)	(100.00)
1992-93	4114	4514	1148	289	2050	3342	9906
(P)	(41.53)	(45.57)	(11.59)	(2.92)	(20.69)	(33.74)	(100.00)
1993-94	3342	3785	1217	307	2167	3392	9344
(Q)	(35.77)	(40.51)	(13.02)	(3.29)	(23.19)	(36.30)	(100.00)
1994-95	4384	4834	1291	313	2307	3652	10793
(A)	(40.62)	(44.79)	(11.96)	(2.90)	(21.37)	(33.84)	(100.00)

P- Provisional Q- Quick A- Advance

* Utilities denote Electricity, Gas & Water Supply.

\# It includes Forestry, Fishing and Mining also

@ It includes Construction also

NET STATE DOMESTIC PRODUCT

Net State Domestic Product is arrived at after deducting consumption of fixed capital (CFC) or depreciation from Gross State Domestic Product.

The Net State Domestic Product (NSDP) at current prices for the year 1993-94 is estimated at Rs. 24285 crores as compared to Rs.23168 crores in 1992-93, thus registering an increase of 4.82 percent.

The State Domestic Product at constant (1980-81) prices,in 1993-94 is estimated to Rs.8187 crores as against Rs.8807 crores in 1992-93 showing a decrease of 7.04 percent. As per advance estimates, the Net State Domestic Product at

constant prices in 1994-95 as estimated to the order of Rs.9576 crores registering a rise of 16.97* percent over the preceding year.

PER CAPITA INCOME

Per Capita Income is arrived at after dividing the Net State Domestic Product from the total population.

The per capita income at current prices works out to be Rs.5220 in 1993-94 as against Rs.5086 in 1992-93 showing an increase of 2.63 percent over previous year.

The per capita income in real terms (at constant 1980-81 prices) is estimated at Rs.1760 for 1993-94 as against Rs.1934 for 1992-93, thus, registering a decrease of 9 percent during the year. The per capita income is estimated at Rs.2016 in 1994-95 as against Rs.1760 in the previous year showing an increase of 14.55 percent.

SECTORAL COMPOSITION

The composition of Net State Domestic Product by broad sectors of economy from 1990-91 and onwards at constant (1980-81)prices is as follows:-

---

* The fluctuation are mainly on account of increase in agricultural production during 1994-95 over the year 1993-94 which was a drought year.

Net State Domestic Product at constant (1980-81) Prices

(Rs. in crores)

Year	Primary		Secondary			Total Tertiary	Total (NSDP)
	Agriculture including animal husbandry	Total Primary #	Manufacturing	Utilities *	Total Secondary @		Col. 3+6+7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1990-91	3854	4122	951	75	1564	2787	8473
(P)	(45.49)	(48.65)	(11.22)	(0.89)	(18.46)	(32.89)	(100.00)
1991-92	3209	3519	948	102	1591	2791	7901
(P)	(40.62)	(44.54)	(12.00)	(1.29)	(20.14)	(35.32)	(100.00)
1992-93	3848	4176	946	133	1654	2977	8807
(P)	(43.69)	(47.42)	(10.74)	(1.51)	(18.78)	(33.80)	(100.00)
1993-94	3069	3437	1002	147	1753	2997	8187
(Q)	(37.49)	(41.98)	(12.24)	(1.80)	(21.41)	(36.61)	(100.00)
1994-95	4105	4477	1063	150	1876	3223	9576
(A)	(42.87)	(46.75)	(11.10)	(1.57)	(19.59)	(33.66)	(100.00)

P- Provisional Q- Quick A- Advance

* Utilities denote Electricity, Gas & Water Supply.

\# It includes Forestry, Fishing and Mining also

@ It includes Construction also

The study of above table highlights following changes in structure of economy, and further reveals that there has been substantial re-alignment in the sectoral composition of Net State Domestic Product over the years:

(i) Primary sector comprising of agriculture, animal husbandry, forestry, fishing, mining & quarrying still continues to dominate State's economy; yet the relative share of primary sector vis-a-vis secondary and tertiary sector is fluctuating.

(ii) The relative share of secondary sector comprising manufacturing, utilities (electricity, gas and water supply) and construction in the Net State Domestic Product increased from 18.46 percent in 1990-'91 to 19.59 percent in 1994-95.

(iii) The relative contribution of tertiary sector comprising transport, communication, trade , hotels & restaurants, banking & insurance, real-estate, public administration and other services has marginally increased from 32.89 percent in 1990-91 to 33.66 percent in 1994-95.

2.2 **EIGHTH PLAN AND ANNUAL PLAN 1994-95**

An amount of Rs.1405.72 crores and Rs. 1743.32 crores was incurred during the year 1992-93 and 1993-94 respectively. Likely expenditure for the year 1994-95 is to be the tune of Rs. 2450.00 crores.

Broad sectorwise allocations for Eighth Plan, expenditure, incurred during the years 1992-93 & 1993-94 and likely expenditure during 1994-95 are given in the following table:-

PLAN OUTLAY AND EXPENDITURE

(Rs. in crores)

S.No.	Sector	Eighth Plan outlay (1992-97)	Expenditure during 1992-93	Expenditure during 1993-94	likely expenditure 1994-95
1	2	3	4	5	6
1.	Agriculture and Allied Services	1286.92 (11.19)	128.15 (9.12)	161.00 (9.24)	245.79 (10.03)
2.	Rural Development	1021.75 (8.88)	100.71 (7.16)	116.67 (6.69)	193.86 (7.91)
3.	Special Area Programme	84.00 (0.73)	1.10 (0.08)	1.52 (0.09)	3.61 (0.15)

1	2	3	4	5	6
4.	Irrigation& Flood control	1919.99 (16.70)	260.32 (18.52)	288.34 (16.54)	387.94 (15.83)
5.	Power	3255.49 (28.31)	395.60 (28.14)	499.60 (28.66)	649.36 (26.51)
6.	Industries & Mines	536.02 (4.66)	81.96 (5.83)	88.12 (5.05)	119.54 (4.88)
7.	Transport	783.97 (6.82)	80.24 (5.71)	142.60 (8.18)	181.89 (7.42)
8.	Scientific Services	19.96 (0.17)	2.93 (0.21)	3.31 (0.19)	4.37 (0.18)
9.	Social & Community Services	2461.62 (21.41)	333.09 (23.69)	412.69 (23.67)	613.91 (25.06)
10.	Economic Services	71.72 (0.62)	8.88 (0.63)	11.54 (0.66)	18.47 (0.75)
11.	General services	58.56 (0.51)	12.74 (0.91)	17.93 (1.03)	31.36 (1.28)
		11500.00 (100.00)	1405.72 (100.00)	1743.32 (100.00)	2450.00 (100.00)

2.3 **BANKING**

Rapid economic growth in the country has improved the quality of life for a larger number of people but still poverty remains a major problem needing urgent attention. Difficult geographical conditions, in which the State is placed, makes the task of development more daunting. Rising expectation of the people cannot be met with the meagre resources of the State alone and that among others, the flow of institutional finance and credit needs to be harnessed effectively.

The State government has been making strenous efforts through plan development to strengthen infrastructural and to develop human resources over years. However, the gap in average per capita income

at the National and State levels continues. To accelerate the pace of development the banks have a vital role to play in providing resources for generating additional economic activity and incomes for the people.

Credit through banks is an important source for investment and development in the State. Various credit based programmes like NRY, PMRY, IRDP, schemes for development of SC / ST and other poverty alleviation programmes are being implemented with the active involvement of banks. The expansion of bank branches, particularly the Regional Rural Banks has helped in execution of various rural development schemes by providing credit support and thus fulfilling the National cause of upliftment of the weaker sections living below the poverty line. The comparative position of bank branches, their deposits and credit advanced in Rajasthan vis-a-vis at National level for september 1994 is presented in the table given below :-

(Ref.period September)

S.No.	Items	Rajasthan		India	
		1993	1994	1993	1994
1	2	3	4	5	6
1.	Regional Rural Banks				
a)	No.of offices (No.)	966	1068	14465	14550
b)	Deposits (crore Rs.)	393	564	7279	9131
C)	Credit (crore Rs.)	181	233	4712	5509
2.	Other Scheduled Commercial Banks				
a)	No.of offices (No.)	2044	2082	47005	47506
b)	Deposits (crore Rs.)	7454	9154	278606	336733
c)	Credit (crore Rs.)	3731	3977	162397	184531
3.	Total				
a)	No. of offices (No.)	3010	3150	61470	62056
b)	Deposits (crore Rs.)	7847	9718	285885	345864
c)	Credit (crore Rs.)	3912	4210	167109	190040

It is revealed from the above table that both the total deposits and credit have increased during 1994 (up to Sept.) over Sept. 1993. The deposits have increased by 23.84 percent in the Rajasthan in 1994 over 1993, while it was 20.98 percent at all India level during the same period .The credit deposit ratio was 43.32 percent in Sept,94 in Rajasthan, and at all India level it was 54.95 percent, whereas in September, 1993 it was 49.86 percent and 58.45 percent in Rajasthan and at India level respectively. Total credit percentage increase in Rajasthan in 1994 over 1993 has been 7.62 while it has been 13.72 percent at all India level.

As per 1991 census one bank office is catering the needs of 13970 persons in Rajasthan as on Sept, 1994 and one bank office was covering 109 sq. Kms of area.

*****

3. PRICES AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM

Price stability is essential for sustaining the momentum of growth and ensuring equitable distribution of benefits. Inflation hurts the poor the most since their incomes are not indexed to prices. Inflationary pressures in the economy accelerated as reflected by Wholesale Price Index Numbers as well as Consumer Price Index Numbers of the State during 1994 as compared to the previous year.

3.1 WHOLESALE PRICE INDEX NUMBERS (1952-53=100)

During the year 1994 the wholesale price index stood at 1827.6 as against 1668.7 during the year 1993 revealing an increase of 9.52 percent. The Wholesale Price Index of food group witnessed the highest rising trend during 1994 which on a point to point basis rose by 12.22 percent followed by industrial raw material group (6.78 percent) and fuel, power, light and lubricant group (2.74 percent) and manufacturing group (2.52 percent).

The Wholesale Price Index Numbers during the year 1994 increased except for the months of March and Dec. During these months index decreased by 3.52 and 0.93 percent over previous month. Thus, the general index exhibited an upward trend during the year 1994. The percentage variation in the Wholesale Price Index Numbers under major commodities groups during 1993 and 1994 over the previous year is given in the following table:-

Table I

WHOLESALE PRICE INDEX NUMBERS

(Base 1952-53 = 100)

S.No.	Major Groups	Annual Average			% Variation over last year	
		1992	1993	1994	1993	1994
1	2	3	4	5	6	7
1.	Food Group	1558.4	1578.8	1771.8	1.31	12.22
2.	Industrial Raw Material	1570.9	1555.3	1660.8	(-)0.99	6.78
3.	Fuel, Power, Light & Lubricant Group	3005.3	3076.7	3160.91	2.38	2.74
4.	Manufacturing Group	1668.9	1843.4	1889.93	10.46	2.52
5.	General Index	1622.7	1668.7	1827.61	2.83	9.52

3.2 CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR INDUSTRIAL WORKERS (Base1982=100)

The Consumer Price Index for industrial workers is prepared by the Labour Bureau, Simla which includes Jaipur and Ajmer centres of the State. The rising trend in the retail prices continued during the year 1994. Consumer Price Index for the year 1994 recorded an increase of 9.80 percent for Jaipur and 10.67 percent for Ajmer centre. This rate of increase is higher as compared to 7.46 percent for Jaipur centre and 4.12 percent for Ajmer Centre in 1993.

Consumer Price Index for all the commodity groups for Jaipur and Ajmer centres are summarised in the table below :-

Major Groupwise Consumer Price Index for Industrial Workers
(Base 1982 = 100)

Groups	Jaipur			% Variation		Ajmer			% variation	
	1992	1993	1994	1994 over 1993	1993 over 1992	1992	1993	1994	1994 over 1993	1993 over 1992
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Food	248	266	295	10.90	7.26	243	249	287	15.26	2.47
2. Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants	292	318	356	11.95	8.90	297	320	337	5.31	7.74
3. Fuel, Power & Light	195	210	219	4.29	7.69	229	233	239	2.58	1.75
4. Housing	146	148	154	4.05	1.37	300	308	314	1.95	2.67
5. Clothing, Bedding & Footwear	174	184	210	14.13	5.75	207	224	248	10.71	8.21
6. Miscella-neous	253	274	297	8.39	8.30	219	238	255	7.14	8.68
7. General	228	245	269	9.80	7.46	243	253	280	10.67	4.12

It is revealed from the table that all the commodity groups contributed a rise in the general average indices of both the centres during 1994.

Average general consumer price index at base 1982=100 for Jaipur, Ajmer and All India for the last 5 years are given in the following table :-

Consumer Price Index for Industrial Workers
(Base 1982 = 100)

Year	Jaipur		Ajmer		All India	
	Index	% variation over previous year	Index	% variation over previous year	Index	% variation over previous year
1990	184	8.87	190	11.11	186	8.77
1991	210	14.13	217	14.21	212	13.98
1992	228	8.57	243	11.98	237	11.79
1993	245	7.46	253	4.11	252	6.33
1994	269	9.80	280	10.67	278	10.32

The table depicts that the rate of increase in the index was the higest in the year 1991 at Jaipur, Ajmer & All India level being 14.13, 14.21 and 13.98 percent respectively over previous year. During the year 1994 the increase in the general price index over previous year has been 10.67 percent at Ajmer 10.32 percent at all India level and a lower increase has been observed at Jaipur centre being 9.80 percent.

3.3 **PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM**

Public Distribution System is operating through a net work of fair price shops in the State to provide the essential commodities in the prescribed quantity at resonable prices fixed by the Government. Total 16,798 fair price shops, were functioning in the State by the end of January, 1995. Out of this, 12631 shops were functioning in the rural areas. Through these shops 3.80 lakh tonnes of wheat, 0.08 lakh tonnes of rice, 1.68 lakh tonnes of sugar and 3.17 lakh K.litres of kerosene oil were distributed during the period from March, 1994 to January, 1995.

The Revamped Public Distribution System (RPDS) is operational in the tribal, desert and drought prone areas of the State since January, 1992. A total of 122 selected blocks of 22 district are covered under RPDS in which wheat and rice are distributed at further subsidised rates.

*****

4. INDUSTRIES AND MINES

4.1 INDUSTRIES

The Industrial Policy, 1994, aims at rapid industrialisation of the State through procedural simplification, speedy clearances, financial incentives and various other measures. Adequate support has been given for the development of small, tiny and village industries, employment oriented industries and women entrepreneurs, etc. Emphasis has been given for export promotion keeping in view the national priority of boosting the exports. Coordinated efforts are being made by the State Industries Derpartment and various State's Corporations viz. RIICO, RAJSICO, RFC, Rajasthan Khadi and Village Industrties Board etc. for the industrial development of the State.

Rajasthan State Industrial Development and Investment Coporation is providing necessary infrastructural facilities in 206 industrial estates established in the State upto December, 1994.

Financial assistance to large and medium industries is also being provided by RIICO. During 1994-95 (upto December, 1994), term loan assistance of Rs. 31.49 crores was sanctioned and Rs. 19.60 crores were disbursed.

Under centrally sponsored Scheme, 4 Growth Centre Projects i.e., Bikaner, Dholpur, Jhalawar and Abu Road were sanctioned. The work on all these four centres was in progress during the year 1994-95. Further , the scheme of two Mini Growth Centres viz. Jodhpur and Udaipur was sent to Government of India for sanction. Jodhpur Mini Growth Centre has been sanctioned and an amount of Rs.45.17 lakhs has been spent in its implementation.

The Rajasthan Financial Corportion has also been providing financial assistance to small and medium industries. During the year 1994-95 (upto December, 1994, sanction and disbursement of loan were to the tune of Rs. 94 crores and Rs. 72.53 crores respectively to 989 industrial units. Besides, an amount of Rs. 87.63 crores was recovered by the RFC during the period under reference.

The State Industries Department has been paying due attention for the rapid growth of small scale industries and artisans units , which have an inherent advantage of higher employment potential with lower capital investments as compared to large and medium industries. Necessary guidance, assistance and facilities are being provided through various packages of incentives and concessions for the promotion of such units. A target of registering 4000 small scale and artisan units has been fixed for the year 1994-95, out of which 2809 units have already been registered upto December 1994 with a capital investment of Rs. 106.55 crores, and an employment to the tune of 14823 persons. Thus a total number of 170209 small and artisans units have so far been registered in the State with an investment of Rs. 1423.33 crores and there by providing employment to 6.51 lakh persons.

"Prime Minister's Rojgar Yojana was first introduced in the year 1993 in urban areas, but now from the current year it has been extended both to the urban and rural areas of the State. Under this scheme, loan/subsidy upto Rs. 1.00 lakh is provided to unemployed youths for establishing their own industry, business or service enterprise. No collateral guarantee / security is required for this loan. A subsidy of 15 percent of the unit cost (maximum of Rs.7500/-) is admissible under this scheme. There is a inbuilt provision of technical training for the selected applicants for which stipend @ Rs. 300/- per month is provided to the trainees. 200 projects profiles have been prepared and made available to the District Industries Centres for use of unemployed youths under the scheme during 1994-95. Against the target of benefiting 8300 unemployed youths, 4783 youths have been benefited by the end of December, 1994.

An Industrial Information Bureau is functioning at the State level in the Industries Department to provide necessary guidance, assistance and facilities at a single place. The District Industries Centres are also functioning in all the districts for providing necessary facilities to the entrepreneurs.

Rajasthan Small Industries Corporation (RAJSICO) is also funtioning in the State for the assistance of small scale industries and craftsmen by providing marketing facilities for their finished products. A number of emporiums are functioning for marketing and popularising the handicrafts of Rajasthan.

4.2 KHADI & VILLAGE INDUSTRIES

Khadi and village industries help to a great extent in generating employment opportunities with lesser capital investment. Rajasthan Khadi and Village Industries Board has been looking after the promotional work of such industries . During 1993-94 , the production of woollen and cotton khadi was to the tune of Rs. 31.51 crores which is estimated to increase to Rs. 34.50 crores by the end of 1994-95 . Likewise the production of village industries which was worth Rs. 197.61 crores during 1993-94 is estimated to increase to Rs. 207.10 crores during 1994-95. Further, employment will be provided to 4.27 lakh persons during 1994-95 as against of 4.17 lakh persons in 1993-94 .

4.3 FACTORIES AND BOILERS

The Chief Inspector of Factories And Boilers, Rajasthan is the State authority in respect of registered factories and boilers. Main function of the Department is to enforce the Factories Act, 1948, Indian Boilers Act, 1923, Payment of Wages Act, 1936, to ensure health , safety and welfare of industrial workers . During the year 1994-95, 674 new factories/boilers were registered and 15037 workers got employment upto December,1994.

A comparative position of production of some of the selected important items during the year 1993 and 1994 (provisional) in the State is depicted in the following table:

Industrial Production of Selected Items

S.No.	Item	Unit	1993	1994	change in 1994 over 1993
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Sugar	Tonnes	26261.70	15245.33	-41.95
2.	Spirit (all Types)	'000 Lt.	17646.93	16667.43	- 5.55
3.	Vegetable Ghee	Tonnes	33841.31	39816.94	17.66
4.	Salt	Lakh M.T.	12.96	11.42	-11.88
5.	Urea	'000 M.T.	406.65	374.46	- 7.92
6.	Super Phosphate	'000 M.T.	71.36	69.92	- 2.02
7.	Cement	'000 M.T.	4810.25	5870.71	22.05
8.	Mica Insulating Bricks	No.	1797.68	2107.04	17.21
9.	Zinc Ingots	'000 M.T.	83.14	100.71	21.13
10.	Cadmium finished prod.	Tonnes	164.19	133.70	-18.57
11.	Railway Wagons	No.	1872	600	-67.95
12.	Ball Bearings	Lakh No.	183.52	203.90	11.11
13.	Water Meters	No.	47422	40935	-13.68
14.	Radiators	No.	3365	2272	-32.48
15.	Polished and repolished stone	'000 Sq.Mt.	200.97	220.28	9.61
16.	Electric Meters	No.	876522	1138755	29.92
17.	Nylon Yarn	Tonnes	3438.04	3956.39	15.08
18.	Polyester Yarn	Tonnes	13510.72	19832.68	46.79
19.	Casustic soda	Tonnes	39131	42251	7.97
20.	Calcium Carbide	Tonnes	47405	45318	- 4.40
21.	P.V.C. Resin	Tonnes	34272	32195	- 6.06
22.	P.V.C. Compound	Tonnes	4607	5100	10.70
23.	Sulphuric Acid	'000 Tn.	226.35	327.72	44.79
24.	Copper Cathodes	Tonnes	21131	32144	52.12
25.	Cotton Cloth	Lakh Mt.	422.41	373.22	-11.64
26.	Cotton Yarn	'000 Tonnes	54.62	58.28	6.70

@ Provisional

As revealed by the above table, there had been a mixed trend in the industrial production of the selected items during 1994 as compared to the previous year. Out of the 26 selected items , the production of the 14 items increased, whereas production of remaining 12 items decreased during 1994. Range of variation in the production of these items is given below:

Range of Variations in Production in 1994 over 1993.	Items
1.1 Increase upto 10 percent	Polished & Repolioshed Stones Caustic Soda & Cotton Yarn
1.2 Increase between 10 to 20 percent	Vegetable Ghee, Mica Insulating Bricks, Ball Bearings, Nylon Yarn & P.V.C compound
1.3 Increase between 20 to 50 percent	Cement, Zinc Ingots, Electric Meters, Polyster Yarn and Sulphuric Acid
1.4 Increase between 50 to 100 percent	Copper Cathodes
1.5 Increase of more than 100 percent	Nil
2.1 Decrease upto 10 percent	Spirit (all types), Urea, Super Phosphate, Calcium Carbide and P.V.C Resin
2.2 Decrease between 10 to 20 percent	Salt, Cadium finished Products Water Meters and Cotton Clothes
2.3 Decrease between 20 to 50 percent	Sugar and Radiators
2.4 Decrease between 50 to 100 percent	Railway Wagons

4.4 **MINERALS**

Recently State Government has declared the new Mineral Policy 1994, with basic objective to explore mineral wealth of the State expeditiously by adopting modern exploration techniques, value addition through promotion of processing units and mineral based industries, encouraging exports, develop human resources as to meet out the requirement of mining and mineral based industries, increase employment opportunities and achieve greater transparancy in decision making. Under the new Mineral Policy, the work relating to infrastructural development in the Mining Estates. In these areas, where the mining leases could be granted in clusters, has been assigned to RSMDC.

Infrastructural facilities like road power etc. will be provided by the RSMDC. The lessees would be required to pay to the RSMDC such premiums which would cover the infrastructure development cost in the Mining Estate.

For the year 1994-95, 72 projects have been kept under the scheme of mineral survey and prospecting. The targets proposed and achievments made upto December,1994 are shown in the following statement:

Work	Unit	Target upto Dec.94.	Achievement (upto Dec.94)	% Achievement.
1.R.M.S.	Sq.kms.	3625	3625	100.00
2.R.G.M.	Sq.kms.	325	260.25	80.07
3.D.G.M.	Sq.kms	20.50	28.09	137.02
4.Drilling	Mts.	11050	9822.10	88.89

During the year 1994-95, the highest priority has been given for granite delineation. Consequently more than 170 plots were delineated in Ajmer, Jalore, Jodhpur, Pali Banswara, Bhilwara and Rajsamand districts.

Further, detailed exploration for proving SMS grade of limestone in Sanu area was continued.During the year 1994-95, drilling was taken up in Khuiala and Tulsi Ram ki Dhani areas of Jaisalmer district. Investigations for proving cement grade limestone in Gariya area of Sirohi district and Polgutta-Kaulji area of Bundi distrct were also continued by drilling.

Rajasthan State Mineral Development Corporation is also engaged in developing, promoting, establishing and executing the industries, projects and enterprises based on minerals, either at its own or in the joint sector. Besides carrying out mining activities, the Corporation also provides consultancy for development of mines and setting up of mineral based industries. The Corporation is operating mines on commercial lines at different places in

13 districts of the State. It is dealing mainly in production and sale of limestone, rockphosphate, gypsum, falspar and graphite.

4.5 LABOUR

INDUSTRIAL RELATIONS

Industrial peace is one of the imperatives for achieving desired level of productivity and production. During the year 1994-95 (upto December, 1994), 35 strikes / lock-outs were reported affecting 14528 labourers and a loss of 3.48 lakh mandays, whereas 43 strikes / lock outs were reported during 1993-94 affecting 14943 labourers and loss of 4.10 lakh mandays in the State.

At the beginning of the year 1994-95, there were 3710 registered trade unions in the State with a membership of 6.48 lakh. 138 new unions with a membership of 0.16 lakh were registered upto December, 1994. 963 trade unions were de-registered due to non-submission of annual returns during the period under reference. Thus there were 2885 registered trade unions in the State by December, 1994.

MINIMUM WAGES

To protect the interests of the labourers, the minimum wages for unskilled, semi-skilled as well as skilled labourers have been increased from 1st January, 1995 as per details given below:-

Labourers	Minimum Weges(in Rs.)	
	on 2.7.90	from 1-1-95
1. Unskilled.	22.00	32.00
2. Semi skilled	23.50	33.00
3. Skilled	25.00	34.00

4.6 **EMPLOYMENT**

Generation of employment opportunities is one of the main objectives of planned development. Therefore, the information on employment opportunities and unemployment in various categories of the population is essential. In the State, average daily employment in registered factories was 3.10 lakh in 1994 against the average daily employment of 2.95 lakh in the last year. In the small scale industries registered with the Industries Department of the State, average daily employment was 6.51 lakh in 1994-95 (upto December, 1994) as against 6.30 lakh in the previous year. Khadi and Village Industries will expected to provide employment to the tune of 4.27 lakh persons during 1994-95. In addition, employment opportunities were also expected to be provided in various rural development and poverty alleviation programmes during the year.

Estimated Employment in Public & Private Sectors in Rajasthan is given below:

(In lakhs)

Year	R A J A S T H A N		
	Public Sector	Private Sector	Total
1.	2.	3.	4.
1992	9.73	2.31	12.04
1993	9.77	2.32	12.09
1994 (upto march, 1994)	9.85	2.39	12.24

Employment fairs were also organised at Panchayat Samiti level to help rural youths in getting employment and to motivate for self employment by providing vocational guidance. Fortnightly newspaper "Rojgar Sandesh" is also published by the Directorate of Employment to provide information regarding public sector vacancies, competitive examinations, trainings, scholarships and various technical courses.

*****

5. AGRICULTURE AND ALLIED SECTORS

5.1 MONSOON

Agriculture continues to be susceptible to the vagaries of the monsoon. Inspite of partly dry spells in September, 1994, monsoon trend remained to be satisfactory raising expectation of a bumper Kharif. Higher than average rainfall in June, July and August, 1994 brightened the prospects of area coverage under Rabi crops. Due to deficient and un-evenly distributed rainfall during 1993-94, agriculture production was adversely affected. However, during the current year foodgrain output is likely to be significantly higher than the targetted level of 105 lakh tonnes. There is even a distinct possibility it may reach the record level of 114 lakh tonnes attained in 1992-93.

5.2 AGRICULTURE PRODUCTION

Agriculture production ought to play a significant role in the State's economy, as it does accounts for about 45 percent of S.D.P. and about 70 percent population is engaged in this sector.

The area and production of major crops for last 3 Years are depicted in the following table :

Crop	Area (in lakh hect.)			Production (in lakh tonnes)		
	1992-93 (Revised)	1993-94 (Final)	1994-95 (Likely)	1992-93 (Revised)	1993-94 (Final)	1994-95 (Likely)
1	2	3	4	5	6	7
Cereals						
Kharif	69.01	60.92	66.36	44.97	22.70	35.28
Rabi	24.95	21.92	21.08	55.24	37.06	51.89
Pulses						
Kharif	19.49	20.54	19.56	6.23	2.75	5.42
Rabi	14.92	12.62	15.49	8.35	7.94	12.78

1	2	3	4	5	6	7
Foodgrains						
Kharif	88.50	81.46	85.92	51.20	25.45	40.70
Rabi	39.87	34.54	36.57	63.59	45.00	64.67
Total	128.37	116.00	122.49	114.79	70.45	105.37
Oil Seeds						
Kharif	9.73	11.71	12.21	7.23	6.41	8.35
Rabi	23.83	24.35	24.08	18.18	17.62	24.34
Total	33.56	36.06	36.29	25.41	24.03	32.69
Sugarcane	0.24	0.21	0.19	11.29	10.20	8.90
Cotton *	4.76	5.18	4.61	10.16	8.39	10.78

* Production in lakh bales

Although total foodgrain production in the State has been increasing over the years yet there are considerable fluctuations on year to year basis. These are mainly because of uncertainty of rains both in quantity as well as in its spread.

Area sown under total foodgrains in 1994-95 is likely to be 122.49 lakh hactares as compared to 116.00 lakh hactares in 1993-94. Total foodgrain production is estimated to be 105.37 lakh tonnes in 1994-95 whereas it was only 70.45 lakh tonnes in 1993-94. Thus there would be an increase of about 49.57 percent in foodgrain production in 1994-95.

Of the total production of cereals in Rajasthan, Bajra, Maize, Jowar during Kharif and Wheat during Rabi accounted for the maximum share. However, during Kharif rice and millets and, during Rabi, barley are also sown.

Kharif cereal production is expected to be 35.28 lakh tonnes in 1994-95 as compared to 22.70 lakh tonnes in 1993-94, and rabi cereal production is estimated to be 51.89 lakh tonnes in 1994-95 as compared to 37.06 lakh tonnes in 1993-94.

Pulses constitute an important source of dietary proteins and rich source of energy and minerals. They help in balancing the cereals dominated diet of low and middle income families, by supplementing the essential amino acids profile of cereals proteins.

The production of Kharif pulses is estimated to increase to 5.42 lakh tonnes in 1994-95 from 2.75 lakh tonnes in 1993-94, which is higher by 97.09 percent. Production of Rabi pulses is expected to increase to a level of 12.78 lakh tonnes in 1994-95 as against 7.94 lakh tonnes in 1993-94. Thus, total production of pulses is likely to increase by 70.25 percent in 1994-95.

Production of Oil seeds in Rajasthan includes groundnut, sesamum, soyabean and castor seed during Kharif and Rape and Mustard, Taramira and Linseed Rabi. In the past, the production of Oil-seeds has increased significantly and the main contributors have been crops like Soyabean during Kharif and Rape and Mustard during the Rabi.

The production is likely to achieve the record level of 32.69 lakh tonnes in 1994-95. Increase in Oilseed production is largely attributable to the increase in area sown.

Sugarcane is an important crop of the State but there has been a decreasing trend in its production, area and productivity over the years.

Sugarcane production is expected to be of the order of 8.90 lakh tonnes in 1994-95 down from 10.20 lakh tonnes in the year 1993-94. This will be the lowest level of sugarcane production during the last 3 years.

Cotton is an important cash crop being grown in the State especially in Ganganagar district. In

addition to Ganganagar, it is also sown in some pockets in the districts of Banswara, Bhilwara, Pali and Bikaner. The production of cotton has increased to 10.78 tonnes during the year 1994-95.

The level of agriculture production and productivity over the years as shown revealed by the Index numbers of area, production and productivity (Base year 1979-80 to 1981-82 = 100) are given in the following table:

(Base 1979-82 = 100)

Year	INDEX		
	Area	Production	Productivity
1	2	3	4
1989-90	103.09	165.94	155.53
1990-91	114.38	211.43	165.06
1991-92	107.68	182.33	147.41
1992-93	117.03	216.67	157.22
1993-94	109.36	156.38	122.04

5.3 **AGRICULTURE EXTENSION AND INPUT MANAGEMENT**

The availability of quality seeds is essential for achieving higher level of production. Accordingly, high yielding seeds variety programme introduced in the State has been a major intrument of agricultural strategy to increase foodgrain production. Use of fertilizers also remains one of the larger determinants of crop yield.

Various measures are being taken by the State Agriculture Department through Agriculture extension and input management to reduce the adverse influence of the erratic monsoon and hostile weather conditions on agriculture

production in the State. Achievements under agriculture extension and input management programmes during the years 1993-94 and 1994-95 are shown in the following table:

Items	Season	Unit	1993-94	1994-95	
			Achieve-ments	Target	Achieve-ments (Likely)
1	2	3	4	5	6
1. Area under high yielding varieties	Kharif	Lakh Hact.	14.56	16.60	12.41
	Rabi(Wheat)		14.83	15.00	14.00
2. Distribution of high yielding variety seeds	Kharif	'000 Qtls.	40.80	49.90	42.70
	Rabi(Wheat)		140.50	110.00	120.00
3. Distribution of other improved seeds	Kharif	'000 Qtls.	47.10	40.30	52.90
	Rabi		37.50	37.00	40.90
4. Distribution of fertilizers	Kharif	'000 Tonnes	227.00	246.60	263.10
	Rabi		275.00	379.50	379.50
5. Distribution of Rhyzobium culture packets	Kharif	Packets in Lakh Nos.	1.67	4.50	0.43
	Rabi		0.47	3.00	0.64
6. Area covered under plant protection measures	Kharif	Lakh Hact.	45.00	38.00	31.50
	Rabi		34.07	36.00	36.00

5.4 **IRRIGATION**

Out of the total area cultivated in the State only 27.20 percent area is under irrigation. There are 4 major sources of irrigation viz. canal, tanks, wells and tube-wells in the State. Out of the total area under irrigation, 58.90 percent area was irrigated through wells and tube-wells, and 36.27 percent through canals, whereas tanks and other sources irrigated 4.83 percent during the year 1992-93.

Details of sources-wise area irrigated during the years 1990-91 to 1992-93 are given in the following table:

(Area in '000 Hectares)

Source of Irrigation	Net area irrigated			Gross area irrigated		
	1990-91	1991-92	1992-93	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6	7
1. Canals	1354	1424	1428	1768	1856	1990
2. Tanks	184	163	207	200	181	230
3. Wells & Tubewells	2341	2702	2803	2658	3170	3231
4. Others	25	54	33	26	57	35
5. Total	3904	4343	4471	4652	5264	5486

The Irrigation Department of the State is engaged in construction of various major, medium and minor irrigation projects with the object of creating irrigation potential. For the year 1994-95 a sum of Rs. 280.34 crores was originally provided for various major, medium and other works, this includes Rs. 93.00 crores for IGNP and Rs. 23.00 crores for Mahi. During 1994-95 a target for creating additional irrigation potential of 79.87 thousand hactares has been fixed, out of which 2670 hactares would be created by Mahi Bajaj Sagar and 61 thousand hactares by IGNP. With the assistance of World Bank, the project on Dam Safety Measures is being implemented. Works on 14 minor irrigation projects are also in progress with FRG assistance.

A provision of Rs. 93.00 crores for IGNP under Plan, and Rs.52.00 crores under C.S.S. for Border Area Development Programme has been made for the year 1994-95, out of which Rs. 47.62 crores and Rs. 32.59 crores respectively have been spent by the end of January '95. An amount of Rs. 79.61 crores under Plan, and Rs. 52.00 crores under C.S.S. was spent during 1993-94 on IGNP.

5.5 **ANIMAL HUSBANDRY**

Owing to its vast employment potential the animal husbandry / livestock rearing plays a prominent role in the rural economy in supplementing the family incomes particularly for the low income landless families and small and marginal farmers.

Rajasthan is endowed with rich and large livestock resources. As per 1991-92 livestock census there were 477.73 lakh (provisional) livestocks in the State.

Under the Integrated Cattle Development Programme, 749 sub-centres were established by re-structuring the existing intitutions in Jaipur and Bikaner divisions to provide animal health care within a radius of 5 to 8 Kms. The Gopal Scheme continued in 40 Panchayat Samities of 12 districts of southern and eastern parts of the State. In Jaipur, Bharatpur, Alwar and Dausa districts, the Cattle Development Programme was being executed in collaboration with Rajasthan Dairy Federation. One Goat breeding Centre has been working in Ramsar village of Ajmer district for goat development and goat feed production.

Under the pig rearing programme, a foreign breed Piggery Farm was established in Alwar district. For poultry development, a new demonstration "Cage System" is being developed at State Poultry farm, Jaipur. 6 poultry farms and 16 intensive poultry development blocks have been working.

5.6 **DAIRY DEVELOPMENT**

Rajasthan Cooperative Dairy Federation Ltd., has been carrying out the dairy development activities on cooperative basis in the State with the assistance of National Dairy Development Board. This programme is basically designed to link rural milk producers with urban consumers. The activities are organised by farmers owned and managed dairy cooperative societies. It aims at providing good quality milk and milk products to the consumers, ensures animal health care and

renumerative return to the milk producers. There are 10 dairy plants with processing capacity of 9 lakh litres milk per day and 24 chilling plants with capacity of 4 lakh litres of milk per day by the end of December, 1994 in the State.

Integrated Dairy Development Programme is being executed in all the districts of the State through 16 milk producers cooperative unions upto December, 1994. 84 new milk producers cooperative societies were constituted and 212 defunct societies were revived. By December, 1994 the total number of functional society were 2862. The total number of members increased to 361654. The average milk collection had been 3.15 lakh litres per day during 1994-95 (April, 1994 to December, 1994).

Dairy Federation is running 4 cattle feeding plants to provide nutritional feed to the animals. 40507 tonnes cattle feed was produced by these plants and 40505 tonnes were marketed during 1994-95(upto December, 1994).

5.7 **SHEEP HUSBANDRY**

Sheep husbandry is fast becoming one of the most important components of rural economy as it provides additional income and employment opportunities to a large segment of population specially the weaker sections of the society. In western and north-western parts of the State, it is the main occupation of the weaker sections to earn their livelihood. According to livestock Census of 1992 the sheep population was 121.68 lakhs (provisional) which is about 25 percent of the Country's sheep population. More than 2 lakh families are engaged in wool processing activities. State is producing about 170 lakhs Kg. of wool and more than 30 lakh heads of sheep and goat are utilised for meat purposes only. As preventive measures dosing against internal parasites spray and destroying against external parasites and vaccination programmes for sheep are being carried out on a large scale. Cross breeding and selective breeding programmes are also being implemented with a view to produce better quality of sheep producing fine wool.

5.8 **FISHERIES**

For fisheries development about 3.30 lakh hectares of surface water area is available in the State. Out of which 1.20 lakh hectares is in the form of large and medium reservoirs, 1.80 lakh hectares in the form of small tanks and 0.30 lakh hectares in the form of rivers/canals. The production of fish was 12220 tonnes upto December, 1994 against a target of 12,000 tonnes. 15 fish farmers development agencies are fuctioning through which each fish farmer is allotted 1 hectare of water area, Training is also imparted to such persons by these agencies. 6262 persons have been imparted training and 3827 hectare of water area has been allotted to them by the year 1993-94. During the year 1994-95 (upto December, 1994) 270 persons were given training and 150 hectare water area was allotted to them.

5.9 **FORESTRY**

Forests are one of the important natural resources so far as environmental protection and ecological balance are concerned.

In Rajasthan only 9 percent of the total geographical area of the State is classified as forest area against the recommended level of 33.33 percent under the National Forest Policy. Rajasthan is the second largest State in the Country, however, the scenerio of forest continues to be a cause of concern for the State.

With the view to accelerate the pace of tree plantation, afforestation and pasture development, works have been carried out under specific projects. National Social Forestry Project was implemented in 19 non-desert districts with the assistance of World Bank. Project of afforestation and pasture development in IGNP area is being implemented in Bikaner, Jaisalmer and Jodhpur districts with the assistance of O.E.C.F. (Japan). Aravali Afforestation Project is also being implemented with a O.E.C.F. (Japan) assistance in the in 10 districts. Afforestation and pasture development works have been also carried out under

State Plan, Centrally sponsored schemes and Area Development and Employment Generation Programmes. During the year 1994-95, plantation on Government land was done on 87206 hectares (upto January, 1995) and 336 lakhs seedlings have been distributed. For involving local people in managment of forests, 869 village level forest protection and management committees have been constituted in the State.

Under the World Food Programme, food units are distributed to labourers working in forestry works in the project area. One food unit constitutes 2 Kgs. of wheat, 200 gram pulses and 80 ml. of vegetable oil. A food unit is distributed to a labourer for 5 members of a family every day. In lieu of one food unit, Rs. 7.00 is deducted from the daily wage of the worker. During 1994-95, 20.86 lakh food units (upto December, 1994) were distributed.

The total forest area was 31753.57 sq.km. by the end of the year 1989-90 in the State. Out of this, 12272.71 sq.km. was reserved forest, 16116.97 Sq. Km was protected forest, 3363.89 Sq. Km was unclassified forest area.

5.10 **PRESERVATION OF WILD LIFE**

Rajasthan is very rich in wild fauna. Because of its size and geographical location, State provides a variety of habitats that support a number of rare and endangered animal and bird and species, viz. Great Indian Bustard, Tiger, Leopard, Chinkara, Sloth Bear, wolf, Floricans, Black Necked Storks, etc.

The State has 2 National parks, 23 sanctuaries and 33 closed areas. Till now the main thrust has been on the improvement and development of national parks, sanctuaries and closed areas. But in the Eighth Five Year Plan, preservation of wild life and its management has also been given importance.

*****

6. BASIC INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT

6.1 POWER

Rajasthan State Electricity Board is engaged in the investigation and execution of various Hydro Electric Projects and transmission and distribution of electricity. Kota Thermal Power Plant, Mahi Hydel Project, Beas, Chambal and Satpura are the principal sources of power supply to the State. In addition to these, Rajasthan Atomic Power Project, Singrauli, Rihand, Anta, Auraiya, Narora and Dadari Gas, Uchahar Thermal and Tanakpur Projects in Central Sector are also sharing power with the State. By the end of 1993-94, the installed capacity in the State was 2985 M.W. During the year 1994-95 (upto February, 1995) 3.80 M.W. installed capacity was added. Due to outage of two units at Kota Thermal Power Station, there has been reduced generation at the station and therefore, efforts were made to purchase power from adjoining system and hence the purchases are more. The power generation is likely to be 6914 million units during 1994-95 as against 7888 million units during 1993-94.

Efforts were made to augment generation capacity. The pattern of generation, purchase and consumption of electricity in the State during three years is depicted in the following table:

(In million units)

Item	1992-93	1993-94	1994-95 (Provisional)
1.	2.	3.	4.
1. Generation (Net)	7961.650	7888.344	6913.880
2. Purchase	6704.853	7486.512	8415.270
Total(1+2)	14666.503	15374.856	15329.150
3. Consumption:			
(a) To other State/ System	501.548	272.636	500.000
(b) To Common Pool Consumer & Power	138.444	138.408	140.000
(c) Consumers of Rajasthan	10528.862	11091.430	11533.380
(i) Domestic	1345.647	1545.331	1495.880
(ii) Non-Domestic	483.166	531.412	530.540

1.	2.	3.	4.
(iii) Industrial	4361.465	4378.917	4861.320
(iv) Agriculture	3361.306	3653.031	3596.110
(v) Public Water Work	450.511	465.695	510.930
(vi) Street Lighting	48.261	54.322	50.750
(vii) Others	478.506	462.722	487.850

Still the State continued to face shortage of power and consequently restrictions / cuts had to be imposed on industries / agriculture depending upon energy availability from time to time. Power was made available for agricultural operations on an average of 8 hours a day.

30004 villages (80.02 percent) were electrified by 1993-94. In addition to these, 650 villages were electrified during 1994-95 (upto February, 1995). Thus total 30654 villages have been electrified so far. 24128 wells have been energised during 1994-95 (upto February, 1995) making a total of 4.78 lakh wells energised so far.

Power consumption is likely to be 11533.380 million units during 1994-95 as against 11091.430 million units during the last year. Thus, the per capita power consumption is likely to be 263 units during 1994-95 as against 236 units in the previous year.

6.2 NON-CONVENTIONAL SOURCES OF ENERGY - REDA

The State has good potential for production of energy from solar and wind power. Rajasthan has vast tracts of unfertile land where solar insulation is very high. In these desert areas, generation of electricity solar energy is feasible. Considerable work has been done on village electrification through Solar Power Packs besides installation of Solar Pumps, community T.V. sets and strengthening of SPV lights. A proposal for setting up of 35 MW Solar Thermal Power Project at Mathania has been posed to the World Bank and is being processed on priority.

Wind energy in desert areas is very high during summer months but has not been found economically viable on average velocity basis for the whole year. Wind Monitoring Stations have now been set up in passes of Aravali range, where because of funelling action, winds of high velocity, on a yearly basis, are expected to be encountered. Projects for setting up of wind mills for lifting of water, are being implemented by REDA during 1994-95.

6.3 TRANSPORT AND COMMUNICATION - ROADS

Rajasthan is one of the few States in India which is far below the National average in respect of road length. The road length per 100 Sq. Km. is likely to be 32.5 Km. by the end of 1994-95, it was 32.0 Km by the end 1993-94, which was much below the National average of 62.0 Km per 100 Sq Kms. Total road length administered by Public Works Department is likely to increase to 64588 Kms. during 1994-95 from 63078 Km in 1993-94. Roads are the harbinger of the development of an area, hence due importance has been attached to road construction since the inception of Five Year Plan era. Categorywise details of the road length during last three years are given below :

(in Km.)

Roads	1992-93			1993-94			1994-95 (likely)		
	Surfaced	Unsur-faced	Total	Surfaced	Unsur-faced	Total	Surfaced	Unsur-faced	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. National Highways	2846	-	2846	2846	-	2846	2846	-	2846
2. State Highways	7111	40	7151	8647	73	8720	8657	63	8720
3. Major District Roads	3487	151	3638	3051	161	3212	3091	121	3212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Other District Roads	12960	2107	15067	12412	1982	14394	13317	1882	15194
5. Village Roads	22395	8184	30579	23338	8329	31667	24198	8179	32377
6. Border Roads	2239	-	2239	2239	-	2239	2239	-	2239
Total	51038	10482	61520	52533	10545	63078	54343	10245	64588

To give more emphasis to the net work of roads, the State has recently announced the "Policy on Road Development in Rajasthan". Its main features are :-

(i) To connect all the villages of population 1000 and above (as per 1971 Population) by BT roads during Eighth Plan period.

(ii) To connect all villages of population 1000 and above (as per 1981 and 1991 Population) upto the end of Ninth Five Year Plan.

(iii) To connect all Panchayat H.Qrs. with BT roads up to the end of Ninth Five Year Plan irrespective of the population.

(iv) To connect all the villages of population 750 and above of tribal and desert areas by BT. road by the end of Ninth Five Year Plan.

(v) To construct by passes around major urban centres.

(vi) To widen SHW and District Roads.

(vii) To construct inter-state roads and missing links and CD works on State Highways.

To achieve these targets resources are to be mobilised from various schemes like Jawahar Rojgar

Yojna, Employment Assurance scheme, 30 Zila 30 Kam. In addition, institutional financing will be taken and private investors will be invited for construction of bridges, tunnels and by-passes. The money so invested will be recovered through levying the toll tax. Under the World Bank assisted programme, upgradation and widening works of 4 State Highways is in progress.

- ROAD TRANSPORT

The total number of motor vehicles on road was 14.09 lacs in 1993 which has gone to 15.47 lacs in 1994 showing an increase of 9.79 percent. Details of various categories of vehicles registered with State Transport Department for last 3 years i.e. 1992 to 1994 are given below :

Type of Vehicles	Cummulative Number in the Year			% increase in 1994 over 1993
	1992	1993	1994	
1	2	3	4	5
1. Motorised Rickshaws	90	90	90	-
2. Auto/motor cycles & Scooters	837840	920437	1020054	10.82
3. Auto Rickshaws	19504	20982	23168	10.42
4. Tempos :				
(i) For carrying Goods	936	1121	1371	22.30
(ii) For carrying Passengers	3679	3947	4182	5.95
5. Car & Station Wagons	59992	63777	68881	8.00
6. Jeeps	45783	50512	55822	10.51
7. Tractors	166401	182156	197386	8.36

1	2	3	4	5
8. Trailors	40878	42208	42701	1.17
9. Taxies	10717	11446	12171	6.33
10. Buses & Mini Buses	26601	28450	30870	8.51
11. Trucks & other Goods carriers	77045	81331	87232	7.26
12. Miscellaneous	2567	2604	2667	2.42
Total	1292033	1409061	1546595	9.76

During 1994-95 (April to December, 1994), permanant permits for 9122 luggage carriages, 1325 stage carriages and 2969 contract carriages were issued. 87 new routes covering 6167 Kms were opened. Besides, 32 smoke meters and 22 gas analysers were in use for pollution control in December, 1994.

*****

7. SOCIAL INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT

7.1 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Rajasthan is educationally backward state. The situation of female literacy is particularly alarming. A wide gap exists between the rate of literacy in urban and rural areas and among male and female. The literacy level of 38.55 percent (1991) in the state is lowest among the states except Bihar. Female literecy in Rajasthan is 20.44 percent only as compared to all India female literacy of 39.29 percent.

Continuous efforts are being made for development of education in the state. A number of measures have been taken up to encourage women education. These include free general education upto college level, free professional and technical education and incentives for girl students and to discourage dropouts in education.

Universalisation of elementary education for all children upto 14 years of age is the main target. In view of the importance attached to it, elementary education is covered under Minimum Needs Programme and 20-Point Programme.

The details of the government and non-government schools functioning in the State during 1994-95 are furnished below:-

(Number)

Institutions	Government	Non-Government	Total
1	2	3	4
1. Primary schools	31397	3213	34610
2. Upper primary schools	9152	1919	11071
3. Secondary schools	2854	360	3214
4. Senior secondary schools	967	290	1257

For increasing the enrolment and retaining the students at primary education level, "Free

Book Distribution Scheme" for girls in classes I to VIII and for boys in classes I to V has been introduced first time in the State during 1994-95. Under this scheme, books worth Rs.10.22 crores have been distributed and 45.68 lakh students (including 15.36 lakh girls) benefitted.

For achieving the target of universalisation of primary education, LOK JUMBISH Project is being implemented in 25 blocks of the State with the assistance of SIDA.

The "Shiksha Karmi" scheme is being implemented with SIDA assistance. Under this scheme, the rural educater youth, both male and female, are imparted training and employed as teachers in their own village. These "Shiksha Karmies" run the schools in the day time and for those children who are busy elsewhere in the day earning livelihood, run night shifts. An autonomous body "Shiksha Karmi Board" has been costituted for effective implementation of this scheme.

At present, 1141 schools and 2452 night shift schools in 26 districts are covered under the "Shiksha Karmi" Scheme, where 2751 Shiksha Karmies are employed, benefitting 84162 children through regular day time schools and 24528 through night shift schools.

Keeping in view the objective of "Education for all by 2000" and the total literacy, the outlay for education has been substantially stepped up in the current year. An outlay of Rs. 223.45 crores has been made for education in the year 1994-95, as copared to Rs. 125 crores in 1993-94. Thus, the outlay for elementary education has been increased by 119 percent and that for total literacy by 105 percent. Under Centrally Sponsored Scheme, an amount of Rs. 43.66 crores would be made available by the Government of India during 1994-95.

For encouraging the girls education, it has been decided to start "SARASWATI YOJNA" through the educated women in the rural area of the State.

Opening of 100 Sarswati Shalas in five districts is envisaged under this programme during 1994-95.

Under adult education, various schemes are being executed in the state. The total literacy compaign started in the year 1990-91, continued during 1994-95. Ajmer and Dungarpur districts have already been declared as total literate districts. Total litrecy programme is being executed in Bharatpur, Sikar, Pali, Tonk, Baran, Udaipur, Alwar, Rajsamand, Jhunjhunu, Bundi, Bhilwara, Banswara and Chittorgarh.

For the children in the age group of 6-14 years, these who are not in a position to go formal schools due to their social and economic circumstances, 10600 nonformal education centres are functioning to provide elementry education in the State. In addition, 3200 nonformal education centres have been sanctioned during the year upto Dec.1994.

For imparting higher education, 71 Government colleges including 37 post graduate colleges have been functioning in the State. Besides, 65 aided colleges and 37 un-aided colleges are also imparting higher education. During the year 1994-95, 2 girls degree colleges (Bharatpur and Ganganagar) have been upgraded to post graduate colleges. Further, 14 new subjects were introduced in the Government colleges.

The Directorate of Technical Education has been providing technical education through industrial training institutes and polytechnics in the State.

7.2 **MEDICAL & HEALTH**

Main objective of the health care programme are to control and eradicate communicable and other deseases and to provide curative and preventive services to the people. Details relating to allopathic medical institutions functioning during 1994-95 (Dec. 1994) are as follows :-

Institutions	Number
1. Hospitals	218
2. Dispensaries	273
3. Primary Health Centres	1507
Community Health Centres	246
4. Maternity and Child welfare Centres	118
5. Sub-Centres	8000
6. Inpatient Bed	35663

For every one lakh population (1991 Census) 81 beds are available in the State in 1994-95 (Dec. 1994).

Under "Malaria Eradication Programme" against a target of 4400599 blood collection slides, 4525430 blood slides were collected and examined up to Dec. 1994.

In order to curb the Infant Mortality rate and to provide safeguard against serious deseases, an intensive "Child Immunization Programme" has been launched in the State. "The Child survival and safe Motherhood Programme" started in 1992-93 continues during the year 1994-95.

Under National "AIDS Control Programme" AIDS cell has been established in five medical colleges of the State, "Blood Examination Centres" have been established.

The National Programme for Control of Blindness which was started in 1977-78 has been further strengthened by the World Bank assisted Cataract Blindness Control Project commencing from 1994-95 for a period of 7 years with an allocation of Rs. 65.24 crores for the project period.

Other medical institutions 3495 Ayurvedic, 108 Homeopathic, 78 Unani and 4 Naturopathy Hospitals / Dispensaries are functioning in the State (Dec. 1994). Besides a mobile surgical unit having 200 beds is also functioning under the Ayurvedic Department with its headquarters at Ajmer.

There are 4 Ayurvedic Rasayan-Shalas functioning at Ajmer, Jodhpur, Bharatpur and Udaipur where medicines are prepared and supplied to Ayurved, Unani and Naturopathy Hospitals / Dispensaries.

7.3 FAMILY WELFARE

In order to achieve the goal of small family, an intensive family welfare programme has been launched through out the State. Against an target of 2.50 lakh sterilization during 1994-95, 1.18 lakh sterilization operations were performed upto Dec. 1994. Under "The Family Welfare Programme" Social Security Net Scheme" launched by the Government of India in 1992-93 is being implemented in 23 districts of the State. Besides a new "India Population Project-IX " has also been launched in the State during 1994-95 with the assistance from World Bank for a period of 7 years with an allocation of Rs. 108.00 crores to improve the health and family welfare services in the State with special thrust on Western districts.

7.4 WATER SUPPLY

The problem of availability of safe drinking water in the State is very complex on account of geographical diversities, and limited availability of both ground water and surface water. The State Government has assigned a very high priority to the programme of providing potable drinking water to the people.

During the Year 1994-95, a budget of Rs. 203.24 crores was made available under State plan for drinking water supply in the State. Out of which Rs. 130.59 crores were earmarked for urban areas, and Rs.72.65 crores to rural areas.

Concerted efforts are being made to overcome drinking water problem in rural areas of the State. The number of villages covered under drinking water facilities through various water supply sources viz, tubewell, hand pump etc. and conventional water sources & water supply schemes up to December, 1994 is 36629.

Drinking water facilities would be provided in additional 1450 villages, 500 dhanies and 1000 SC / ST basties during 1994-95.

7.5 HOUSING

There has been a large expansion in the urban population of cities and towns. There have also been conscientious efforts to augment infrastuctual facilities like housing. To solve the housing problem with the object to provide the better houses at cheaper rates for weaker sections of population, Rajasthan Housing Board was set up on 24th February 1970.

Details of the activities of Housing Board are given in the following table:-

Items	Unit	Achievements
1. Applicants registered in 63 Cities/ Towns	No.	2,07,318
2. Construction activities started upto Dec.94	No.	1,37,466
3. Houses Completed	No.	1,29,914
4. Allotment of complete Houses	No.	1,25,244
5. Possession of Houses	No.	1,07,829
6. Physical Targets for 1994-95 (Houses)	No.	11,000
7. Houses under construction (up to Dec.94)	No.	9,698

New techniques of construction viz use of blocks of concrete cement, precasted lin-tal and roof ceiling have been adopted by Housing Board. "Awas Vikas Sansthan" has been constituted by Housing Board. This Sansthan is using the latest techniques of Turnel Shuttering. This has resulted in reduced construction cost / time. A scheme of allotment of skeleton houses has also been initiated. Campaigns were also launched to make the process of registration of houses simpler and effective.

7.6 WELFARE OF BACKWARD CLASSES AND SOCIAL WELFARE

Social Welfare Department of the State is implementing various programmes for socio-economic and educational development of the Scheduled castes, Scheduled tribes and other backward classes. In addition, programmes are also being implemented to improve the quality of life and cater to the special needs of vulnerable sections like children, women and handicapped etc.

-WELFARE OF SCHEDULED CASTES

Rajasthan S.C. Development Co-operative Corporation was established on 28th March, 1980 to uplift economic status of S.C. population residing below poverty line. Now it has been reorganised as Rajasthan State Scheduled Caste / Tribe Finance & Development Cooperative Corporation Ltd. Till now 10,47,710, persons have been benefited since its formation.

-WELFARE OF SCHEDULED TRIBES

Article 46 of the Constitution of India has entrusted the Government with the responsibility of promoting the economic and educational interests of SCs & STs. The basic outline were framed in the First Five Year Plan for the development of the tribal area and the economic upliftment of the tribal families. The basic infrastructure of tribal populated areas were framed as area based programme, consequently during the year 1974-75 tribal sub-plan was formulated.

Among tribals, mainly the Bhils, Meena, Garasiya, Damor and Kathodies are residing in Rajasthan. The declared sub-plan area consists of 23 panchayat samities of district Banswara, Dungarpur, Chittorgarh, Udaipur and Sirohi. As per Census of 1991, the total population of tribals in Rajasthan is 54.75 lakhs, out of which 24.01 lakhs are residing in tribal sub-plan area.

Various developmental plans pertaining socio-economic upliftment of tribals are being implemented by T.A.D. Department for the economic and social upliftment.

A total provision of Rs. 33312.98 lakhs has been kept in 1994-95, for the development and welfare of scheduled tribes. Out of total provision, Rs. 21244.17 lakhs have been provided under State plan, Rs. 1336.30 lakhs under special central assistance, Rs. 1919.30 under institutional finance and Rs. 8813.21 lakhs under centrally sponsored schemes.

- **WELFARE OF WOMEN AND CHILDREN**

There are 178 Bal Vikas Schemes. Out of these, 139 are in rural areas, 11 are in urban areas and 28 are in tribal areas. Out of 237 Panchayat Samities in the State, these services have been expanded in 167 Panchayat Samities of 31 districts. In 1994-95 under Poshahar Programme, 14.80 lakh women & children are to be benefited.

Various scheme are being implemented for the welfare of women like Mahila Mandal, Kishore Balika Scheme and DWCRA etc.

8. RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

The main objectives of the rural development programmes are (i) more employment, (ii) more equitable distribution of income and eradication of rural poverty among rural masses, and (iii) more investment in rural areas to enable them to lead better social and economic life. To achieve these objectives, State and Centrally sponsored Schemes / Programmes remained under implementation during 1994-95.

IRDP basically aims at generating additional employment opportunities and to raise the income levels of the identified target groups. During the year 1994-95, 0.94 lakh families were benefited upto February, 1995 as against a target of 1.08 lakh families. Under TRYSEM, which is also a part of IRDP, provides training to un-employed rural youths for self and wage employment under which 6865 youths were trained upto February, 1995 as against a target of 9000 youths. 2093 trained youths were engaged in self employment wage employment.

The primary objective of JRY, is to generate additional gainful employment opportunities for unemployed and under-employed persons both men and women in rural areas. During the year 1994-95, 306.27 lakh mandays employment was generated up to February, 1995 against a target of 385.21 lakh mandays employment. Under Indira Awas Yojana, 22258 houses have been completed and 2527 wells have been constructed upto February, 1995 under Jeevan Dhara Yojana.

Apna Gaon Apna Kaam scheme was taken up from 1st January, 1991 for creating additional employment opportunities through construction of public utility assets in the rural areas. In 1994-95 an amount of Rs.14.28 crores has been spent upto February, 1995. 1272 works of basic public utilities were completed upto February, 1995, and 1572 works are under progress. As per revised funding pattern, 50 percent expenditure would be

through public contribution/ panchayats (minimum public contribution being 30 percent) in the form of labour and material, and besides 50 percent being State matching share from JRY/other plan funds.

Desert Development Programme (100 percent Centrally Sponsored) covers 85 blocks of 11 desert districts of State. Under this scheme, Rs. 64.50 crores have been kept for the year 1994-95. A sum of Rs. 11.33 crores have been kept for implementation of Drought Prone Area Programme under State.

Under bio-gas a sum of Rs. 1.72 crores have been spent and 3947 plants have been established by the end of February, 1995 as against a target of 5000 plants.

To give due importance to the felt needs and aspirations of the local people, it has become necessary that some of the plan funds should be transferred to the districts under the scheme known as untied funds. 489 works have been completed upto February, 1995, under the scheme.

With a view to best utilization of available local resources by the district itself, the scheme of Tees Zile Tees Kaam has been launched in the State in the year 1991-92. Investment in the district is made keeping in veiw the scope of development and available resources 619 works have been completed by the end of February, 1995.

Under Mewat Development a sum of Rs. 2.00 crores have been kept for development of meo area in the districts of Alwar & Bharatpur. Highest priority has been given to the construction of roads in the Mewat area.

With a view to provide employment to the poor sections of the community in rural areas an employment assurance scheme has been announced for rural poor. A sum of Rs 122.00 crores has been kept for the year 1994-95, Rs. 82.60 crores have been spent by February, 1995. This scheme is being implemented in 172 panchayat samities.

To reduce poverty and development impetus introduced in the past, an approach paper of the comprehensive project have been prepared and sanction has been received from World Bank. Under this project districts would be provided economic assistance of Rs. 15 to 20 crores per year for a period of 4 to 5 years. First of all, Rajsamand district has been selected on pilot basis. Similarly for the development of Luni basin project of Rs. 200 crores has been designed and an approach paper has been sent to F.W. German Mission for financial assistance. For development of decoit affected area (DANG), special scheme has been prepared and sent to SIDA for financial assistance. A project for development of Saharia Tribal Belt in Baran district has been sent to Govt. of Indian and financial sanctions have been received.

An outlay of Rs. 1111 lakhs under Rural Development and Panchayats and 468 lakh under Rural housing has been provided for the year 1994-95.

Under the scheme of free allotment of plots to the rural poors, 29021 plots have been allotted upto December, 1994.

*****

9. OTHER PROGRAMMES

9.1 TWENTY POINT PROGRAMME

The Twenty Point Programme, a blue print for economic and social transformation of our country and for frontal attack on poverty, has provided the momentum for development. This programme has been dovetailed into a plan of overall development while pinpointing areas of special thrust. It envisages goals of higher productivity, efficiency and reduction in disparities.

The contents of the programme consist of the programmes of poverty alleviation, improvement of quality of life, environment and ecology and insulating weaker section against erosion of income.

Rajasthan has evolved a strategy of effective implementation of the multi-dimensional programme that consists of allocation of plan funds, quantification of physical targets and assignment of responsibilities at various levels. A monitoring system has been devised for building up of a reporting system from the grass roots to the top.

There are in all 119 items under Twenty Point Programme. Out of these, 65 items have been identified for physical targets and the rest 54 items are being monitored on evaluatory basis.

9.2 FAMINE & RELIEF

During monsoon 1993-94, there was long dry interval in the month of August 1993, which adversely affected the crops. As per Girdawari reports, 22586 villages of 25 districts were declared drought affected on 31.1.94. State Govt. started Relief works from 1st Feb., '94 to 15th July 1994. Relief works were sanctioned with a view that the works should be of permanent nature and previous incomplete works should be completed on priority basis.

An employment was provided to 7.93 lakh labourers under famine and relief works by the end of June 94. A sum of Rs. 160.74 crores were allotted to the District Collectors for relief works. During summer Rs. 126.26 lakhs were allotted to the district collectors to provide drinking water in affected villages.

Under the gratuitous relief scheme Rs. 140.28 lakh were alloted and relief was given to 28816 persons.

An amount of Rs. 93.41 lakh were spent for purchasing of medicines for human health and Rs. 53 lakh for animals welfare. Under the flood control scheme Rs. 92.90 lakh were provided for releif to affected persons. Rs. 2621.31 lakhs were also provided to various institutions and departments for flood restoration works of 1993.

9.3 **SMALL SAVINGS**

Role of small savings has become very important in State's economy since 75 percent of the total collection can be taken back in the form of long term loans from the Government of India. Hence Small Savings contributes substantially to the financial resources of the State. The State Government has declared incentives to create atmosphere for small savings which has resulted into an appreciable increase in small savings collections. The savings of households, individuals, corporates and the institutions are channelised into investments for the economic development of the State.

A target of Rs. 460 crores has been fixed for the Year 1994-95, out of which Rs.402 crores have been collected till December, 1994 which is 87 percent of the targets. Looking to the present trend it is expected to achieve 120 percent of its annual targets i.e. Rs. 560 crores of net deposits.

As against the targets of Rs. 350 crores in B.E. 1994-95, the State Government, has already availed Central Government loans of Rs. 450.31 crores against net small saving collections upto February, 1995.

Collection position under various small savings schemes during 1993-94 and 1994-95 is given in the following table:

(Rs. in lakhs)

Securities	1993-94 1st April to December,93		1994-95 1st April to December,94	
	Gross	Net	Gross	Net
1	2	3	4	5
1.National savings Certificates VIII issue	3028.88	3017.98	3759.18	3718.00
2.Post Office Saving Accounts	12849.68	-2292.56	15097.22	-671.23
3.Cumulative Time Deposits.	24.01	-79.26	19.39	-67.72
4.Recurring Deposits	13338.62	6145.45	16812.43	7532.62
5.Post Office Time Deposits	6675.65	2807.31	6594.65	863.66
6.Public Provident fund.	1528.52	912.06	2086.44	1400.19
7.Indira Vikas Patra.	9149.76	150.23	9552.06	3723.36
8.Monthly Income Scheme.	4136.22	3142.38	6763.96	5426.89
9.National Savings	328.61	-1829.68	410.90	-2579.36
10.Kisan Vikas Patra	20063.88	18701.26	28216.22	24205.12
11.Old Certificates.	-	-4766.87	-	3192.28
TOTAL	71123.83	25908.30	89312.45	40359.25

It is revealed from the above table that Post Office Savings Accounts, Recurring Deposits and Kisan Vikas Patra and Indira Vikas Patra continued to be the most popular schemes. These four schemes accounted for 77.90 percent of the total gross collection in 1993-94 and 78.02 percent in 1994-95 (upto December, 1994).

*****

10. ECONOMIC AND FINANCIAL REFORMS INITIATED IN THE STATE

The process of Economic Reforms has been initiated in the State and the following steps have been taken so far :

1. INDUSTRY AND STATE ENTERPRISES

(i) The entry of private sector in establishment and maintenance of industrial areas has been permitted.

(ii) Telecom operators are being encouraged to set up systems in selected areas within the over all policy framework of Government of India.

(iii) Private participation in construction and maintenance of roads has been allowed. Alongwith this, private parties would also be allowed to collect toll tax from roads and bridges constructed by them.

(iv) Entry of private sector is being encouraged in Tourism, Hotels and Health Care Sectors.

(v) Amendments have been made in the Laws / Rules relating to conversion and allotment of land for industrial purposes. This has greatly facilitated the conversion of land for industry.

(vi) In the area of pollution control the procedure for issue of No Objection certificate and consent by the State Pollution Control Board has been simplified. 155 types of small scale industries have been exempted from the requirement of such NOCs / Consents. Powers for grant of NOCs / Consents have been decentralised at the field level.

(vii) The system of separate inspection under industrial labour laws has been done

away with. Instead, there will be a common inspection of industry in accordance with the check list prepared for the purpose.

(viii) The number of inspections under labour laws have been reduced to 5 percent of the establishments in the small scale and tiny sectors and 10 percent in other sectors selected on random basis.

(ix) The SSI units will be required to send only one return and display one common notice covering all labour laws.

(x) The State Government have decided to reduce the list of industries to be inspected under the Factories Act from 15 items to just 3 items. As a result of this 5000 units out of the total of 12600 factories of the State would get excluded from various provisions of the Act.

(xi) An Empowered Committee has been set up under the chairmanship of Chief Secretary with powers to take final decisions in regard to any matter connected with a particular input / clearance.

(xii) Nodal officers have been designated in all concerned departments / agencies for speedy clearances.

(xiii) Specific time frames have been prescribed for various clearances / inputs required by the industries.

In the case of State Owned Enterprises, following reforms have been initiated :

(i) Improving efficiency and productivity of those State Owned Enterprises which are viable and critical for State's development.

(ii) Privatising and closing down enterprises in which either the State Government does not have a critical role to play and which cannot be rehabilitated with the State Government efforts.

(iii) Restructuring of some of the units to make them more viable.

(iv) State Renewal Fund on the pattern of National Renewal Fund is being set up with a corpus of Rs. 5 crores to facilitate industrial restructuring.

(v) Steps have been taken to shed excess staff through Golden Hand Shake under the Voluntary Retirement Scheme.

(vi) The State Enterprises are being encouraged to enter into Memorandum of Understanding with the State Government so that they enjoy complete functional autonomy and are accountable to State Government for the achievement of specified objectives.

2. **TAX REFORMS**

(A) **SALES TAX**

(i) The existing Rajasthan Sales Tax Act has been completed re-written and draft of the new Act has been presented before the State Assembly. In the new draft Act various provisions / procedures have been greatly simplified.

(ii) Reduction in the number of tax slabs from 14 to 10.

(iii) Introduction of compounded levy (green channel system) of tax payment. It has already been made applicable in the case of brick klins, mini cement plants, sarafa and restaurants.

(iv) Reduction / exemption in tax on a large number of inputs used as raw materials for manufacturing.

(v) Introduction of self-assessment scheme for dealers having a tax liability of Rs. 10,000/- per year. Out of a total number of about 1.63 lakh registered dealers in the State, about 1.20 lakh dealers have been covered under this scheme.

(vi) Reduction in the number of checkposts in the State from 152 to 72. This is aimed at ensuring freer movement of goods.

(vii) Norms / guidelines fixed for survey / inspection of dealers aimed at reducing discretion at the level of individuals officers and avoiding harassment to the dealers.

(viii) Computerisation of records of dealers and challans of sales tax at Jaipur.

(ix) Single window for registration forms made operational at Jaipur.

(x) Amnesty scheme introduced for dealers aimed at reducing litigation in the courts.

(B) **REGISTRATION AND STAMPS**

(i) A flat rate of 10 percent stamp duty has been fixed in place of 9 rates prevailing earlier.

(ii) Rationalisation in the rates of registration fee.

(iii) Reduced rate of 6 percent stamp duty fixed for houses and flats constructed by Rajasthan Housing Board, Jaipur Development Authority, Urban Improvement Trusts and the State Government.

(C) **LAND AND BUILDING TAX**

(i) The exemption limit has been raised from Rs. 1 lakh to Rs. 2 lakhs.

(ii) The Self-Assessment Scheme and Valuation system has been rationalised and simplified. Self-Assessment Scheme has been extended upto Rs. 10.00 lakhs value of land and building. In the normal cases valuation by the Registered Approved Valuer of the Department would be accepted by the Department for assessment purposes. Inspectors of the Department have been debarred from conducting assessment in such cases.

3. **POWER SECTOR** Power Sector

(i) The State Government have decided to go in a big way for generation of power through the aegis of private sectors by following the International Competitive Bidding route.

(ii) The procedure for release of connections to agriculture has been greatly simplified.

(iii) For better interaction with public and consumers, districtwise committees have been constituted under the chairmanship of the District Collectors. Besides, Divsional Level Committees have also been set up under the chairmanship of Chairman, RSEB for this purpose.

(iv) Decision has also been taken to encourage industrial units to set up captive power plants. In the interest of rapid industrial growth of the State, the State Electricity Board would accord over-riding priority in release of HT industrial connections.

(v) In order to improve the efficiency and viability of the State Electricity Board, a number of measures have been taken including increase in tariff, gradual reduction in pole subsidy for agriculture connections etc.

4. **OTHERS**

Apart from the above, reforms have also been initiated in other areas of the State Government. The process of reforms would be carried on further.

The reforms have been undertaken with a human face. In certain social sectors like Health, Education, Drinking Water, Rural roads, Nutrition needs of women / children, the State would continue to play a greater role to provide the safety net to the vulnerable sections of the society.

*****